स्वतंत्रता आन्दोलन में गोरखपुर का योगदान
(१८८०—१९४७)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिये प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

शोधकर्त्री
कु० राजश्री तिवारी

निर्देशक
प्रो० सी० पी० झा

मध्यकालीन एवम् आधुनिक इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
१९८८

प्राक्कथन

किसी भी क्रान्ति या आन्दोलन की सफलता के लिये जन साधारण का समर्थन अनिवार्य है। किसी समुदाय, वर्ग या व्यक्ति विशेष का प्रयास देश को स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। गांधी जी के स्वतंत्र भारत के स्वप्न को हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से ही मूर्त रूप मिला। देश के हर भाग ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर प्रदेश का ऐसा ही एक जिला गोरखपुर था। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में वह बड़े से बड़ा बलिदान करने में पीछे नहीं रहा। 1857 के विद्रोह को राजाओं, ताल्लुकेदारों व जमींदारों के समर्थन के साथ जनता का भी सहयोग मिला था।

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास पर कई शोध ग्रंथों की रचना हुयी है। स्वतंत्रता के प्रयासों की अधिकता के कारण उपलब्ध ग्रंथों में घटनाओं का विस्तृत वर्णन नहीं हो सका है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में गोरखपुर के योगदान पर प्रामाणिक ग्रंथ के अभाव तथा उन अनाम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के उद्देश्य से - जिन्हें राष्ट्रीय ख्याति नहीं मिल सकी परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में उनका बलिदान किसी भी दृष्टि से कम सराहनीय व प्रशंसनीय नहीं था - मेरी इस विषय पर काम करने की अभिरूचि उत्पन्न हुयी।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। चूंकि 1920-47 तक कांग्रेस ही देश की एकमात्र सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था थी जिसके संगठन, नेतृत्व व विस्तृत कार्यक्रम का कोई विशेष प्रान्त नहीं था, उसी के कार्यक्रम प्रान्तों में लागू किये जाते थे; इसी कारण कई

स्थानों पर सम्पूर्ण राष्ट्र का आधार-भूत पूर्वी तत्वों का उल्लेख आवश्यक हो गया है ।

मैंने स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी देने का प्रयास किया है तथा सभी सम्भव साधनों का उपयोग किया गया है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय ; पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद ; राजकीय अभिलेखागार - लखनऊ, सचिवालय अभिलेखागार - लखनऊ, विधान सभा पुस्तकालय - लखनऊ ; राजकीय जिला पुस्तकालय, गोरखपुर में संग्रहीत अपने विषय से सम्बन्धित अभिलेखों से मैंने उपयुक्त सामग्री एकत्र की है । गुप्तचर विभाग की गोपनीयता बनाये रखने के लिये 'गुप्तचर विभाग के अभिलेख' लिखा गया है ।

प्रो० राधेश्याम, अध्यक्ष मध्य० व आधुनिक इतिहास विभाग का मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने में यथेष्ट सहायता दी । श्री चंद्र प्रकाश झा, प्राध्यापक मध्य० व आधुनिक इतिहास विभाग का मैं विशेष आभारी हूँ जिनके निर्देशन व प्रेरणा के बिना यह कार्य असम्भव था । अपना बहुमूल्य समय दे कर उन्होंने कार्य शीघ्र सम्पन्न करवाया ।

Rajshri Tiwari

राजश्री तिवारी

मध्य कालीन एवं आधुनिक

इतिहास विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

दिनांक :

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

:=:=:=:=:=:

भूमिका

उत्तर प्रदेश जिसे पहले पश्चिमोत्तर प्रान्त और फिर आगरा और अवध का संयुक्त प्रान्त कहा जाता था, की चर्चा करते हुए बंगाल सिविल सर्विस के अधिकारी श्री क्रुक्स ने 1897 में लिखा - "हमारे साम्राज्य में (भारतीय साम्राज्य में) जितने भी प्रान्त हैं, उनमें कोई भी इससे ज्यादा आकर्षक नहीं है। यह वस्तुतः भारत का एक उद्यान है"।[1] इसकी राजनीतिक स्थिति ने न केवल राज्य का बल्कि सारे देश के इतिहास का निर्माण किया। चाहे तुर्क हों, मुगल हों या अंग्रेज, जिस किसी ने इस हृदय भूमि पर कब्जा किया वही अन्ततोगत्वा सारे देश का स्वामी हो गया।[2]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासन की पहली शताब्दी दुःख व असन्तोष की थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश मूलतः बंगाल महाप्रान्त का एक भाग था। प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम के अन्तर्गत बंगाल महाप्रान्त का विभाजन कर के पृथक आगरा प्रान्त के सृजन का विधान बनाया गया। किन्तु विधान कार्यान्वित न कर के आगरा प्रान्त का नवीन नामकरण पश्चिमोत्तर प्रदेश किया गया। इसका प्रशासन 1836 में उपराज्यपाल के अधीन सौंप दिया गया।

---

1. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद -'हमारे देश के राज्य - उत्तर प्रदेश', प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। पृ० - 1

2. वही ; पृ० 13,

1877 में अवध जो कि एक पृथक प्रदेश था, इसमें शामिल कर लिया गया 1902 में इस प्रदेश को "संयुक्त प्रान्त आगरा एवम् अवध का नाम दिया गया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम परिवर्तित कर के उत्तर प्रदेश कर दिया गया ।[3]

आज देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाने वाले आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है ।[4] भारत का रेखोद्दीप्त भू-भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश है । यहां की अदम्य राजनीतिक चेतना, गौरवशाली सांस्कृतिक व साहित्यिक परम्परा के बीच जीवन्त पत्रकारिता पनपी है ।[5] इसी क्षेत्र में भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या स्थित है । महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ (वाराणसी) से प्रारम्भ किया था तथा कुशीनगर (देवरिया) में निर्वाण प्राप्त किया । महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु का बस्ती जनपद में पिपरहवा नामक स्थान के आस-पास स्थित होने का संकेत पुरातत्व वेत्ताओं ने दिया है । कुसीनारा (कुशीनगर, देवरिया) और पावा (फाजिलनगर, देवरिया) के शक्तिशाली मल्ल गणतंत्र, बुद्धकालीन भारत के गणतंत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे । वाराणसी प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती रही है । आदि शंकराचार्य ने भी वाराणसी की यात्रा की थी । वाराणसी का पंच गंगा घाट गुरु रामानन्द का निवास था । कबीर जैसे महान रूढ़ि भंजक

---

3. गहलोत, बी०एल०, "पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास ।" शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय । पृ० 1-2
4. त्रिपाठी, आमोद नाथ, "पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन जीवन में बाबा राघवदास का योगदान ।" शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ० - 1
5. तिवारी, डा० अर्जुन, "स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता", पूर्वी उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में । पृ० - 14,

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत मात्र गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और मिर्जापुर जिले को स्वीकार करते हैं।[9] गंगा, घाघरा, राप्ती, गण्डक आदि नदियों से अभिसिंचित उर्वर भूमि वाले इस क्षेत्र की आबादी अत्यन्त घनी है तथा इसकी जनता की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है।[10]

गोरखपुर जिला संयुक्त प्रान्त के पूर्वोत्तर कोने में है। यह 26°745 तथा 27°2915 उत्तरी अक्षांश तथा 83°8'0 और 85°3230 पूर्वी अक्षांश के बीच में स्थित है। 1889 के एक्ट के अनुसार किये गये सर्वेक्षण के आधार पर जिले का क्षेत्रफल 4581'13 वर्ग मील या 2931, 921, 52 एकड़ है। इस तरह प्रान्त में यह मिर्जापुर के बाद दूसरा सबसे लम्बा मैदानी जिला है। 1865 ई० में जब गोरखपुर में से एक नये जिले बस्ती का निर्माण किया गया तो इसके क्षेत्र में कमी आयी। 1904 ई० में भी इसके कुछ गांवों का स्थानान्तरण आजमगढ़ को किया गया। 1904 ई० के बाद इसका क्षेत्रफल 4, 51, 413 वर्ग मील हो गया है।

गोरखपुर जिले के उत्तर दिशा में नेपाल, दक्षिण में घाघरा नदी, पूर्व में सारन और चम्पारन जिले तथा पश्चिम में बस्ती जिला है।

---

9. कायस्थ, एस० एल० व सिंह, एम० बी० – लेख 'दी यूटीलाइजेशन आफ ह्यूमन रिसोर्सेज ; ए स्पेशल एनालिसिस आफ मैनुफैक्चरिंग इंस्टालमेंट इन ईस्टर्न यू०पी० – दी नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल आफ इंडिया–अंक 24 (वाराणसी – सितम्बर – दिसम्बर 1978) पी० 18

10. त्रिपाठी, आमोद नाथ – 'पूर्वी उ० प्र० के जन जीवन में बाबा राघवदास का योगदान'। शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ० – 6

1857 के पहले गोरखपुर में आधुनिक बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर तथा बलिया के कुछ भागों से बने मंडल का मुख्यालय था। परन्तु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद पूरा मंडल (उस समय का गोरखपुर मंडल) बनारस मंडल के साथ मिला दिया गया। 1891 में गोरखपुर कमिश्नरी में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ जिले थे। वर्तमान गोरखपुर जिला उसमें से निकाल दिया गया है। 1946 में देवरिया और गोरखपुर जिले अलग कर दिये गये।[11]

यहाँ की जनता को अक्सर अकाल और अभाव की विपत्ति झेलना पड़ा।[12] 1861 से 1901 के बीच आजमगढ़ प्रतिवर्ष अतिवृष्टि अथवा सूखे के कारण उत्पन्न गम्भीर कठिनाइयों से जूझता रहा।[13] बस्ती जिला 1874 व 76 में अकाल से पीड़ित रहा। 1896 – 97 में मूल्यवृद्धि का प्रभाव बस्ती पर भी पड़ा।[14]

इस क्षेत्र में आम आदमी को अपनी आजीविका के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कृषि कार्यों में महिलायें भी पुरुषों का साथ देती हैं। अक्सर दिन के कठिन श्रम के बाद स्त्री-पुरुष नाच गा कर अपना मनोरंजन करते हैं। जिले में विभिन्न उत्सवों और मौसमों में गाये जाने वाले मुख्य लोक गीत हैं – दीपावली के अवसर पर कहरवा, होली के समय फाग, वर्षा के दिनों में आल्हा, बारहमासी, कजरी और जाड़ों की रात बिरहा।[15]

---

11. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स – गोरखपुर. 1985
    पृ0 170
12. इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया यूनाइटेड प्राविन्सेज खण्ड 2
    (कलकत्ता 1908) पृ. 209
13. वही, पृ0 237
14. वही, पृ0 226
15. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्टगजेटियर्स – गोरखपुर – 1985 उ0प्र0 सरकार
    द्वारा प्रकाशित , पृ0 237.

महिलायें भी देवी गीत गाती हैं। जिले के लोकप्रिय लोक नृत्यों में कहरवा, धोबिया और नेटुआ है जो कि त्योहारों, शादियों और मेलों में किये जाते हैं। हारमोनियम, ढोलक, मजीरा, थाली, मृदंग, नगाड़ा और हुक्का मुख्य वाद्य यंत्र हैं।[16]

प्राचीन इतिहास :

गोरखपुर के प्रारम्भिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है।[17] महाकाव्यों के युग में यह क्षेत्र कारूपथ के नाम से जाना जाता था। यह कोशल राज्य का भाग था[18] जो कि आर्य सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र था।[19] यह बस्ती जिले के साथ महाकोशल राज्य का भाग था जहाँ राप्ती और घाघरा नदियों के संगम पर भगवान राम ने तपस्या की थी। बौद्ध धर्म को यहाँ पर संरक्षण मिला। उसका विकास हुआ। ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि 500 ई० पू० में बौद्ध धर्म गोरखपुर में आया। कहा जाता है कि मौर्यों व लिच्छवियों ने इस जिले में शासन किया था। चौथी शताब्दी में लिच्छवियों के हाथ से यह स्थान चंद्रगुप्त के हाथ में चला गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पर आदि वासियों ने शासन किया।[20]

---

16. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स-गोरखपुर - 1985, उ० प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित। पृ० 237,
17. राम आधार पान्डे "हिस्ट्री आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ गोरखपुर" शोध प्रबन्ध। पृ० 1
18. डा० राजबली पान्डे - गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास पृ० 4
19. आर० एस० त्रिपाठी - हिस्ट्री आफ एनशियेन्ट इंडिया पृ० 41.
20. राम आधार पान्डे - हिस्ट्री आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ गोरखपुर - शोध प्रबन्ध. पृ० 2

पूर्व मध्यकालीन इतिहास :

इस अवधि में यहां का शासन स्थानीय नायकों के हाथ में था । घाघरा व गंडक नदियों के मध्य फैला सारा भू-भाग बाद में मुस्लिम शासन के अन्तर्गत आ गया । महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके जनरल मसूद सालार ने जिले के पूर्वी भाग में प्रवेश किया । वहां उसे प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और अचानक उसकी मृत्यु हो गया । चौथे आक्रमण के बाद गजनवी ने जिले के उपद्रवी राजाओं को जानने के उद्देश्य से वहां पर एक सेना और मुस्लिम निवासियों का प्रवेश भेजा । परन्तु इन क्रिया कलापों ने यहां के निवासियों का आतिथ्य की भावना समाप्त कर दी और शीघ्र ही एक प्रबल विरोध को जन्म दिया । जिले से मुसलमानों को खदेड़ दिया गया । इस बार सालार ने एक बार फिर जिले की ओर इस निश्चय के साथ प्रस्थान किया कि या तो विजय प्राप्त करे या शहादत । राजाओं के साथ बड़े संघर्ष में सालार मारा गया और इसकी मृत्यु के साथ ही मुसलमानों की घाघरा नदी के पूर्व में विजय की आशायें समाप्त हो गया ।

ऐबक और खिलजी ने अवध और बिहार को क्रमशः 1193 ई० और 1200 ई० में जीता, पर इस जिले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 1553 ई० में जब फिरोज तुगलक बंगाल के हाजी इलियास शाह के विरुद्ध एक अभियान में संलग्न था, तब वह गोरखपुर के नजदीक रुका था और यहां के स्थानीय नेता उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिये एकत्र हुये थे ।[21] 12वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के अन्त तक गोरखपुर का इतिहास प्रधान रूप से मुख्य क्षत्रिय जातियों का इतिहास है । सबसे पहले बिसेन आये पर शीघ्र ही डोमकटारों द्वारा

---

21. राम आधार पान्डे - 'हिस्ट्री आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ गोरखपुर' शोध प्रबन्ध - इलाहाबाद विश्वविद्यालय । पृ० 3.

निष्कासित कर दिये थे। इसके बाद भूमिहारों का जिले में प्रवेश हुआ और वे धुरियापार परगने में बस गये। इसके बाद कौशिक और सार्नेट आये : अन्ततः सार्नेट भोपालराज को वहाँ से हटाने में सफल हुये।

मुगलों के अधीन :

अकबर के शासन के प्रारम्भिक वर्षों में गोरखपुर जिला बंगाल राज्य का एक भाग था। 1595 से यह अकबर के पाँच सिरकारों में से एक था और तब इसमें बस्ती, गोंडा व आजमगढ़ के जिले भी शामिल थे। इससे 30 लाख रुपये की आय होती थी। इसमें उनवल परगना भी शामिल था। अकबर के राज्य में खान जामन ने विद्रोह किया और मारा गया। उसका भाई सिकन्दर खान अयोध्या और फिर वहाँ से गोरखपुर भाग आया। अकबर के दीर्घकालीन शासन में जिले ने अधिकतम विकास किया। शाहजहाँ के समय में जिले में व्यापक असंतोष और विद्रोह की भावना थी। जिले के जमींदार स्वेच्छाचारी हो गये और बाद में उन्होंने कर देने से इंकार कर दिया। परिणामतः पहली बार यह जिला सैनिक शासन के सुपुर्द किया गया। औरंगजेब के शासन काल में गोरखपुर ने पुनः समृद्धि प्राप्त की, पर उसकी मृत्यु के साथ ही जिले का पतन शुरू हो गया।[22]

अवध के नवाब के अधीन :

1721 ई० में सादात खाँ को अवध प्रान्त मिला, इसमें तब गोरखपुर शामिल था। उसने स्थानीय राजाओं को दबाने की नीति अपनायी। दक्षिणी परगनों में वह स्थानीय नेताओं को कम करने में सफल रहा, पर उत्तरी परगनों में वह असफल रहा।

---

22. राम आधार पान्डे - 'हिस्ट्री आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ गोरखपुर, शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ० 4 - 5

इन्हीं परिस्थितियों में बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला पराजित हुआ। उसके प्रतिनिधि कर्नल हैना को सैनिक दलों की कमान और गोरखपुर तथा बहराइच में राजस्व कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गयी। कर्नल हैना ने ठेकेदार के कार्यालय समाप्त कर दिये और अमाल नियुक्त किये जो कि राजस्व इकट्ठा करने के ठेकेदार थे। अमालों ने भूमि कर एकत्र करने में बल का प्रयोग किया। परिणामतः बड़ी संख्या में लोग स्थान छोड़ कर जाने लगे। कर्नल हैना के तीन वर्षों के प्रशासन के दौरान 60,000 निवासी स्थान छोड़ कर गये।

बहुत से कमजोर जमींदार स्थान छोड़ कर चले गये। बहुत से समाप्त कर दिये गये और एक बड़ी संख्या को उनके राज्यों से निष्कासित कर दिया गया। निर्विवाद रूप से हैना के नागरिक प्रशासन ने जिले को अन्तिम रूप से नष्ट कर दिया।[23]

बन्जारों की गतिविधियों से जिले में एक नयी हलचल उत्पन्न हुयी। इन्होंने राजाओं की उपाधियां छीन लीं और आपसी भिन्नता के कारण जिले पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजा इनके विरुद्ध अपने हितों की रक्षा न कर सके। अन्ततः बस्ती के राजा ने बंजारों को हरा कर उन्हें उनकी शक्ति व अधिकार से वंचित किया। एकमात्र राज्य मझौली सम्पन्न था। उसने बंजारों के अतिक्रमण के भय से पडरौना और तमकुही राज्यों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया।

23· रामाधार पान्डे - "हिस्ट्री आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ गोरखपुर" शोध प्रबन्ध 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय' पृ0 5-6

जिले का हस्तांतरण : 1801 ई०

1801 में नवाब की भूमि जो कि ब्रिटिश सैनिकों के लिये थी, मंहगी हो गया। नवाब वजीर (सादात अली खां) उनकी ऋण चुकाने में असमर्थ था। उसने ऋण को चुकाने के लिये नवम्बर 1801 में एक सन्धि के द्वारा अन्य क्षेत्रों के साथ गोरखपुर और बुटवल को ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया जिसकी वार्षिक आय 549, 854 रुपया 8·0 ए·पी· थी। जोन रोटलेन की कलेक्टरी में कोई प्रशासन नहीं था। चार लाख से ऊपर की संख्या में किसान स्थान छोड़ कर चले गये, जो बचे उन्होंने खेती की उपेक्षा की।[24]

पूर्वांचल की जनता गरीबी, शोषण, अशिक्षा एवम् अन्धविश्वासों से ग्रस्त थी। योग्य नेतृत्व व सही मार्ग दर्शन मिलने पर यह देश अन्याय, शोषण व अत्याचार के विरुद्ध हमेशा तैयार मिला। जमींदारों के शोषण व अत्याचार के विरुद्ध प्रतापगढ़ के बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में अवध के किसान खड़े हो गये। इसी तरह पूर्वांचल के गांवों में बसने वाली प्रताड़ित, अभावग्रस्त एवं बुभुक्षित जनता के भीतर छिपी इस महान शक्ति को पहचानने का कार्य बाबा राघवदास ने किया। उनके जीवन का लक्ष्य यहां की जनता में राजनीति, सामाजिक जागरूकता को विकसित करना हो गया।[25]

24· राम आधार पान्डे - 'हिस्ट्री आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ गोरखपुर' शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ० 6 ·

25· आमोद नाथ त्रिपाठी - 'पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन जीवन में बाबा राघव दास का योगदान' शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ० 36

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा तथा पिछड़ी सामाजिक स्थिति के कारण राजनीतिक जागृति व सक्रियता अपेक्षाकृत कुछ देर से आयी।[26] बाबा राघवदास के अथक प्रयासों से[27] तथा शिव प्रसाद गुप्त के सहयोग से चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खाँ, पं० परमानन्द ने पूर्वी जनपदों में स्वतंत्रता की लहर जगाया।[28]

1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा को सरकार का कर्तव्य बना दिये जाने के कारण शिक्षा की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ पर फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँवों की बहुसंख्यक जनता अशिक्षा की भंवर में पड़ी रही। बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक तक स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ। समाज के पिछड़े वर्ग में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं की जा सकी थी।[29]

ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 1801 में जब गोरखपुर दे दिया गया तब यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा हुआ था।[30] 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बुकानन ने कहा कि जिले के अनेक भागों में एक भी स्कूल नहीं है।[31]

---

26. डा० अर्जुन तिवारी - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में) पृ० 30
27. आमोद नाथ त्रिपाठी - 'पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन जीवन में बाबा राघव दास का योगदान' शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ० 36
28. डा० अर्जुन तिवारी - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में) पृ० 30
29. सप्लीमेंटरी नोट्स आन दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध (1921 - 22) इलाहाबाद 1923, जनरल समरी, पृ० 43-44
30. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स-गोरखपुर-1985, उ० प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ० 228
31. वही, पृ० 228

प्राचीन समय में गोरखपुर जिले का अधिकांश भाग जंगलों से घिरा हुआ था जहां पर ऋषि लोग आश्रमों में रहते थे और देश के विभिन्न भागों से आने वाले लड़कों को शिक्षा देते थे। उपनयन संस्कार के साथ नियमित शिक्षा शुरू कर दी जाती थी। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय का अध्ययन कर सकता था परन्तु वेदों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था। शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, शिक्षक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता था। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था। छात्रों अथवा उनके माता पिता द्वारा जो कुछ भी दिया जाता था, उसी में शिक्षक लोग संतुष्ट हो जाते थे।[32]

यह गुरुकुल प्रणाली मुसलमानों के आने तक थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ बनी रही। मध्य काल में ये संस्थायें व्यक्तिगत पाठशालाओं में बदल गयीं। जब इस भू भाग में मुसलमान लोग व्यवस्थित हुये तो उन्होंने अपनी पाठशालायें स्थापित कीं। ये मकतब या मदरसा कहे जाते थे। जहां पर मौलवी इस्लाम के विभिन्न शाखाओं के बारे में शिक्षा दिया करते थे।[33]

19वीं शताब्दी के अन्त तक शिक्षा की पुरानी स्वदेशी प्रणाली समाप्त होने लगी और उसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान प्रसारित करने की प्रणाली स्थापित की गयी।

---

32. वही, पृ0 227

33. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स - गोरखपुर - 1985. उ0 प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित पृ0 227 - 28

1835 में एक स्थानीय संस्था द्वारा एक नि:शुल्क विद्यालय खोला गया, पर नौ वर्ष के बाद बन्द कर दिया गया । 1844 में चर्च मिशनरी सोसाइटी द्वारा खोला गया स्कूल काफी समय तक जिले का एक मात्र महत्वपूर्ण संस्था था । 1847 में जब शिक्षा के ऊपर पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, तब 243 पर्शियन 170 संस्कृत और 15 हिन्दी स्कूल गोरखपुर और बस्ती जिलों में थे जिनमें 3,808 छात्र थे । मई 1856 में 'हल्काबन्दी' प्रणाली के अन्तर्गत गांवों में स्कूल खोले गये और उसी समय सलेमपुर, पिपराइच और साहबगंज में तहसीली स्कूल खोले गये ।[35]

1850 में पश्चिमोत्तर प्रान्त की सरकार द्वारा जनता में शिक्षा का प्रचार करने के लिये स्वदेशी विद्यालयों के विकास और उन्नति की एक योजना बनायी गयी । इसने प्रत्येक तहसील के मुख्यालय में एक सरकारी स्कूल खोलने का प्राविधान किया । ये विद्यालय अधिक सफल नहीं हुये ।

1856 में तीन तहसीली स्कूल सलेमपुर, पिपराइच और साहबगंज में खोले गये परन्तु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण शिक्षण कार्य को धक्का लगा । 1858 में जब दुबारा स्कूल खुले तो तहसीली में 52 छात्र और 11 गांव के स्कूलों में 108 छात्र थे । 180 छात्रों का एक चर्च मिशनरी सोसाइटी स्कूल भी था । 10 साल बाद 1868 में संख्या और बढ़ गयी । चर्च मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल तथा अनाथालय के अतिरिक्त 176 हल्काबन्दी स्कूल थे जिनमें 9,505 छात्र, 11 स्कूल लड़कियों के थे, जिनमें 281 छात्रायें थी । 185 स्कूल डेली प्रणाली के थे । इनमें 2,243 विद्यार्थी थे । 14 मिडिल स्कूलों में 1,116 विद्यार्थी थे ।

---

35. वही, पृ0 228 - 29,

1878 में स्कूलों की संख्या 407 तथा छात्रों की संख्या 9,769 हो गयी । 1888 में हल्काबन्दी स्कूल 80 रह गये तथा सभी सरकारी स्कूलों में संख्या 7,371 हो गयी । 1899 में विद्यार्थियों की संख्या 20,000 हो गयी ।[36]

1901 में गोरखपुर जिले की आबादी का मात्र 2·8% (5·5% पुरुष तथा 0·1% स्त्रियां) शिक्षित था ।[37] 1901 में आजमगढ़ में 3·3% व्यक्ति शिक्षित थे ।[38] यहां के 90% से 95% किसान ऋण के बोझ से दबे हुये थे । विवाह व मृत्यु के अवसरों पर होने वाले भारी व्यय तथा कपड़े गहने खरीदने के लिये वे ऋणग्रस्त होने के लिये बाध्य थे ।[39] बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तकनीकी रूप से अत्यधिक विकसित आधुनिक चीनी मिलों के स्थापित होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के खांडसारी व गुड़ उद्योग को गम्भीर क्षति पहुंची तथा मिल मालिकों द्वारा गन्ना बोने वाले किसानों का शोषण प्रारम्भ हुआ ।[40]

नवाभ्युत्थान या पुनर्जागरण एक बौद्धिक चेतना मात्र थी, इसने तत्कालीन साहित्य को प्रभावित किया । अगली पीढ़ी में यह एक नैतिक उपाय बना जिसने भारतीय धर्म व समाज को सुधारा । दूसरी पीढ़ी में इसने आधुनिकीकरण को जन्म दिया जिसके फलस्वरूप ही बाद में राजनीतिक एकीकरण सम्भव हो सका ।"

36· उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स-गोरखपुर 1985, उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ0 229-230,

37· इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया यूनाइटेड प्राविन्सेज खण्ड 2 (कलकत्ता 1908) पृ0 210·

38· इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया-यूनाइटेड प्राविन्सेज -खण्ड 2 (कलकत्ता 1908) पृ0 230,

39· आमोद नाथ त्रिपाठी-पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन जीवन में बाबा राघव दास का योगदान शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय । पृ0 34,

40· आमोद नाथ त्रिपाठी- पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन जीवन में बाबा राघवदास का योगदान' शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृ0 35.

यह पुनर्जागरण भावना का विषय है जिसने राष्ट्र के विकास की मांग के साथ साथ धर्म, समाज व संस्कृति में अनेक परिवर्तन किये । इस समय सामाजिक जीवन के क्षेत्र में अराजकता व अव्यवस्था थी । सामन्तवादी व्यवस्था से देश जड़ हो गया था । पुनर्जागरण वास्तव में एक विस्तृत आन्दोलन था जिसने राष्ट्रीय जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया, धर्म, साहित्य कला, विज्ञान, शिक्षा राजनीति व समाज में नयी बातों का विकास हुआ ।

अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस व साहित्य के विकास ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया । देश का शिक्षित वर्ग अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के प्रति जागरूक हुआ । तथा समाज की बुराइयां दूर करने के लिये कृत संकल्प हुआ । फलस्वरूप बंगाल में राजा राम मोहन राय ने ब्रम्ह समाज की स्थापना 1875 में की । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू समाज की कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से 'वेदों की ओर लौटो' (Back to Vedas) का नारा दे कर आर्य समाज की स्थापना की । इसी तरह से रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना हुयी । स्वामी विवेकानन्द ने पाश्चात्य जीवन की अच्छाइयों को अपनाने पर जोर दिया । धीरे - धीरे देश के लगभग हर भाग में इनकी शाखायें स्थापित हुयी । इसने अन्धविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों को दूर कर के भारतीय जन मानस को उदार दृष्टिकोण का बनाया तथा उसमें राजनीतिक चेतना की भावना भी जागृत की ।[41]

यह सत्य है कि डलहौजी की अपहरण नीति, स्वतंत्र देशी राज्यों के नि:संतान राजाओं के दत्तक पुत्रों के सिंहासनारोहण के अधिकार को अस्वीकार करना नयी लागू की गयी कर व्यवस्था तथा ऐसे कानून व नियमों के पास होने से जिन्होंने लम्बे समय से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं पर आघात किया -

41. विपिन चंद्र, त्रिपाठी, अमलेश व दे सरून - स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 26-30

और इस सबसे भारतीय समाज में बहुत असंतोष फैला तथा वह शासन से दूर होता गया।[42] 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध की जनता के विरुद्ध अवध पर कब्जा करना 1857 के संग्राम का मुख्य कारण था। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता का यह पहला संग्राम 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ हुआ था। इसी क्षेत्र में संघर्ष के केन्द्र रहे।[43] संग्राम के समय केवल सैनिक वर्ग में ही नहीं वरन् किसानों, ताल्लुकदारों, जमींदारों में भी असंतोष व्याप्त था।[44] लगभग सभी प्रान्तों में महिलाओं ने लोगों को संग्राम में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया तथा इसके प्रचार - प्रसार में मदद दी।[45]

1857 में 10 मई को मेरठ से प्रथम सैनिक महाविद्रोह का प्रारम्भ हुआ।[46] यह संग्राम देश के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता हुआ तेजी से सारे देश में फैल गया। निःसन्देह संघर्ष की शुरुआत सैनिकों ने की, जैसे - जैसे संघर्ष बढ़ा, उन्हें देश के पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत के असंतुष्ट वर्गों से मदद मिलती गया।[47] उत्तर प्रदेश में इस संघर्ष के मुख्य केन्द्र झांसी, कालपी, बिठूर, कानपुर, लखनऊ, अवध तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ जैसे जिले थे। इस दौरान अनेक वीरों का उदय हुआ। झांसी की लक्ष्मी बाई, बिठूर के नाना साहब तथा तात्या-टोपे, उनके प्रमुख सहायक अजीमुल्ला खां और अवध की बेगमें, मौलवी अहमदुल्लाशाह

---

42. बन्दोपाध्याय, हर प्रसाद - 'दि सिपाय म्यूटिनी 1857' "ए सोशल स्टडी एंड ऐनालिसिस" पृ0 - 20
43. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद - 'हमारे देश के राज्य' उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पृ0 - 13,
44. बन्दोपाध्याय, हर प्रसाद - दि सिपाय म्यूटिनी ए सोशल स्टडी एंड एनालिसिस' पृ0 20
45. कौर, मनमोहन - 'रोल आफ विमेन इन दि फ्रीडम मूवमेन्ट (1857-1947) पृ0 15
46. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद- "हमारे देश के राज्य-उत्तर प्रदेश"-प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार - पृ0, 18
47. बन्दोपाध्याय, हरप्रसाद - दि सिपाय म्यूटिनी ए सोशल स्टडी एंड एनालिसिस पृ0 21.

तथा राजा बेनी माधव मुख्य थे । जब यह विद्रोह दबाया गया तो विशाल स्तर पर दमन चक्र चला ।[48]

कुछ हमारी राष्ट्रीय खूबियां हैं कि कारण हम इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर सके और कुछ हमारी राष्ट्रीय खामियां हैं कि काफी शक्ति होते हुये भी हम स्वतंत्रता का संग्राम हार गये ।[49]

1857 के विफल स्वतंत्रता प्रयास के बाद का समय भयंकर था । तीन वर्ष तक फसलें नष्ट होती रहीं और जीवन निर्वाह का भार बढ़ता चला गया । 1859-61 तक किसानों का विद्रोह (नील की खेती), 1872-73 में पबना और बोगरा के किसानों का आन्दोलन रहा ।

विदेशी शासन के विरुद्ध संग्राम का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग ने संभाला । पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन शुरू किया । अंग्रेजों की अकड़ से भारतीयों में राष्ट्रीय अपमान की चेतना ने और जोर पकड़ा । प्रेस एक्ट व आर्म्स एक्ट द्वारा इस चेतना को दबाने का प्रयास किया गया । सरकारी नौकरियों में भेदभाव की नीति भारतीयों को अखरने लगी थी ।[50]

एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो सारे भारत की संस्था हो तथा राष्ट्रीय मांग व आवश्यकतायें स्पष्ट कर सके । 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ ।[51]

---

48. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद - हमारे देश के राज्य उत्तर प्रदेश-प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार-पृ० 18
49. 'प्रभाकर', कन्हैया लाल मिश्र - उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी - सूचना विभाग उत्तर प्रदेश पृ० 20,
50. विद्यार्थी, रामशरण एवं गुप्त मन्मथ नाथ - मुझे किसने क्रान्तिकारी 'क्रान्तिकारी आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास ।' पृ० 7,8
51. गहलौत, वी०एस० - 'पूर्वी उ०प्र० में स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास' शोध प्रबन्ध - इलाहाबाद विश्वविद्यालय । पृ० 7,8.

गोरखपुर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारम्भ मई महीने के अन्तिम दिनों में हुआ। यहाँ भारतीय सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारियों ने अतिरिक्त खजाना गोरखपुर से हटा कर आजमगढ़ भेज दिया गया तथा सेना एवम् पुलिस को शक्तिशाली ढंग से संगठित करने का प्रयास किया।[52] पैना गाँव के (देवरिया) निवासियों ने 1857 के विद्रोह में पहल की।

मई में पैना के निवासियों ने अनाज से लदी अंग्रेजी नौकाओं को लूट कर गोरखपुर आजमगढ़ जलमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया।[53] नरहरपुर के राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। राजा और उसके आदमियों ने बड़हलगंज (गोरखपुर) में 50 कैदियों को मुक्त करा दिया। और चौकी के जमादार को धमकाया। गोरखपुर से आजमगढ़ से को जोड़ने वाले बड़हलगंज के नौका मार्ग पर अधिकार कर नरहरपुर के राजा ने आजमगढ़ से गोरखपुर का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। 7 जून को गोरखपुर जेल में बन्द कुछ विचाराधीन कैदियों ने जेल से भागने का असफल प्रयास किया।[54] 10 जून को महुआडाबर के निवासियों ने फैजाबाद के उपद्रवों से जान बचा कर भाग रहे छः अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।[55] जिले में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोरखपुर के अधिकारियों ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया।[56] 200 गुरखा सैनिकों को अंग्रेजों की सहायता के लिये

52. नेविल, एच0आर0-डिस्ट्रिक्ट गजेटियर गोरखपुर (इलाहाबाद 1909) पृ0189
53. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक देवरिया पृ0 - 1-4
54. गोरखपुर के मैजिस्ट्रेट का गोरखपुर के कमिश्नर को पत्र दि0 2जुलाई सं01857, गोरखपुर मैजिस्ट्रेट आफिस रिकार्डस, बस्ता नं0 181, पत्र सं0 144 (क्षेत्रीय अभिलेखागार, इलाहाबाद)
55. वही
56. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, देवरिया, पृ0 1-4.

नेपाल के महाराज ने पलपा से गोरखपुर भेजा ।[57] पर वे भी विद्रोह को शान्त करने में असफल रहे । बाध्य हो कर जिले के यूरोपीय अधिकारियों ने गोरखपुर छोड़ने का निश्चय किया । गोरखपुर छोड़ने के पहले जिला जज विनयार्ड ने जिले की सुरक्षा का भार पांच राजाओं की परिषद को सौंप दिया ।[58] इस परिषद के सदस्य सतासी, गोपालपुर, सलेमपुर, तम्कुही व आंसी के राजा थे । राजा साहब गोपालपुर के अतिरिक्त परिषद के अन्य किसी सदस्य ने इस थोपे गये उत्तरदायित्व के निर्वाह में रुचि नहीं ली । शीघ्र ही यह परिषद व्यावहारिक रुप से भंग हो गया ।[59]

अवध के चौकीदार मुहम्मद हसन ने स्वयं को गोरखपुर तथा आजमगढ़ जिलों का नाजिम घोषित कर दिया । राजा साहब सतासी एवं कुछ प्रमुख मुसलमानों की सहायता से स्वयंभू नाजिम मुहम्मद हसन ने राप्ती पार कर गोरखपुर में प्रवेश किया । मुहम्मद हसन के गोरखपुर में प्रवेश करते ही मजिस्ट्रेट बर्ड जंगल में भाग गया । नाजिम मुहम्मद हसन ने बर्ड का सर काट कर लाने वाले को 5000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की । यह घोषणा सुन कर बर्ड मोती हारी (बिहार) की ओर चला गया ।[60] नाजिम ने बेतिया राज के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अत्याचार किया । उसने महाराज बेतिया तथा अंग्रेज कलेक्टर की सम्पत्ति भी लूटी ।[61]

---

57. नेविल - डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-गोरखपुर, पृ0 189,
58. रिजवी - फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश, खन्ड 4, पृ0 294
59. गोरखपुर के कमिश्नर को गोरखपुर कलेक्टर का पत्र गोरखपुर बोर्ड आफ रेवेन्यू रिकार्ड्स , सूची सं0 34, मिसलेनियस 21 (राजकीय अभिलेखागार इलाहाबाद)
60. फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश - खन्ड 4- पृ0 157-58,
61. 25 दिसम्बर 1857 को बेतिया महाराज राजेन्द्र किशोर सिंह का गोरखपुर के कमिश्नर को पत्र-गोरखपुर मैजिस्ट्रेट आफिस रिकार्ड्स , मिसलेनियस-बस्ता नं0 185 (क्षेत्रीय अभिलेखागार इलाहाबाद,

बहुत से राजाओं जमींदारों व बाबुओं ने नाजिम की अधीनता स्वीकार कर ली । कुछ समय के लिये नाजिम मुहम्मद हसन गोरखपुर का वास्तविक शासक बन गया । हिंसा व अराजकता के इस वातावरण में विद्रोहियों ने यूरोपीय अधिकारियों के अधिकांश निवास स्थानों को लूट लिया और जला डाला ।[62] 25 दिसम्बर को सुगौली से नेपाल के महाराजा जंग बहादुर के नेतृत्व में 500 गुरखा सैनिकों की सहायता अंग्रेजों को प्राप्त हुआ । 28 दिसम्बर 1857 को छोटी गंडक नदी के किनारे मझौली में अंग्रेजी सेना और विद्रोहियों के बीच हुये युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिली । इस युद्ध में 127 से अधिक विद्रोही मारे गये तथा एक बड़ी संख्या में घायल हुये । नायब नाजिम मुसर्रत खां और पटना के अली करीम मौलवी ने भी इस संघर्ष में भाग लिया था ।[63] गुरखा सैनिकों ने सलेमपुर पर अधिकार कर लिया ।[64] महाराजा जंग बहादुर ने 6 जनवरी 1858 को गोरखपुर पर अधिकार कर लिया ।[65] नायब नाजिम मुसर्रत खां गिरफ्तार कर लिया गया तथा गोरखपुर शहर के प्रमुख बाजार में हजारों की भीड़ के सामने उसे फांसी दे दी गयी ।[66] लेफ्टीनेन्ट मुलन और वर्ड के नेतृत्व में सिख रेजीमेन्ट ने पैना के विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया और पैना गांव को जला दिया ।[67] गोरखपुर की

---

62. फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश - खन्ड 4, पृ0 157-58
63. वही, पृ0 299-300
64. त्रिपाठी,आमोद नाथ पूर्वी उ0प्र0 के जनजीवन में बाबा राघवदास का योगदान शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय - पृ0 15
65. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, देवरिया - पृ0 1-4
66. फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश - खन्ड 4 - पृ0 305
67. वही, पृ0 342

स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजों ने विद्रोहियों को और उनका साथ देने वालों को क्रूरतापूर्वक दंडित किया । विद्रोहियों और उनके सहयोगियों को फांसी, आजीवन कारावास या 14 वर्ष की कैद का दण्ड दिया गया और उनकी सम्पत्ति जप्त कर ली गयी ।[68] पराजय के अपमान से बचने के लिये नरहपुर के राजा ने जंगल की शरण ली । नाजिम मुहम्मद हसन खां ने 1859 में अंग्रेजों के सम्मुख आत्म समर्पण किया ।[69]

प्रशासनिक सुविधा व कुशलता की दृष्टि से गोरखपुर जिले को खंडित करके 6 मई 1865 को बस्ती नामक नया जिला बनाया गया ।[70] गोरखपुर जिले में देवरिया व कसिया नामक नये सब डिवीजनों का निर्माण किया गया । देवरिया जिले का निर्माण 1946 में हुआ ।

आजमगढ़ में नेटिव इंफैन्ट्री की 17वीं रेजीमेन्ट ने 3 जून 1857 को विद्रोह किया । विद्रोहियों ने कुछ यूरोपीय अधिकारियों को मार डाला तथा सरकारी खजाना फैजाबाद उठा ले गये । विद्रोहियों से भयाक्रान्त हो कर यूरोपीय अधिकारियों ने गाजीपुर में शरण ली । आजमगढ़ के विद्रोह में पालवारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ।[71] 26 अगस्त को नेपाल के गुरखा सैनिकों ने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया । 3 सितम्बर को सभी यूरोपीय अधिकारी (सिविल) पुनः आजमगढ़ आ गये ।[72] लखनऊ से भागते समय कुंवर सिंह ने फरवरी 1858 के मध्य में आजमगढ़

---

68. त्रिपाठी, आमोद नाथ – पूर्वी उ0 प्र0 के जन जीवन में बाबा राघव दास का योगदान– शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृ0 15
69. फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश, खण्ड 4 – पृ0 371,
70. त्रिपाठी,आमोद नाथ – पूर्वी उ0प्र0 के जन जीवन में बाबा राघव दास का योगदान । शोध प्रबन्ध– इलाहाबाद विश्वविद्यालय – पृ0 16
71. इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया – यू0 पी0 आफ आगरा एंड अवध खण्ड – 2 (1908) पृ0 232,
72. वही, पृ0 232,

जिले में प्रवेश किया । अप्रैल के मध्य तक आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का प्रभाव बना रहा । विद्रोहियों की छिटपुट गतिविधियों के कारण अक्टूबर 1858 तक आजमगढ़ में अव्यवस्था रही । कर्नल केली अक्टूबर में पुनः शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुआ ।[73]

1893 में एक गोरक्षिणी आन्दोलन छिड़ा था । 1865 में बस्ती जिला गोरखपुर से अलग कर दिया गया । बलिया व देवरियां का सब डिवीजन बनाया गया । विद्रोह के कुछ समय बाद गोरखपुर की कमिश्नरी भी तोड़ दी गयी थी । इसे बनारस कमिश्नरी में मिला दिया गया था । 1891 में पुनः स्वतंत्र गोरखपुर कमिश्नरी बनायी गयी ।[74] 1873-74 में जिले में भयंकर अकाल पड़ा । 15 जनवरी 1885 में जिले में बंगाल और उत्तरी पश्चिमी रेलवे खोली गयी ।

इस समय किसानों अथवा ग्रामीण लोगों की बेहतरी के लिये प्रभावशाली कदम या कानून नहीं बनाये जा सके । भूमि का वास्तविक स्वामी धीरे-धीरे अपनी भूमि से अधिकार खोता गया । जबकि दूसरी ओर जमींदार की अच्छी स्थिति में था । इस बढ़ते असंतोष ने शक्तिशाली ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिये प्रेरित किया तथा इन लोगों ने प्रान्त के अन्य भागों में चल रहे आन्दोलन को पूर्ण हृदय से समर्थन दिया ।[75]

---

73. इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया - पृ0 232 .
74. पाण्डे, राजबली - गोरखपुर जनपद और क्षत्रिय जातियों का इतिहास । पृ0 - 267 - 68
75. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ 'गोरखपुर' (1985) पृ0 39 - 40,

" सुधार काल " (1885-1905)

प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन के थमने के बाद एक अरसे तक पूरे देश में सन्नाटा बना रहा, पर भीतर ही भीतर नया विद्रोह धीरे - धीरे गति पकड़ने लगा था ।[1] उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में भारत में चतुर्दिक चेतना का संचार हुआ, स्वदेश प्रेम की भावना प्रबल होती गयी तथा आँग्ल शासन के प्रति गहन असंतोष बढ़ता गया । भारतीयों ने अपने अधिकारों की मांग की और उनके न मिलने पर विदेशी शासन के विरुद्ध संगठित रूप से मोर्चा लेने का निश्चय किया ।[2] 1859 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दबा तो दिया गया पर उसकी आग बुझी नहीं । 1884 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना होने के पहले से ही कसमसाहट के प्रमाण मिलने लगे थे । सही नेतृत्व के अभाव में कोई महत्वपूर्ण आन्दोलन छेड़ा नहीं जा सका ।[3]

1885 में अवकाश प्राप्त आई0 सी0 एस0 एलेन ऑक्टेवियन ने विभिन्न नेताओं के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना की । इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना था । साथ ही जनता की मांगों को सरकार के समक्ष रखना । डब्लू0 सी0 बैनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ । इस अधिवेशन में संयुक्त प्रान्त से छः प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

1885 से 1905 के मध्य कांग्रेस का मुख्य कार्य भारतीय राजनीतिज्ञों को मिलने व प्रशिक्षण के लिये एक सामान्य प्लेटफार्म देना था । कांग्रेस द्वारा वैधानिक सुधार की मांग रखने पर संघर्ष आरम्भ हुआ । कांग्रेस ने उच्च पदों के तथा उद्योगों के भारतीय करण पर तथा राजस्व कर कम करने तथा नमक कर

---

1. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर - पृ0 4
2. स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता - डा0 अर्जुन तिवारी (पूर्वी उ0 प्र0 के सन्दर्भ में) पृ0 25
3. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, संक्षिप्त परिचय बस्ती - पृ0 3-4

समाप्त करने की मांग रखी । 1892 के भारतीय कौंसिल एक्ट से असंतुष्ट हो कर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिनचंद्र पाल ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिये उग्र तरीकों पर जोर दिया ।[4]

1885 – 1905 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घटनायें हुयीं । 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अतिरिक्त बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन का उद्घाटन, बंगाल टैनेन्सी एक्ट पास हुआ । 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत का भाग घोषित किया गया । 1887 में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयन्ती मनायी गयी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी । 1889 में चार्ल्स ब्रेडला द्वारा भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिये बिल पेश करना । 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पास करके संयुक्त प्रान्त में 12 सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गयी । यह जनता को संतुष्ट नहीं कर सका । 1896 में सारे भारत में भयंकर अकाल की स्थिति । ब्रिटिश अफसर रैन्ड व अर्यस्ट की 1897 में पूना में हत्या । 1900 में अकाल आयोग की रिपोर्ट पेश की गयी । महारानी विक्टोरिया की 1901 में मृत्यु । 1904–5 मे रूस व जापान युद्ध में रूस की पराजय से भारतीयों के मन में यह भावना आयी कि अनन्य देशभक्ति व बलिदान से ही भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाया जा सकता है । 1905 में बंगाल का विभाजन तथा परिणाम स्वरूप प्रान्त में व प्रान्त से बाहर सार्वजनिक विद्रोह ।[5] कांग्रेस ने बंगाल विभाजन को अखिल भारत की समस्या बना दिया

लार्ड कर्जन ने बंगालियों की संघ शक्ति को कुचलने के लिये भीषण विरोध के बावजूद 19 जुलाई 1905 को बंग विभाजन की विस्तृत योजना प्रकाशित की । 16 अक्टूबर जो विभाजन दिवस था, बंगाली जनता के लिये शोक दिवस बन गया । जनता बन्दे मातरम् का उद्घोष हुआ तथा

---

4. घोष, पी0 सी0 – इंडियन नेशनल कांग्रेस – पृ0 25
5. राबर्ट्स, पी0 ई0 – ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास, पृ0 365–366,

एक दूसरे के हाथ पर राखी बांध कर समस्त बंगाल को एकता बनाये रखने का दृढ़ संकल्प किया गया । बंग भंग के कारण देश में स्वाभिमान व असंतोष की भावना जगी । देशवासी यह समझ गये कि एक हो कर ही अंग्रेजों से सामना किया जा सकता है । इस समय हर तरह दमन नीति, शोषण नीति अपनायी गयी ।[6]

लार्ड कर्जन ने बंगाल के दो टुकड़े कर के इस बढ़ती आग में घी डाल दिया । बंगाल में जो कुछ होता है, उसका प्रभाव हमारे यहां तत्काल पड़ता है । उन दिनों बंगालियों के साथ घूमने फिरने में खतरा था । सारे नगर में सरकारी गुप्तचरों का जाल बिछा था । खतरे की आशंका से उत्साह और बढ़ता था ।[7]

राजनीतिक हलचल के साथ स्वदेशी आन्दोलन जोरों से चला ।[8] इस बार बंग विच्छेद के बाद से लोगों का क्रोध उभरा हुआ था ।[9]

गोरखपुर का महत्व तराई का जिला होने के कारण अंग्रेजों के लिये अधिक था । यहां से नेपाल के गुरखा सैनिकों की भर्ती करते थे, इसलिये भी इस क्षेत्र को वे विशेष महत्वपूर्ण समझते थे । तराई की यह पट्टी बिहार तक फैली थी । निलहों के अत्याचारों की कहानी से खिंचकर गांधी जी चम्पारन आये थे । वैसी अत्याचारी कोठियां गोरखपुर में भी थीं।[10]

---

6. तिवारी डा० अर्जुन – स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता पृ० 26 – 27
7. सम्पूर्णानन्द – कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार पृ० 8
8. वही – पृ० 10
9. वही – पृ० 13
10. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक – संक्षिप्त परिचय – गोरखपुर, पृ० 4

1885–1905 के काल में इस जिले में शान्ति को भंग करने वाली कोई घटना नहीं हुयी ।[11]

अप्रैल 1888 में बनारस के कमिश्नर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भारत सरकार के सेना विभाग के सचिव को सूचित किया गया कि लेफ्टीनेन्ट गवर्नर और मुख्य कमिश्नर को गोरखपुर से सिपाहियों को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है ।[12]

मई 1888 में बनारस मंडल के आयुक्त को भारत सरकार के सैनिक विभाग की ओर से भारत के क्वार्टर मास्टर जनरल को लिखे पत्र की एक प्रति भेजी गया जिसमें गोरखपुर में सैनिक छावनी कायम रखने की बात था ।[13]

दिसम्बर 1888 में बनारस मंडल के आयुक्त से रिपोर्ट पाने के बाद सैनिक विभाग के सचिव को सूचित किया गया कि गोरखपुर छावनी का वहां के जिलाधिकारी द्वारा स्थायी प्रशासन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं ।[14]

19 मार्च 1889 को गोरखपुर में जमींदारों की सभा हुयी । इसमें गोरखपुर व बस्ती के जमींदार आये थे ।[15]

---

11. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर – गोरखपुर – 1985, पेज नं० 39
12. जी० ए० डी०, फाइल नं० 203 ए, बाक्स नम्बर 46, पृ० 1–6
13. वही, पृ० 7–8
14. वही पृ० 9–13
15. पायनियर – दैनिक समाचार पत्र – 1889 – 19 मार्च पृ० 5.

1893 में गोरखपुर में गोरक्षिणी आन्दोलन चला । इस आन्दोलन का उद्देश्य गौ हत्या रोकना था । इस क्षेत्र के कट्टर हिन्दुओं ने 1887 में गोरक्षिणी सभा नामक गुप्त समितियों की स्थापना की थी ।[16] 1888 में लार (देवरिया) में गोरक्षिणी सभा के सदस्यों ने एक सम्मेलन आयोजित किया । धीरे-धीरे यह आन्दोलन हिन्दुओं में लोकप्रिय होता गया । प्रतिक्रियास्वरूप मुसलमानों ने गोरक्षिणी सभा पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगा कर इसका विरोध करने का निश्चय किया ।[17] 19 अप्रैल 1893 को सोहनाग मेले के दिन हिन्दुओं ने गायों का झुंड लेकर जा रहे कसाइयों पर आक्रमण कर दिया । कसाइयों ने भी प्रत्युत्तर में हिन्दुओं पर आक्रमण किया और शीघ्र ही यह घटना साम्प्रदायिक दंगे के रूप में बदल गयी ।[18] मझौली की रानी ने गोरक्षिणी आन्दोलन को संरक्षण दिया ।[19] आन्दोलन को दबाने के लिये अंग्रेज सरकार ने कई कदम उठाये । बलिया, सलेमपुर, मईल, हरैया बेरौना आदि स्थानों (जहां यह आन्दोलन अधिक उग्र था) के सभी हिन्दू जमींदारों पर एक विशेष पुलिस कर लगाया गया । इस अतिरिक्त आय से उपरोक्त स्थानों के ~~प्रत्येक के~~ प्रत्येक थाने पर शान्ति व्यवस्था की देख रेख के लिये दो विशेष कांस्टेबुल नियुक्त किये गये । मझौली की रानी पर आन्दोलन को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया । दण्ड स्वरूप उन्हें अपने पुत्र के साथ गोरखपुर में रहने का निर्देश दिया गया । उन्हें चेतावनी दी गयी कि भविष्य में पुनः आन्दोलन को संरक्षण

---

16. त्रिपाठी, आमोदनाथ - पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन जीवन में बाबा राघवदास का योगदान शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ0 22
17. गोरखपुर के मैजिस्ट्रेट का गोरखपुर के कमिश्नर को पत्र संख्या 258/16-396, उ0 प0 अ0, फाइल नं0 730 बी, बाक्स नं0 36 .
18. लेख - मझौली में गोरक्षा - गोधर्म प्रकाश, हिन्दी मासिक, फर्रुखाबाद, 17 जून 1893 (रा0 अभि0 लखनऊ)

देने पर उनको व उनके पुत्र को पदच्युत कर दिया जायेगा ।[20] इस आन्दोलन के कारण बलिया, आजमगढ़ व पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में 1894 में दंगे हुये ।[21]

नवम्बर 1894 में गोरखपुर में 4 बंगाल इन्फैन्ट्री और मुसलमानों में झगड़ा हो गया । जिले के अधिकारियों के सामयिक हस्तक्षेप से इस संघर्ष पर शीघ्र ही नियंत्रण पा लिया गया ।[22] 29 मई 1896 को गोरखपुर में महारानी के जन्मदिन के उपलक्ष में एक सभा का आयोजन किया गया ।[23]

1900 में जामा मस्जिद के पेश इमाम को जामा मस्जिद के प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रार्थना के उत्तर में गोरखपुर मंडल के आयुक्त को सूचित किया गया कि 1863 के एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार सन्देहपूर्ण है और उससे निवेदन किया गया कि भविष्य में जिलाधिकारी स्वयं को मस्जिद के प्रबन्ध से अलग कर लेगा, यह सूचना मस्जिद की प्रबन्ध समिति को दे दी जाय ।[24]

---

20. गोरखपुर के मैजिस्ट्रेट का गोरखपुर के कमिश्नर को पत्र, संख्या 258/16394 पी0पी0 3950, जी0 ए0 डी0, फाइल सं0 730 बी, बाक्स सं0 36 (राज0 अभि0, लखनऊ)
21. त्रिपाठी, आमोदनाथ – पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनजीवन में बाबा राघवदास का योगदान, शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ024
22. जी0ए0डी0 – फाइल नं0 43 सी, बाक्स नं0 47
23. पायनियर – दैनिक समाचार पत्र 29 मई 1896, पृ0 – 5
24. जी0 ए0 डी0, फाइल नं0 106 सी/675, बाक्स नं0 63

27 फरवरी 1897 को 'गोरखपुर' सप्ताह मनाया गया ।[25] 1897 में अकाल के दौरान गोरखपुर के आयुक्त श्री अलेक्जेन्डर द्वारा दूरदर्शिता व चतुराई का परिचय दिया गया । जिन जगहों पर मदद की आवश्यकता थी और जिस सीमा तक थी ; सहायता प्रदान की गयी ।[26]

दस वर्ष तक लगातार गोरखपुर में मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर के रूप में जनता की सेवा करने के बाद डा0 होई का यहां से स्थानान्तरण हो गया । बहुत बड़ी संख्या में लोग विदाई समारोह में शामिल हुये । डा0 होई ने भविष्य में भी यहां के लोगों की मदद करने का आश्वासन दिया ।[27]

1901 में महारानी विक्टोरिया का निधन हो गया । सारे देश में शोक मनाया गया । यहां पर जामा मस्जिद में सभी मुसलमानों ने एकत्र हो कर महारानी की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया । महारानी की मृत्यु पर दुःख व्यक्त करने के लिये एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया तथा महारानी के सचिव, वायसराय और लेफ्टीनेन्ट गवर्नर को संवेदना संदेश भेजे गये ।[28]

कायस्थ सभा द्वारा रानी की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया गया । थियोसोफिकल सोसाइटी की गोरखपुर शाखा, आर्य समाज तथा सनातन धर्म ने भी महारानी की मृत्यु पर शोक सभा का आयोजन किया ।[29]

---

25. पायनियर - समाचार पत्र, 27 फरवरी 1897, पृ0 3
26. पायनियर - समाचार पत्र, 21 दिसम्बर 1897 पृ0 7
27. पायनियर - समाचार पत्र, 23 अक्टूबर 1899 पृ0 5
28. पायनियर - समाचार पत्र - 25 जनवरी 1901, पृ0 5
29. पायनियर - समाचार पत्र - 26 जनवरी 1901, पृ0 4

नवम्बर 1901 में गोरखपुर में शारदीय सप्ताह (Autumn Week) मनाया गया ।[30]

जनरल सर एच0 मोल्ला जोन द्वारा गोरखपुर लाइट हार्स, और बंगाल तथा उत्तरी पश्चिमी रेलवे वालन्टियरों का वार्षिक निरीक्षण किया गया ।[31] फरवरी 1905 में गोरखपुर स्प्रिंगमीट (Spring Meet) का आयोजन किया गया ।[32]

नवम्बर 1905 में गोरखपुर में शारदीय सभा (Autumn Meet) का आयोजन किया गया ।[33]

19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध राजनीतिक राष्ट्रवादी चेतना के फूलने फलने और एक संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्भव और विकास का साक्षी है । देश में नये शिक्षित वर्ग के द्वारा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार और देश में राजनीतिक कार्यकलाप बन्द करने के लिये राजनीतिक संघों की स्थापना की । उस समय तक यह धारणा थी कि जनता अपने शासन के लिए राजनीतिक ढंग से संगठित नहीं हो सकती है । इसी कारण जनता को राजनीतिक दौरे में लाने में आधी शताब्दी से अधिक का समय बीत गया ।[34]

राजनैतिक कार्य शुरू करने के प्रारम्भिक दौर में राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाये गये तरीकों के कारण उनको नरमपंथी की उपाधि दी गयी । ये तरीके छोटे रूप में धीरे - धीरे व्यवस्थित राजनीति प्रगति के लिये स्वयं को संवैधानिक

---

30. पायनियर समाचार पत्र - 7 नवम्बर 1901, पृ0 3
31. पायनियर - 3 मार्च 1902, पृ0 6
32. पायनियर - 25 फरवरी 1905, पृ0 5
33. पायनियर - 10 नवम्बर 1905, पृ0 6
34. विपिनचन्द्र त्रिपाठी, अमलेश एवं दे बरुन - स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 50

आन्दोलन के चौखटे में सीमित रख कर काम थे। उनका मुख्य काम जनता को आधुनिक राजनीति में शिक्षित करना था।[35]

प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवादियों को व्यावहारिक धरातल पर कम सफलता मिली। ब्रितानी शासकों ने उपेक्षा का बर्ताव किया।[36] आन्दोलन की मूलभूत कमजोरी उसके सामाजिक आधार की संकीर्णता में थी। उस वक्त लोग उसके प्रति व्यापक रूप से आकर्षित नहीं हुये थे, उसके प्रभाव का क्षेत्र मुख्यत: शहरों के शिक्षित भारतीयों तक सीमित था।[37]

1885 – 1905 के बीच का समय भारतीय राष्ट्रवादिता के बीजारोपण का समय था। उस समय के राष्ट्रवादियों ने उस बीज को अच्छी तरह बोया।[38]

अपनी कुछ असफलताओं के बावजूद प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन की ठोस नींव रखी। इस पर आन्दोलन का अगला विकास हुआ।[39] उन्होंने व्यापक स्तर पर राजनीतिक चेतना पैदा की।[40] एक ऐसा समान राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसने भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों को एकबद्ध कर दिया।[41]

ब्रितानी साम्राज्यवाद के वास्तविक चरित्र का पर्दाफाश करने में उन्होंने दिशा निर्देशक का काम किया। लगभग सारे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों को भारत की राजनीतिक स्वाधीनता से जोड़ा।[42]

---

35. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश, दे बरून – स्वतंत्रता संग्राम, पृ० 66–67
36. वही – पृ० 74
37. वही, पृ० 68
38. वही, पृ० 77
39. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश एवं दे, बरून, स्वतंत्रता संग्राम पृ० 78
40. वही – पृ० 76
41. वही – पृ० 78
42. वही – पृ० 76

उन्होंने ब्रितानी शासन के चरित्र के, उसके अच्छे आशय और अच्छे परिणाम के बारे में जनमन में बैठे विश्वास को धीरे - धीरे खत्म कर दिया ।[43]

इसमें शक नहीं है कि उनका व्यावहारिक उपलब्धि मामूली था । तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रितानी शासन के चरित्र में परिवर्तन आ जाने के कारण उनकी पूर्व धारणायें और दृष्टिकोण पुराने हो गये थे । यहां तक कि वे देश व्यापी स्तर पर संवैधानिक आन्दोलन चलाने में असफल रहे । युवा वर्ग उनकी ओर आकर्षित नहीं होता था । आम जनता उनके संगठन व प्रचार से अप्रभावित रही । 1905 तक वे राजनीतिक विकास की सीमा पर पहुंच गये थे ।[44]

यदि उनकी अपरिमित कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि नरमपंथी राष्ट्रवादियों की राजनीतिक उपलब्धि सचमुच उतनी धुंधली नहीं है ।[45] उन्होंने भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ की स्थिति को सम्भव बनाया ।[46]

महान नरमपंथी नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा -

"हम यह न भूलें कि हम देश की प्रगति की उस बिंदु पर खड़े हैं, जहां हमारी उपलब्धियां अनिवार्यतः नगण्य और असफलतायें बार - बार की तथा पीड़ा व परीक्षा लेने वाली होंगी । यही वह प्राप्ति है जो हमें नियति की अनुकंपा से इस संघर्ष में मिली है । जैसे ही हम यह काम खत्म करेंगे,

---

43. वही - पृ0 77
44. विपिनचंद्र , त्रिपाठी अमलेश, दे वरुण, स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 75
45. वही - पृ0 75
46. वही - पृ0 76

हमारा दायित्व पूरा हो जायेगा । इसमें शक नहीं कि आने वाली पार्टियों को देश सेवा के कार्य में सफलतायें मिलती रहेंगी । हमें, यानी वर्तमान पार्टी के लोगों को, अपनी असफलताओं के बावजूद उसकी सेवा करके संतुष्ट होना ही चाहिये क्योंकि वे असफलतायें कठोर भले ही हों, शक्ति उन्हीं से फूटेगा जिससे अंततः महान कार्य पूरे होंगे ।"[47]

इस सबके बावजूद यह मानना गलत होगा कि 1885 - 1905 के मध्य हुयी राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का एकमात्र या मुख्य माध्यम कांग्रेस ही था । उस दौर में राष्ट्रीयता को धारदार बनाने या उसे विकसित करने की अनेकों और दिशायें थी । बहुत से स्थानीय और प्रांतीय स्तर के राजनीतिक संगठन राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे । हर वर्ष प्रांतीय सम्मेलन होते थे, जनता उनमें हिस्सा लेती थी ।

राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने राष्ट्रीयता के प्रचार व संगठनकर्ता का काम किया । लगभग सभी बड़े समाचार पत्रों, उस काल के, की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से पहले ही हो चुकी थी । अमृत बाजार पत्रिका, हिन्दू, स्वदेश मित्रम मराठा, केसरी, ट्रिब्यून कोहिनूर मुख्य राष्ट्रीय समाचार पत्र थे । उत्तर प्रदेश से एडवोकेट, हिन्दुस्तानी और आजाद प्रकाशित होते थे ।[48]

---

47. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुन - स्वतंत्रता आन्दोलन पृ0 78

48. विपिन चंद्र, त्रिपाठी अमलेश, दे बरुन - स्वतंत्रता संग्राम पृ0 56

पूर्वी उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता स्वतंत्रता आन्दोलन की गौरव गाथा से महिमा मंडित है । ' जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालों ' के अनुरूप यहां के पत्रकारों ने कार्य किया ।[49]

19वीं शती में गोरखपुर के मझौली राज के महाराज खड्ग बहादुर मल्ल के आर्थिक सहयोग से रेपुरा (बलिया) के निवासी महाराज कुमार रामदान सिंह ने बांकीपुर (पटना) में खड्ग विलास छापा खाना स्थापित किया ।[50] संवत् 1938 में गंगा क्षमा को खड्ग विलास प्रेस से क्षत्रिय का पत्रिका का प्रकाशन महाराज रामदान के संपादकत्व में हुआ । गोरखपुर जनपद के साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विविध क्रिया कलापों के प्रेरणा स्रोत मझौली के श्री लाल खड्ग बहादुर जी ही थे जिन्होंने क्षत्रिय पत्रिका द्वारा हर क्षेत्र में नवीन चेतना का स्वर भर दिया ।

मौखिक व लिखित सूत्रों के अनुसार 19वीं शती तक देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर जनपद से प्रकाशित किसी पत्र का पता नहीं चलता है । यहां नवीन चेतना का संचार बहुत बाद में हुआ, प्रेस की स्थापना भी नहीं हो पायी । - - - - - - - - - - - - - - 19 वीं शती के उत्तरार्द्ध में समाचार संपादन कला का विकास नहीं हुआ । निबन्ध के रूप में ही साहित्यिक ढंग पर घटनाओं का वर्णन पत्रों में प्राप्त होता है । धर्म प्रचार

---

49. तिवारी , डा० अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता, (पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में) पृ० 18 - 19

50. वही, पृ० 14 - 15

समाज सुधार, जातीय भावना, भाषा प्रेम से प्रभावित हो कर पत्र प्रकाशित किये जाते थे ।[51]

19वीं शताब्दी के अन्तिम दो दशकों में स्वतंत्रता के लिये संगठित प्रयास शुरू हो गया था । 1885 में कांग्रेस की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था । परन्तु अभी गोरखपुर में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था । इसका मुख्य कारण पूर्वी प्रदेश की जनता की गरीबी, अशिक्षा तथा सामाजिक पिछड़ापन था ।

---

51. वही, पृ0 23 - 24

'उग्रवाद का काल' {1906 – 1920}

राष्ट्रवादी आन्दोलन की शक्ति और व्यापकता के बावजूद बंगाल विभाजन रद्द नहीं किया गया । सरकार पहले से भी अधिक दमनकारी हो गया । इन दोनों तथ्यों ने विद्रोही मनः स्थिति वाले बेचैन युवकों के दिमाग पर तात्कालिक प्रभाव डाला ।[1] परिस्थितियों ने बड़ी संख्या में उन नेताओं को मैदान में उतार दिया जो अपनी मांगों में आमूल परिवर्तनवादी थे, और जो राष्ट्रवादिता के एक युद्धोन्मुखी रूप में विश्वास करते थे । ये लोग उग्रपंथी कहलाये । नरमपंथियों को शिक्षितों और शहर के मध्य वर्ग के लोगों से समर्थन मिला तथा उग्रपंथियों को निम्न मध्य वर्ग, छात्रों तथा किसानों व मजदूरों से समर्थन मिला ।[2]

आयरलैंड, रूस, मिस्र, टर्की व चीन की जनता के स्वतंत्रता संघर्ष से भारतीय लोगों पर यह सिद्ध हो गया था कि अपने सिद्धान्तों के लिये तकलीफें सहने को तैयार एक संगठित देश सर्वाधिक शक्तिशाली देश तक से संघर्ष कर सकता है ।[3]

उग्रपंथियों के विशिष्ट नेता बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषणों व लेखों से जनता को आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी, निर्भय और निस्वार्थी बनने को कहा ।[4] विपिनचंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविन्द घोष इन सभी उग्रपंथी नेताओं का विचार था कि स्वतंत्रता पाने के लिये भारतवासी स्वयं कार्य करें । स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया । उन लोगों को जन शक्ति में पूरा विश्वास था ।[5]

---

1. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण – "स्वतंत्रता संग्राम" पृ० 93
2. वही – पृ० 79
3. वही – पृ० 81
4. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण – 'स्वतंत्रता संग्राम', पृ० 81
5. वही – पृ० 82

कलकत्ता कांग्रेस (1906) के अवसर पर दादा भाई नौरोजी ने उग्रपंथियों की भावनाओं की प्रशंसा की तथा घोषणा की कि कांग्रेस का उद्देश्य ब्रितानी राज्य या उपनिवेशों की तरह स्वराज प्राप्त करना है।[6]

मुसलमान की शिक्षा, उद्योग व व्यापार में अपेक्षाकृत पिछड़ा था। शासक वर्ग 1858 के बाद से जानबूझकर मुसलमानों के साथ भेदभाव की नीति अपना रहा था।[7] इसके अलावा अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला।[8] 1906 में इस सिद्धान्त को ठोस स्वरूप मिला जब कि आगा खाँ और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया।[9]

बंग भंग के दौरान नरमपंथियों तथा गरमपंथियों में मतभेद काफी बढ़ गये थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल कांग्रेस से अलग हो गया।

1909 का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण वर्ष था। इस समय उदारवादी सरकार द्वारा सुधार लागू किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उग्रवादी देश में स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन का प्रचार करने को तैयार थे।[10] मार्ले मिन्टो सुधार

---

6. वही - पृ0 91
7. वही - पृ0 101 - 102
8. वही - पृ0 103
9. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण - 'स्वतंत्रता संग्राम' पृ0 108
10. गहलोत, बी0 एस0 - "पूर्वी उ0 प्र0 में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास" शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ0 11

द्वारा गवर्नर जनरल तथा प्रान्त सरकारों के कार्यपालिका एवं विधायनी कौंसिल का आकार बढ़ा तथा मुसलमानों के लिये अलग निर्वाचन की व्यवस्था हुआ ; इनका शर्तों से बहुत कम लोगों को संतोष हुआ ।[11] कांग्रेस ने एक दल की हैसियत से सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को अस्वीकृत कर दिया । नरमपंथी तरीकों पर से अधिकांश कांग्रेसियों का विश्वास उठ गया । मार्ले-मिन्टो सुधारों का वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवादी नेताओं को विभाजित करना तथा भारतीयों की एकता की वृद्धि को रोकना था ।[12] 1911 में लार्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तथा भारतीय जनमत को संतुष्ट करने की कोशिश की । बिहार व उड़ीसा बंगाल से अलग कर दिये गये, आसाम एक अलग प्रान्त कर दिया गया । किंग जार्ज पंचम ने 15 दिसम्बर को नयी दिल्ली की नींव रखी, राजधानी दिल्ली ला दी गयी ।[13]

1914 में ब्रितानी महाशक्ति द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से भारत स्वतः उसकी परिधि में आ गया । यद्यपि युद्ध में भारत का अवदान स्वैच्छिक नहीं था, पर काफी बड़ा था । युद्ध पर कुल 12 करोड़ 10 लाख पौंड से अधिक खर्च हुआ । भारत के राष्ट्रीय ऋण में 30% की वृद्धि की गयी । उसके एक बड़े भाग के भुगतान के लिये जनता को मजबूर किया गया ।[14]

---

11. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण -'स्वतंत्रता संग्राम' पृ० 96
12. वही ; पृ० 97 - 98
13. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश, दे बरुण -'स्वतंत्रता संग्राम' पृ० 98
14. वही ; पृ० 110

1915 में गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता के देहावसान तथा तिलक की मांडले से वापसी ने उग्रपंथियों व नरमपंथियों को साथ लाने में सहयोग दिया । श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के सुझाव पर बंबई कांग्रेस ने उग्रपंथियों के लिये दरवाजे कई मामलों में खोल दिये । उन्होंने सितम्बर 1916 में 'होम रूल लीग' की स्थापना की ।[15] 1916 में प्राय: हर पूर्वी जिले में होम रूल लीग की शाखायें थीं ।[16] तिलक अपनी होम रूल लीग के साथ उसमें शामिल हो गये ।[17]

1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुआ लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का प्रारम्भ था ।[18] इस समय सरकार को देश के दो बड़े राजनीतिक दलों के विरोध का, होम रूल लीग के आन्दोलन का सामना करना पड़ा । सरकार ने सुधार व दमन की नीति का आसरा लिया । वायसराय चेम्सफोर्ड ने भारतीय मामलों के मंत्री से सुधारों की घोषणा का आग्रह किया तथा दूसरी ओर गृह विभाग के सदस्य ने नयी बाढ़ को रोकने के लिये बांध खड़ा करने की बात कही ।[19] 15 जून 1917 को मद्रास में एनी बेसेन्ट की गिरफ्तारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में रोष की लहर व्याप्त हो गयी ।[20]

---

15. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण - स्वतंत्रता संग्राम, पृ0 111
16. गहलौत, बी0 एस0 "पूर्वी उ0प्र0 में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास शोध प्रबन्ध-इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ0 15
17. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण -'स्वतंत्रता संग्राम' - पृ0 111
18. गहलौत, बी0 एस0 - पूर्वी उ0 प्र0 में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृ0 17
19. विपिन चंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण, 'स्वतंत्रता संग्राम' पृ0116
20. गहलौत, बी0 एस0 - पूर्वी उ0 प्र0 में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास-शोध प्रबन्ध , इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ0 17

जुलाई 1918 में जब मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तो वह है एक ऐसा भोजन था जिसे कराने से परोसा गया हो पर जिसमें कुछ तत्व न हो।[21] सुधार कार्यक्रम एक के बाद एक चरण में लागू किये जाने थे तथा आगे बढ़ने के लिये हर बार के समय व तरीके का निश्चय ब्रिटिश सरकार करती। व्यवहार में प्रभावकारी अधिकारों का इस्तेमाल अंग्रेज अपने हित में करते।[22]

1905 से 1918 के मध्य क्रान्तिकारी गतिविधियों की जाँच के लिये रौलेट कमेटी नियुक्त की गया।[23] सरकार ने 6 फरवरी 1919 को बड़ी कौंसिल में रौलेट बिल (भाग 2) पेश कर सबको चौंका दिया। यह सरकार को नादिरशाही अधिकार देता था।[24] इस बिल के दो भाग थे - सामयिक व स्थायी। सामयिक भाग भारत रक्षा कानून के उठ जाने से सरकार की जो शक्ति छिन जाती थी, उसकी पूर्ति करता था। स्थायी भाग प्रचलित फौजदारी कानूनों में ऐसे परिवर्तन करता था कि जनता का हक घटकर नहीं के बराबर रह जाता था। सारे देश में इसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ।[25]

इन विधेयकों को काले विधेयकों का नाम दिया गया। गांधी जी ने कहा यदि विधेयक वापस नहीं लिये जाते तो हममें से बहुत लोगों की दृष्टि में सुधार निरर्थक हैं। सरकार से प्रतिकूल उत्तर मिलने पर प्रतिज्ञा जरूर प्रकाशित की जायेगी।[26]

---

21. मिश्र, कन्हैया लाल - उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी, पृ037
22. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण-स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 116-117
23. वही, पृ0 122
24. मिश्र, कन्हैया लाल -'उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी, पृ038
25. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास पृ0 335
26. गांधी, संस्मरण व विचार - प्रकाशित सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली पृ0 - 379-380.

18 मार्च को यह बिल कानून बन गया । उसी दिन गांधी जी ने एक प्रतिज्ञापत्र छपाया । जिस पर हस्ताक्षर करने वाले को इस कानून का उल्लंघन करने की शपथ लेनी होती थी । 30 मार्च को इस कानून के विरोध में भारतव्यापी हड़ताल का आयोजन करने का निश्चय किया गया । बाद में यह तारीख 6 अप्रैल कर दी गयी । सारे देश में हड़ताल रही ।[27] जनता ने उत्साह से भाग लिया पर दिल्ली, अमृतसर, बम्बई अहमदाबाद में उपद्रव हो गये तथा गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया ------- 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नगर में जलियांवाला काण्ड हो गया जहां पर निहत्थे सैकड़ों हिन्दुस्तानी मशीनगन की गोलियों से भून दिये गये ।[28]

पंजाब हत्याकाण्ड को लेकर प्रबल आन्दोलन चला । सरकार को अक्टूबर में हंटर कमेटी नाम से जांच कमीशन बैठाना पड़ा । कांग्रेस ने अपनी कमेटी बैठायी । दोनों की रिपोर्टें यथासमय आयीं । लीपापोती करने पर भी हंटर कमेटी के सामने जनरल डायर ने जो कुछ भी कहा वह यह प्रमाणित करने के लिये काफी था कि यह हत्याकाण्ड पहले से सोचा हुआ था ।[29]

27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आन्दोलन शुरू हुआ । मुस्लिम नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद चाहते थे । अली बन्धु कांग्रेस में आ गये ।[30] 10 मार्च 1920 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि टर्की

---

27. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ0 337
28. मिश्र, कन्हैया लाल - उ0प्र0 स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी पृ0 39
29. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ0 342
30. मिश्रा, डा0 गोविन्द - कांस्टीट्यूशनल डेवेलपमेंट एण्ड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया - पृ0 44

के साथ सन्धि की शर्तें हिन्दुस्तान के मुसलमानों के भावों के विरुद्ध हुईं तो मैं असहयोग आन्दोलन शुरू कर दूंगा ।[31]

1914-18 के महायुद्ध में टर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा था । भारत की मुस्लिम जनता को संतुष्ट करने के लिये लायड जार्ज ने वादा किया था कि वे टर्की पर अधिकार नहीं करेंगे ।[32]

1920 की फरवरी व मार्च में खिलाफत के प्रश्न ने और विराट रूप धारण कर लिया । 19 मार्च को सारे देश में हड़ताल का निश्चय किया गया ।[33]

गांधी जी का असहयोग का कार्यक्रम सर्वप्रथम जनता के सामने 26 जनवरी 1920 को मेरठ में आयोजित खिलाफत कांफ्रेंस में रखा गया ।[34] खिलाफत, पंजाब के अन्याय व स्वराज्य के त्रिसूत्र को ले कर[35] गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आन्दोलन शुरू किया । वायसराय चेम्सफोर्ड को लिखे पत्र में उन्होंने अपनी कैसर -ए- हिन्द की उपाधि त्याग दी । 10 अगस्त 1920 को सेव्रेज की सन्धि द्वारा टर्की साम्राज्य विभाजित कर के बांट दिया गया । गांधी जी ने अपना आन्दोलन शुरू कर दिया । इस तरह कांग्रेस अब गांधी जी के नेतृत्व में एक क्रान्तिकारी संस्था ~~बन~~ हो गयी और जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी ।[36]

---

31. मिश्र, कन्हैया लाल - उ0 प्र0 स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी, पृ0 42
32. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ0 349
33. वही - पृ0 350 - 351
34. गांधी, संस्मरण और विचार - प्रकाशित - सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली , पृ0 453
35. लिमये, मधु - स्वतंत्रता आन्दोलन की विचारधारा - पृ0 103
36. मिश्रा, डा0 गोविन्द -'कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट ऐन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919-47) पृ0 44

6 नवम्बर 1920 को भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा एक राजनीतिक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा असहकारिता के प्रति भारत सरकार के भाव व नीति को फिर से प्रकाशित किया गया। कहा गया कि जनता असहयोग को (स्वराज्य प्राप्ति का) असम्भव व कल्पित उपाय समझ कर स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार करने पर सब जगह गड़बड़ी और राजनैतिक उपद्रव फैला जायेगा, उन सब लोगों को हानि पहुँचेगा जिनका ~~जन कल्~~ को इस देश की उन्नति व अवनति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। असहयोग से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग - फाइल नं0 636, बाक्स नं0 - 132, उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार लखनऊ।)

1905 के बाद से भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन मिला। तिलक ने अपने युवक अनुयायियों के मन को इतना उत्तेजित कर दिया था जो उनसे निजी तौर पर आतंकवादी कार्य कराने के लिये पर्याप्त था।[37] उनका विचार था कि स्वतंत्रता क्रान्तिकारी कार्यों के माध्यम से ब्रिटीश सरकार के अन्दर भय का संचार कर के प्राप्त की जानी चाहिये।[38]

प्रथम क्रान्तिकारी संगठन 1894 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में स्थापित किया गया। 1897 में पहली बार (रैंड की हत्या) राजनैतिक हत्यायें हुयी। चापेकर बंधुओं को मृत्युदण्ड मिलने के बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन सावरकर बंधुओं के नेतृत्व में आया।

---

37. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश, दे बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 93
38. टैरेरिज्म इन इंडिया (1917-1936) कम्पाइल्ड बाई दि इन्टेलीजेन्स ब्यूरो होम डिपार्टमेन्ट आफ इन्डिया।

बंगाल में ब्रिटिश राज को भयंकर चुनौती मिली । बंगाल के समाचार पत्रों ने उत्तेजना फैलाने में बड़ा काम किया । युगांतर संध्या 'वंदेमातरम्' ने क्रान्ति का अजस्र धारा बहा दी ।

1907 में पंजाब में भी किसानों ने नौकरशाही से अनेक मुठभेड़ें कीं । क्रांतिकारियों के सभी कृत्य सुनियोजित और लक्ष्य को सामने रख कर किये गये थे । डकैतियाँ डालना भी क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में शामिल था । 1915 का भारत रक्षा कानून बनने के बाद भी क्रांतिकारी आन्दोलन की गति नहीं रुकी । सैकड़ों युवकों को पकड़ कर जेल में डाला गया ।[39]

1914 तक यह आन्दोलन उत्तर भारत में भी फैल गया । अनुशीलन व युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनोंकेअलावा और भी संगठन स्थापित हो गये थे । उत्तर भारत का नेतृत्व रास बिहारी बोस व शचीन्द्र नाथ सान्याल के हाथों में था ।[40]

प्रथम महायुद्ध के समय पंजाब व बंगाल के क्रांतिकारियों ने मिल कर काम किया ।[41] महायुद्ध समाप्त होने पर देश का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आया । चौराचौरा काण्ड के कारण असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया । 1924 में शचीन्द्र सान्याल ने उत्तर भारत में हिन्दुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की ।[42]

1924 से क्रान्तिकारी आन्दोलन का क्षेत्र बढ़ गया । राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप धारण कर लिया । भगत सिंह व उनके साथियों ने क्रान्ति की लहर दौड़ा दी ।[43]

39. विद्यार्थी, रामशरण व गुप्त, मन्मथ नाथ - भूले बिसरे क्रान्तिकारी पृ09-12
40. वही ; पृ0 12
41. वही ; पृ0 12
42. वही ;, पृ0 14
43. वही ; पृ0 14-15

18 अप्रैल 1930 को जो ज्वाला चटगांव में धधकी थी, वह सारे देश में फैल गया। 1930-34 तक क्रान्तिकारियों ने अनेक हत्याओं के प्रयास किये। 1936 से आगे जनक्रांति का नेतृत्व कांग्रेस ने किया।[44] अपने खतरनाक कामों से, साहसिक योजनाओं तथा गुप्त क्रियाओं व मृत्यु के प्रति निःसंगता के कारण स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में इन आतंकवादियों ने स्थायी जगह बना ली। पर निजी तौर पर किये गये हिंसा के कार्यों ने जनता को संचालित नहीं किया। उनके पास केन्द्रीय नेतृत्व और समान योजना का अभाव था। जनता में आधार नहीं था। गुप्त संगठन होने के नाते जनता को विश्वास पात्र नहीं बना सकते थे। नरमपंथियों ने उन्हें खुले रूप में अस्वीकृत किया तथा उग्रपंथियों ने उन्हें अपनाने में अनिच्छा दिखाया।[45]

प्रायः सभी राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का अनुभव है कि इन आन्दोलनों ने कांग्रेस आन्दोलन के मार्ग में बाधा नहीं खड़ा की, बल्कि शक्तिशाली ही की।[46]

अक्टूबर 1906 में तिलक, लाजपत राय व विपिनचंद्र पाल ने संयुक्त प्रान्त का दौरा किया। 1909 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वदेशी व बहिष्कार का आन्दोलन चल रहा था। गोरखपुर आदि में सार्वजनिक सभायें हुयी। इनका लक्ष्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, शिक्षा का प्रसार व सामाजिक कुरीतियों दूर करना था।[47]

---

44. वही ; पृ0 16
45. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण - स्वतंत्रता संग्राम पृ0 95-96
46. सान्याल, शचीन्द्र नाथ - बन्दी जीवन - पृ0 434
47. गहलोत, बी0 एल0 - पूर्वी उ0 प्र0 में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृ0 - 13

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक बीस वर्षों में तिलक, गांधी, गोखले के नेतृत्व में सारा भारत स्वदेश प्रेम से ओत प्रोत था । तत्कालीन पत्रकारिता का मुख्य स्वर स्वदेश प्रेम था । उस समय गोरखपुर से आनशक्ति (1915), क्षत्रिय (1907), तथा स्वदेश (1919) नामक पत्रिकायें निकलती थीं । आनशक्ति की रचनायें स्पष्ट करती हैं कि 1915 में राष्ट्र प्रेम की लहर किस तरह फैल रही थी ।[48]

सन् 1919 में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा व आदेश पर पं० दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने 'स्वदेश' का प्रकाशन आरम्भ किया । निम्नलिखित पंक्तियों से हर संपादकीय का प्रारम्भ होता था -

"स्वर्ग लाभ के लिये आत्मबलि हमन करेंगे ।"
जिस स्वदेश में जिये, उसी पर सदा मरेंगे ।"

स्वदेश का मूल सिद्धान्त सभी अंकों के मुख पृष्ठों पर प्रकाशित होता था -

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं ।
वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ।[49]

सितम्बर 1920 से 'आज' दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ । निम्नलिखित पंक्तियां 'आज' के प्रकाशन का लक्ष्य स्पष्ट करती हैं -

---

48. तिवारी, डा० अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में) पृ० 51

49. वही - पृ० 59,

"भारत के अभ्युदय के साथ हमारा अभ्युदय
और उसके पतन के साथ हमारा पतन है, यह
बात हमें सदा स्मरण रहता है। - - -राष्ट्रीय
हित हमारा स्वभाव लक्ष्य हैं। मातृचरण
की सेवा ही हमारी उपासना है, वही जननी
और जन्मभूमि ही हमारी उपास्य देवता है।[50]

जलियांवाला बाग काण्ड से देश की सुप्त आत्मा जागृत हो गयी थी। गांधी जी ने 'यंग इंडिया' में 6 से 13 अप्रैल तक सत्याग्रह सप्ताह मनाने का आह्वान किया था। 16 मार्च (1920) को गोरखपुर में शाकिर अली के हाते में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सभा हुयी। 18 मार्च को पुनः एक सभा उसी स्थान पर हुयी जिसमें 19 मार्च को होने वाली हड़ताल के विषय में प्रकाश डाला गया। 19 मार्च को शहर में जबर्दस्त हड़ताल व एक सभा हुयी। इसमें दस हजार लोग थे। सभा में अध्यक्ष मुहम्मद फारूक साहब, अनवर अली साहब, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, शाकिर अली और विन्ध्यवासिनी प्रसाद आदि ने खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन पर प्रकाश डाला।[51]

जुलाई 1920 में कौंसिल के चुनावों के लिये वातावरण बन रहा था। इस सिलसिले में कई सभायें जिले में की गयी।

---

50. तिवारी, डा० अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में) पृ० - 297

51. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक संक्षिप्त परिचय - (गोरखपुर) पृ० 4-5

तिलक की मृत्यु का समाचार मिलते ही यहां पर शोक का वातावरण बन गया । बाजार बन्द हो गये । स्वदेशी प्रेस से एक मातमी जुलूस निकला । शोक सभा की अध्यक्षता श्री हरिशंकर तिवारी ने की । 1अगस्त को अरहज बाजार में बाबा राघवदास की अध्यक्षता में खिलाफत की एक बड़ी सभा हुयी थी जिसमें हिन्दू मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।

28 नवम्बर 1920 को रघुपति सहाय 'फिराक' ने डिप्टी कलेक्टरी के पद से त्यागपत्र दे दिया ।

5दिसम्बर को हुयी सभा में रघुपति सहाय ने गोरखपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की आवश्यकता पर बल दिया तथा विश्वास व्यक्त किया कि गांधी जी के इस नगर में आते-आते इसकी स्थापना अवश्य हो जायेगी ।

12दिसम्बर को खिलाफत प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मौलाना सैयद सुलेमान नक्वी गोरखपुर आये तथा विशाल जन सभा को सम्बोधित करते हुये गांधी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की ।[52]

20दिसम्बर को जिला कांग्रेस अधिकारियों का चुनाव हुआ जिसमें विन्ध्यवासिनी प्रसाद सभापति तथा बाबू नरसिंह दास जी मंत्री चुने गये । इसके बाद जिले में धुआंधार कार्य शुरू हुआ तथा नित्य सभायें व विचार गोष्ठियां आयोजित की जाने लगीं ।[53]

---

52. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय (गोरखपुर) पृ0,5

53. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर, पृ0 5

25 फरवरी को बांसगांव में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गयी। रघुपति सहाय के भाषणों से परेशान हो कर 14 फरवरी 1921 से दो मास के लिये उनके भाषण पर सरकार ने रोक लगा दी।[54]

1911 में शहर में प्लेग का महामारी फैली। इसके आक्रमण से कई दुःखद मौतों की खबर मिली। स्थानीय सरकारी जुबली हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री ए0 एन0 चटर्जी ने विद्यार्थियों के समुदाय में प्लेग के टीके को लोकप्रिय बनाया।[55]

1915 में गोरखपुर टेक्निकल स्कूल के विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण देने के लिये योजना बनायी गयी।[56]

1916 में गोरखपुर में सेन्ट एन्ड्रूज कालेज खोला गया। लेफ्टीनेन्ट गवर्नर जेम्स मेस्टन ने इस अवसर पर यहाँ तीन दिन व्यतीत किये।[57]

अक्टूबर 1917 में 30 वर्षों के बाद रामलीला और मुहर्रम फिर एक साथ पड़े। यह प्रान्त के लिये चिन्ता का कारण हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर लोगों की धार्मिक भावनायें बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती थीं। इस वर्ष भी उपद्रव की संभावना थी, पर कानून व व्यवस्था बनाये रखने वाले अधिकारियों ने नियंत्रण बनाये रखा। पूर्वी जिलों में इस तरह की खबरों से वातावरण असंतोषजनक हो गया था। जहाँ पर झगड़े की सम्भावना थी, वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस भेजी गयी तथा फैजाबाद, बनारस व गोरखपुर में स्थिति से निपटने के लिये सैनिक बल नियुक्त किये गये।[58]

---

54. वही - पृ0 6
55. पायनियर - 13 मार्च 1911, पृ0 7
56. इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट - फाइल नं0 626/1915, बाक्स नं0 45
    उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
57. पायनियर - 9 जनवरी 1916, पृ0 3
58. पायनियर - 9 जनवरी 1918 - पृ0 8

15 अगस्त 1918 को संयुक्त प्रान्त के मुख्य सचिव को पत्र द्वारा (हस्ताक्षर अपठनीय) बताया गया कि इस मंडल में रामलीला व मुहर्रम के सम्बन्ध में उपद्रव का कोई सम्भावना नहीं है। इसमें गोरखपुर के लिये श्री विशेश्वर प्रसाद माँडेक के स्थान पर एक अच्छे हिन्दू कलेक्टर की नियुक्त करने के लिये कहा गया था।[59]

9 अप्रैल 1919 को गोरखपुर मंडल के आयुक्त ने उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकार के मुख्य सचिव को तार दिया कि मंडल में कहीं पर भी अशान्ति नहीं है।[60]

26 मार्च 1919 को रौलेट बिल का विरोध करने के लिये सभा का आयोजन देवरिया में किया गया।[61] 30 मई 1919 की रिपोर्ट के अनुसार सत्याग्रह का जोश कम होने के साथ ही गोरखपुर मंडल में भी राजनीतिक स्थितियां शान्त हो गयी।[62]

24 दिसम्बर 1919 को गोरखपुर में शान्ति के समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आयुक्त ने भाषण दिया तथा युद्ध के दौरान गोरखपुर द्वारा साम्राज्य को जाने वाली मदद का उल्लेख किया।[63]

7/8 मई 1919 को भारत सरकार के सचिव द्वारा संयुक्त प्रान्त की सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया। इसमें कहा गया कि समाचार पत्रों के सम्पादकों को चेतावनी दी जाय कि वे ऐसी कोई खबर न

---

59. जी०ए०डी०, कान्फीडेन्शियल D.O. No. 4299/XV-57 फाइल नं० - 597, बाक्स नं० 130, उ०प्र० राज० अभि० लखनऊ
60. जी०ए०डी०, कान्फीडेन्शियल, गोरखपुर मंडल के आयुक्त का उ०प्र० सरकार के मुख्य सचिव को टेलीग्राम की प्रति, 2848/XV 230 फाइल नं० -262, बाक्स नं० 131, उ०प्र० राज० अभि० लखनऊ
61. जी० ए० डी० - सी०आई०डी० रिपोर्ट-फाइल नं० 262, बाक्स नं० 131 उ० प्र० राज० अभि० लखनऊ
62. वही।
63. पायनियर - 24 दिसम्बर 1919 पृ० 9

जिससे मुसलमानों की भावनाओं (टर्की के सम्बन्ध में) को ठेस पहुंचे ।[64]

31 जनवरी 1920 को पंजाब के अतिरिक्त सचिव द्वारा संयुक्त प्रान्त के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया । इसमें कहा गया कि 1915 के भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत पंजाब में 'स्वदेश' अखबार के आने पर रोक लगा दी गया है ।[65]

13 फरवरी 1920 को गोरखपुर मंडल के आयुक्त ने संयुक्त मे प्रान्त के मुख्य सचिव को सूचित किया कि 'स्वदेश' के संपादक श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी को पंजाब सरकार का आदेश दे दिया गया है ।[66]

14 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के कारण किसी तरह की परेशानी नहीं हुयी । गोरखपुर, आजमगढ़ व बस्ती में सभाओं का आयोजन हुआ । पर लोगों की उपस्थिति कम थी । सरकार का विचार था कि जन साधारण को बिलों के बारे में भ्रामक जानकारी दी जा रही है ।[67]

इस काल में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, उनके मुख्य विषय होते थे - सत्याग्रह - उसके परिणाम, सुधार, कांग्रेस व मुस्लिम लीग, खिलाफत, पंजाब, असहयोग, हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध, स्वदेशी, अकाली आन्दोलन आदि ।[68]

---

64. होम-पुलिस विभाग-गुप्त पत्रावली सं0-867, भारत सरकार के सचिव का संयुक्त प्रान्त के सचिव को पत्र, फाइल नं0 378, बाक्स नं0 36, उ0 प्र0 राज0 अभि0 लखनऊ,
65. होम पुलिस विभाग, गोपनीय-सं0 1002 पंजाब सरकार के अतिरिक्त सचिव का संयुक्त प्रान्त के मुख्य सचिव को पत्र, फाइल नं0 378, बाक्स नं0 36, उ0 प्र0 राज0 अभि0 लखनऊ ।
66. होम पुलिस विभाग-गोरखपुर मंडल के आयुक्त का संयुक्त प्रान्त के सचिव को पत्र - सं0 162406/xx-256, फाइल नं0 378, बाक्स नं036उ0प्र0राज0अभि0ल
67. जी0ए0डी0-गोरखपुर के आयुक्त का संयुक्त प्रान्त के मुख्य सचिव को गोपनीय संख्या-D.O.No. 7970/XV 84. फाइल नं0262, बाक्स नं0131, उ0प्र0 राज0 अभि0 लखनऊ ।
68. सरकारी रिपोर्ट - उ0प्र0 राज0 अभि0 लखनऊ

इन सब घटनाओं के अतिरिक्त इस काल (1906-1920) की सबसे महत्वपूर्ण बात थी भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना व पत्रों के मार्ग पर चल रही थी। उग्रवादी इसके विरोधी थे। ये दोनों धारायें काफी समय तक चलती रहीं। 1920 में गांधी जी के आगमन के बाद कांग्रेस को जन साधारण का समर्थन मिला।[69]

गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने नये युग में प्रवेश किया। इसकी ओर जन साधारण आश्चर्य जनक रूप से आकर्षित हुआ। 1920 में कांग्रेस के ऊपर गांधी जी का नेतृत्व दृढ़ता से स्थापित हो गया।[70]

---

69. बनर्जी, जे0 सी0, 'इंडियन रिवोल्यूशनराज इन कान्फ्रेंस' पृ0 1

70. मिश्रा, डा0 गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवलपमेन्ट एण्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919 - 47) पृ0 - 43

गांधी युग – असहयोग आन्दोलन और उसके बाद की स्थिति (1921–1930)

1921 का असहयोग आन्दोलन भारतीय इतिहास की युगान्तरकारी घटना है। गांधी जी के भारतीय राजनीति के मंच पर प्रवेश करने के बाद घटनायें तेजी से घटीं और देखते देखते पूरा देश असहयोग आन्दोलन की लपेट में आ गया।[1]

उदारवादी इस आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे और 1919 के कानून के अन्तर्गत इन लोगों ने मंत्री तथा उच्च अधिकारी के पद स्वीकार किये। ड्यूक आफ कनाट के भारत आने पर गांधी जी के नेतृत्व में उनके आगमन का बहिष्कार किया गया।[2]

बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आन्दोलन में भाग लिया। राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा था। नये वायसराय लार्ड रीडिंग ने गांधी जी को वार्ता करने के लिये मई 1921 में शिमला बुलाया। इस मुलाकात में 1919 का पंजाब की घटना, खिलाफत आन्दोलन, स्वराज्य और भारत पर अफगान आक्रमण की स्थिति में गांधी जी की नीति के बारे में वार्ता हुयी।

31 जुलाई को गांधी जी ने बम्बई में विदेशी वस्त्रों को जलाने का कार्यक्रम रखा। देश के हर भाग का उन्होंने दौरा किया तथा दौरे के प्रथम तीन महीनों में उन्होंने अदालतों, स्कूलों व कालेजों के बहिष्कार पर जोर दिया।[3]

---

1. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक – संक्षिप्त परिचय – गोरखपुर, पृ० 6
2. मिश्रा, डा० गोविन्द – कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919–47) पृ० 46
3. मिश्रा, डा० गोविन्द – कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919–47) पृ० 47.

1921 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में असहयोग आन्दोलन का व्यापक प्रसार हो गया था। इसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार समर्थकों ने 'शान्ति सभा' तथा 'अमन सभा' का आयोजन करने का निर्णय किया। प्रान्तीय सरकार ने इनको प्रोत्साहन दिया। इन सभाओं में प्रायः सरकारी अधिकारी उपस्थित रहते थे। वे सरकार की नीतियों में अपनी आस्था प्रकट करते थे तथा असहयोग विरोधी प्रस्ताव पास करते थे।[4]

अनेक महत्वपूर्ण नेता जेल में थे, पर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वह इससे होने वाले परिणामों से बचना चाहती थी।[5] संयुक्त प्रान्त में सरकार ने 15 मार्च 1921 को अपनी एक विज्ञप्ति में प्रान्त में व्याप्त अव्यवस्था का एकमात्र कारण असहयोग आन्दोलन बताया और अपनी पूर्व नियोजित दमन नीति को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया।[6]

दिसम्बर 1921 तक असहयोग आन्दोलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर था। 15 जनवरी 1922 को हाटा व पडरौना गंज में श्रीमती शान्ती देवी ने जन सभाओं को सम्बोधित करते हुये पुलिस की दमन नीति की आलोचना की तथा सरकारी कर्मचारियों से सरकार की सेवा से त्यागपत्र देने की अपील की।[7]

31 जनवरी 1922 को कांग्रेस कार्यसमिति ने बारडोली को करबन्दी सत्याग्रह करने की अनुमति दी और देश को यह निर्देश दिया कि वह बारडोली के साथ सहयोग करें।[8]

4.. पायनियर 5 जनवरी 1921 - पृ0 11

5. वही ; पृ0 48

6. इंडियन एनुअल रजिस्टर 1921-22 पृ0 21

7. गुप्तचर विभाग के अभिलेख

8. मिश्र, कन्हैया लाल - उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी पृ0 50

इस निर्णय के पांच दिन बाद 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रान्त में गोरखपुर से 15 मील दूर चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसा की घटना हो गयी। एक स्थानीय पुलिस अफसर द्वारा कुछ कांग्रेसी सत्याग्रहियों को मारा पीटा गया। इससे उत्तेजित हो कर कुछ सौ स्वयंसेवकों ने पुलिस थाने पर आक्रमण कर वहाँ उपस्थित 22 पुलिस वालों को जला कर मार डाला। भीड़ ने थाने में आग लगा दी और जो लोग गर्मी व धुयें से घबरा कर बाहर निकल आये, उनको वापस थाने में ढकेल दिया गया।[9]

'लीडर ने लिखा' योजनाबद्ध होकर पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, पुलिस वालों को निर्दयतापूर्वक जला कर मार डाला गया।[10]

इस घटना पर भारत की विधान सभा तथा 14 मार्च 1922 को हाउस ऑफ कामन्स में बहस हुयी। कर्नल सी0 याटे ने कहा ---------- गांधी के स्वयंसेवकों के नेतृत्व में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को तेल छिड़क कर जला कर मार डाला।[11]

इस घटना से दुःखी हो कर गांधी जी ने 6 फरवरी 1922 को असहयोग आन्दोलन को अनिश्चित काल के लिये - देश में पूर्ण अहिंसक वातावरण स्थापित होने तक स्थगित करने का निर्णय ले लिया। 1922 की 11-12 फरवरी को बारडोली में आहूत कांग्रेस कार्य समिति ने आन्दोलन के स्थगन का प्रस्ताव पारित किया जिसकी पुष्टि 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी बैठक में कर दी।[12]

---

9. बक्शी, डा0 एस0 आर0 - 'गांधी एन्ड नान कोआपरेशन मूवमेन्ट' 1920-22 § पृ0 221

10. 'लीडर'- 8 फरवरी 1922

11. बक्शी, डा0 एस0 आर0 - गांधी एन्ड नान को आपरेशन मूवमेन्ट §1920-22§ पृ0 221

12. बम्फोर्ड, पी0 सी0 - हिस्ट्रीज आफ दि नान को आपरेशन एन्ड खिलाफत मूवमेन्ट्स - पृ0 70

चौरा चौरा काण्ड के पहले भी कई हिंसात्मक घटनायें हो चुकी थी। पर इस काण्ड ने गांधी जी को अन्तिम चेतावनी दी। गत नवम्बर में मुझे बम्बई में मनुष्य के जंगलीपन का साक्षात्कार हुआ, पर तब भी मुझे सबक नहीं मिला। अब चौरा-चौरा ने मुझे शिक्षा दी। गोरखपुर से चेतावनी मिलने के बावजूद अगर हम आन्दोलन जारी रखते तो जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता और सत्य तथा शान्ति की बदनामी होती।[13]

यह निर्णय कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिये अप्रत्याशित था। आन्दोलन अचानक स्थगित किये जाने से अधिकांश नेताओं में असंतोष था।[14] सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक भारतीय संग्राम में लिखा "ऐसे समय जब कि जनता का जोश सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच चुका था, पीछे लौटने का नारा राष्ट्रीय संकट से कुछ कम न था।"

13 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये, उन्हें छः वर्ष की सजा दी गयी। सारे आन्दोलन की जिम्मेदारी - विशेषकर चौरी चौरा की उन्होंने अपने ऊपर ले ली।[15]

इस तरह असहयोग आन्दोलन अपने उद्देश्य नहीं पा सका। टर्की में कमाल अता तुर्क के आने के बाद खिलाफत आन्दोलन भी समाप्त हो गया। टर्की में गणतंत्र की स्थापना हो गयी। 24 मार्च 1924 को यह खबर भारत में पहुंची और धीरे-धीरे यह आन्दोलन समाप्त हो गया।[16] अब मुसलमान लोग राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग होने लगे।[17]

---

13. सम्पूर्ण गांधी वांङमय प्रकाशन विभाग भारत सरकार, पृ0 446
14. मिश्रा, डा0 गोविन्द - दी कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया {1919-47} पृ0 48
15. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास पृ0 370
16. मिश्र, डा0 गोविन्द - कांस्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया {1919-47} पृ0 49
17. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ0 372

चौरा चौरा केस के सिलसिले में सैकड़ों लोगों पर मुकदमा चलाया गया । 172 लोगों को फांसी की सजा दी गयी । पं० मदन मोहन मालवीय ने हाईकोर्ट में अपील की, इसके परिणाम स्वरूप एक साल तीन महीने के मुकदमे के बाद हाईकोर्ट में 19 आदमियों को फांसी तथा 14 को आजन्म काले पानी की सजा हुयी । कई लोगों को पांच और तीन साल की सजायें हुयीं । मुकदमेके दौरान 232 लोगों का चालान हुआ, 228 सेशन के सुपुर्द किये गये । इसमें दो बाद में मर गये तथा एक पर से मुकदमा उठा लिया गया । सेशन को 172 को फांसी की सजा दी । हाईकोर्ट ने 19 की सजा बहाल रखी, 38 को छोड़ दिया, 3 को दंगे के जुर्म में दो- दो वर्ष सख्त कैद, 14 को काले पानी की, शेष को 8,5 और 3 वर्ष की सजा दी गयी । 30 अप्रैल 23 को यह फैसला दिया गया । पहली जुलाई को वायसराय ने फांसी पाने वाले सत्याग्रहियों की दया की अपील खारिज कर दी । 2 जुलाई को सभी को फांसी दे दी गयी । इसमें 3 व्यक्ति इटावा जेल में थे । खद्दर के कफन में लिटा कर सभी शहीदों का अंतिम संस्कार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया ।[18]

अब सत्याग्रह का वातावरण बदलने लगा और लोग रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख हुये ।[19]

1920-22 में संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध में किसान आन्दोलन चला । यह साम्राज्य विरोधी व सामन्त विरोधी था । फसल मारे जाने के साथ अकाल और महामारी ने राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ मिल कर गरीब किसानों को हथियार उठाने की प्रेरणा दी । जनवरी 1921 तक प्राय: सभी जिलों में किसानों में अशान्ति थी । असहयोग आन्दोलन की भी प्रधान

---

18. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर पृ० 12
19. वही; पृ० 13

शक्ति यहां के किसान थे। कांग्रेस के स्वयंसेवक दल में हजारों की संख्या में भरती हो कर उन्होंने पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन को शक्तिशाली बनाया था, फरवरी 1922 में यह आन्दोलन संयुक्त प्रान्त के उत्तरी पूर्वी भाग में फैला था।

ब्रिटिश शासकों ने कठोर कदम उठाकर किसानों के आन्दोलन को दबाया।[20] सरकार ने किसान आन्दोलन की गम्भीरता को समझा और किसान सम्बन्धी कानून शीघ्र ही पास किया। संयुक्त प्रान्तीय परिषद में वित्त सदस्य सर लुडोविक पोर्टर ने 4 अगस्त 1921 को एक अधिनियम पेश किया। वर्ष के अन्त तक इसने कानून का रूप दे दिया गया।[21]

इस अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम द्वारा किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसमें बेगार व नजराना रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार से ताल्लुकेदारों को सुविधा मिलती रही, पर किसानों के हितों की उपेक्षा की गयी। किसानों की कठिनाइयां बरकरार रहीं। किसानों का असन्तोष कायम रहा, प्रायः किसान सभायें होती रहीं। कांग्रेस द्वारा चलाये गये आन्दोलनों में भाग लेकर ताल्लुकेदारों और सरकार के कुशासन के विरुद्ध अपना असन्तोष प्रकट किया।[22]

---

20. सिंह अयोध्या - भारत का मुक्ति संग्राम, पृ0 426
21. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यूनाइटेड प्राविन्सेज (1921-22)
22. डॉ0 एस0 गहलौत - पूर्वी उ0 प्र0 में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ0 29

7, 8, 9 जून 1922 को लखनऊ में कांग्रेस में महासमिति की बैठक में पं० मोती लाल नेहरू ने कहा 'हम ऐसा असहयोग चाहते हैं जिसका प्रवेश द्वारा नौकरशाही के गढ़ में हो सके'। यह कौंसिल प्रवेश की भूमिका थी। सी० आर० दास व मोती लाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में भाग लिया तथा बड़ी सफलता पायी।[23]

स्वराज्य पार्टी की ओर से पं० मोती लाल नेहरू ने केन्द्रीय धारा सभा में राष्ट्रीय मांग पर एक प्रस्ताव पेश किया जिसका अर्थ था औपनिवेशिक स्वराज्य के ढांचे पर शासन विधान बनाने के लिये गोल मेज सम्मेलन बुलाया जाय। स्वराज्य पार्टी के कारण देश में जोश का वातावरण बना रहा। सुभाष बाबू ने लिखा है - स्वराज्य पार्टी के लोगों के मन में गांधी जी के लिये अधिक से अधिक सम्मान था, पर यह पार्टी स्पष्ट रूप से गांधी विरोधी थी और यह इतनी तगड़ी थी कि इसने गांधी जी को इच्छापूर्वक राजनीति से बैठ जाने को मजबूर किया। 1928 के कलकत्ता कांग्रेस तक उन्हें बैठे रहना पड़ा।[24]

इस समय हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्ध बिगड़ते रहे। 1922 के असहयोग आन्दोलन के बाद साम्प्रदायिक दंगों का जो तूफान उठा, उसमें काकोरी काण्ड ही एकमात्र राजनीतिक विस्फोट है जिसने जनता का ध्यान साम्प्रदायिकता से हटा कर फिर राजनैतिक प्रश्न देश की गुलामी की तरफ खींचा। इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला जैसे उद्भट वीर सामने आये और देश की नयी पीढ़ी को देशभक्ति की ताजी प्रेरणा दी

---

23. मिश्र, कन्हैया लाल - उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी, पृ० 60
24. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ० 373-374
25. मिश्र, कन्हैया लाल- उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी, पृ० 64

बाद में 18 दिसम्बर 1927 को शहादत प्राप्त करके श्री बिस्मिल ने गोरखपुर जेल को अमर बना दिया।[26]

1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू किये गये मांटिग्यू चेम्सफोर्ड शासन सुधारों की प्रस्तावना में कहा गया था कि इन सुधारों में घटा-बढ़ी की जांच के लिये दस वर्ष बाद सरकार एक कमीशन कायम करेगा और उसकी रिपोर्ट परपार्लियामेन्ट विचार करेगा। 8 नवम्बर 1927 को हिन्दुस्तान में यह घोषणा की गयी कि एक कमीशन (अध्यक्ष के नाम पर उसका नाम पड़ा 'साइमन कमीशन') हिन्दुस्तान आयेगा और 3 फरवरी 1928 को वह बम्बई आ पहुंचा।[27] इसकी नियुक्ति 1929 में होनी चाहिये थी। परन्तु इसे दो वर्ष पूर्व ही गठित कर दिया गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत में व्याप्त साम्प्रदायिक उत्तेजना से लाभ उठाना चाहती थी। अनुदार दल भारत का भविष्य मजदूर दल के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था। एक कारण जवाहर लाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में चल रहा युवा आन्दोलन भी था।[28]

कमीशन की नियुक्ति ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और पूरे देश में विरोध और असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी। सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ खड़े होकर कमीशन का विरोध किया। कांग्रेस ने हर स्थिति में साइमन कमीशन के विरोध का निश्चय किया। 1922 में चौरी चौरा काण्ड के बाद असहयोग आन्दोलन समाप्त होने के बाद यह

---

26. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर, पृ0-13
27. मिश्र, कन्हैया लाल - उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी, पृ0 70
28. डा0 एस0 गहलौत, पूर्वी उ0 प्र0 में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास-शोध प्रबंध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ0 58

आन्दोलन ब्रिटिश सरकार के लिये खुला चुनौती था । हर स्थान पर इस कमीशन का बहिष्कार किया गया । 'साइमन वापस जाओ' के नारे से उसका स्वागत किया गया । पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया । बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बस्ती में जन सभायें सम्बोधित की गयी तथा साइमन कमीशन की कटु आलोचना की गयी ।[29] तमाम विरोधों के बावजूद साइमन कमीशन ने अपना कार्य पूरा किया और प्रथम गोल मेज सम्मेलन के पहले 5 सितम्बर 1929 को 'साइमन रिपोर्ट' प्रकाशित की गया ।[30]

भारत राज्य सचिव लार्ड बरकेन हेड द्वारा लगाये गये अक्षमता के आरोप का जवाब देने के लिये 1928 में दिल्ली व बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया । सभी दल इस बात पर सहमत थे कि पूर्ण उत्तरदायी शासन को आधार मान कर ही भारत की वैधानिक समस्या पर विचार किया जाना चाहिये । 19मई 1928 को पं0 मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी जो पूर्ण उत्तरदायी शासन को आधार मान कर हिन्दुस्तान की हुकूमत का ढांचा तैयार करे और अपनी रिपोर्ट 1जुलाई 1928 तक कांग्रेस को दे । इस रिपोर्ट में डोमीनियन स्तर की प्राप्ति को तत्काल लक्ष्य और पूर्ण स्वराज्य को अगला लक्ष्य बताया गया । अलग निर्वाचन का विरोध किया गया तथा कुछ माह बाद मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया ।[31]

---

29. लीडर - 28 जनवरी 1928 पृ0 11
30. मिश्रा, डा0 गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवलेपमेन्ट एण्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919 - 47) पृ0 56-57-58,
31. मिश्र, कन्हैया लाल - उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम का एक झांका । पृ0 74 - 75

काफी समय बाद गांधी जी कांग्रेस में सक्रिय हुये। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया। इस कांग्रेस में (कलकत्ता कांग्रेस) यह प्रस्ताव भी पास हुआ कि यदि ब्रिटिश संसद 1929 के 31 दिसम्बर तक सर्वदल सम्मेलन की मांग को पूर्ण रूप से मान ले तो ठीक है। पर यदि इसके पहले या इस तारीख तक मांग न मानी जाय तो कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोग, टैक्स बन्दी तथा अन्य उपायों को ग्रहण करेगी।[32]

अंग्रेजी सरकार ने नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया इसलिये 31 दिसम्बर की रात 12 बजते ही रावी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में यह प्रतिज्ञा दोहराया गया। इसके अन्त में कहा गया हम ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा व करबन्दी तक के साज सजायेंगे।[33]

1930 के प्रारम्भ में देश में चारों ओर राजनीतिक उत्तेजना का वातावरण था। इस बात के चिन्ह थे कि यदि महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आन्दोलन शुरू नहीं किया होता तो दयनीय आर्थिक दशा तथा कठोर नौकरशाही के कारण भारत में हिंसात्मक क्रान्ति का सूत्रपात हो जाता। फरवरी की 14,15,16 ता0 को साबरमती में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से आन्दोलन शुरू करने की घोषणा की। 12मार्च से उन्होंने आश्रम के 79 कार्यकर्ताओं के साथ डांडी मार्च शुरू किया तथा अपने कार्यक्रम के

---

32. गुप्त मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ0 386
33. मिश्र, कन्हैया लाल - उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी, पृ0 75

अनुसार 5 अप्रैल को समुद्र के जल से नमक बना कर कानून तोड़ा । सरकार का दमन चक्र शुरू हो गया । 5 मई को गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये ।[34]

इलाहाबाद में कार्य समिति की बैठक में नमक सत्याग्रह जारी रखने, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने, लगान बन्दी, चौकीदारी टैक्स न देना आदि का निश्चय किया गया । लार्ड इर्विन द्वारा आर्डिनेन्स से प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गयी । प्रतिवाद स्वरूप कई समाचार पत्रों ने प्रकाशन बन्द कर दिया । जून के अन्त में कांग्रेस कार्य समिति भी गैर सरकारी घोषित कर दी गयी । इस समय गिरफ्तारी, गोली चलना, लाठी चार्ज आम बात हो गयी थी ।[35]

1930 का वर्ष नाटकीय घटनाओं से पूर्ण था । सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60,000 तथा कांग्रेस के अनुसार 90,000 लोग गिरफ्तार किये गये थे । नमक कानून तोड़ने के कारण कई प्रमुख नेता गिरफ्तार किये गये । उच्च व मध्यम वर्ग की महिलाओं ने आन्दोलन में भाग लिया ।

आम तौर पर 1930 का आन्दोलन अहिंसक था । कभी-कभी कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों में झगड़े हुये ।[36]

संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने आन्दोलन का दमन करने के लिये कठोर नीति अपनायी (सत्याग्रह समाचार) सविनय अवज्ञा के उत्तेजना पूर्ण वातावरण में संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 18-21 अप्रैल 1930 को कानपुर में हुआ । इसमें यह निश्चित किया गया कि यदि नया कानून समाप्त किया जायेगा तो भी स्वतंत्रता न मिलने तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी रहेगा ।[37]

---

34. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ0 397-398,
35. वही, पृ0 399-400,
36. मिश्र, डा0 गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919 - 1947) पृ0 87
37. **Indian Annual Register** भाग - 1 (1930) पृ0 344

12 नवम्बर 1930 को कथित गोल मेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। यह सम्मेलन किसी मतलब का नहीं था।[38] सविनय अवज्ञा आन्दोलन सफलतापूर्वक चल रहा था। इर्विन की दो तरह की प्रतिक्रिया हुयी। वह नये-नये अध्यादेश स्वीकृत कर आन्दोलन को पूरी शक्ति से दबाना चाहते थे, साथ ही किसी सम्मान जनक समझौते के लिये भी प्रयत्नशील थे।

गोरखपुर जिले में असहयोग आन्दोलन की नींव 1920 में पड़ी और 8फरवरी 1921 में गांधी जी के प्रथम आगमन से इसे बड़ी प्रेरणा मिली।[39] 8 फरवरी 1921 को गांधी जी गोरखपुर आये। यहां पर उनके साथ मौलाना मुहम्मद अली भी थे। बाले मियां के मैदान में एक लाख लोगों की विशाल सभा को सम्बोधित किया और स्कूल, अदालत तथा सरकारी सेवा के बहिष्कार की अपील की।[40] यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वयं को राष्ट्रीय स्वयं सेवक कहा और सारे जिले से लोगों को इसमें शामिल किया गया। जिले के हर कोने में सभाओं का आयोजन किया गया। रोज जुलूस निकाले जाते थे। शराब की दुकानों पर धरना दिया जाता था। ताड़ के पेड़ जिनसे ताड़ी बनायी जाती थी और ब्रिटिश सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती था, काट डाले गये। विदेशी सामान का बहिष्कार तथा विदेशी कपड़ों की होली सार्वजनिक रूप से जलायी जाती थी। हाथ के बने खादी के कपड़ों का प्रयोग होता था।[41]

---

38. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ0 403,
39. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एन्ड अवध - सप्लीमेन्टरी नोट्स एन्ड स्टैटिस्टिक्स अप टू 1931-32 **Vol. XXXI (D)** गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट (इलाहाबाद 1935) पृ0 24
40. आज 11 फरवरी 1921, पृ0 4
41. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर गोरखपुर (1985) पृ0 40

असहयोग की आवाज बुलन्द करने वालों में बाबा राघवदास और उर्दू शायर रघुपति सहाय 'फिराक' प्रमुख थे।[42] बाबा राघवदास द्वारा कांग्रेस की जो विशिष्ट सेवा की गयी, उससे प्रभावित हो कर गांधी जी ने कहा था यदि उनके जैसे थोड़े से सन्त हमें मिल जायें तो स्वराज्य हमारे आगे हाथ बांधे खड़ा हो जाय।[43] इसके अलावा बाबू त्रिवेणी सहाय, विन्ध्यवासिनी प्रसाद श्रीवास्तव, बाबू नरसिंह दास, मौलवी सुभानउल्लाह, प्रभात कुसुम बनर्जी, डा० विश्वनाथ मुकर्जी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, भगवती प्रसाद दूबे ने देश के लिये हर प्रकार का त्याग व बलिदान किया।[44]

13 अप्रैल 1921 को जलियां वाला बाग की स्मृति में गोरखपुर की सड़कों पर 15000 व्यक्तियों का विशाल जुलूस निकला। सभी व्यक्ति नंगे पैर व नंगे सिर थे। 30अप्रैल 1921 को लप्पा लाल पटवारी को असहयोग का प्रचार करने के कारण 9 मास की सजा हुयी। इस समय यहां पर 'स्वदेश' एकमात्र ऐसा पत्र था जो पूरी शक्ति से असहयोग आन्दोलन का समर्थन कर रहा था।[45] 10 अप्रैल 1921 के संपादकीय लेख में कहा गया -------- अब तक 'स्वदेश' का नाम स्वदेश रखना हमारी धृष्टता थी। परन्तु ईश्वर ने चाहा तो हम इस वर्ष 'स्वदेश' का नाम स्वदेश सार्थक कर के ही छोड़ेंगे क्योंकि स्वराज्य स्थापित होने पर ही हम अपने देश को स्वदेश कह सकेंगे और वही दिवस स्वदेश का सौभाग्य दिवस होगा।[46]

---

42. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर, पृ० 6
43. बाबा राघवदास स्मृति ग्रन्थ - पृ० 17
44. स्वतंत्रता संग्राम के के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर, पृ० 6
45. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक संक्षिप्त परिचय,गोरखपुर, पृ० 7
46. तिवारी, डा० अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता {पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में} पृ० 60

राष्ट्रभक्तों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत बड़ा जत्था 'स्वदेश' ने तैयार किया । 'स्वदेश' के प्रथम अग्रलेख से इसका स्वरूप पता चलता है ---- पाठक आप ही सोचें, ऐसा कौन सा वज्र हृदय होगा जो हमारी इस अधोगति दशा को देख कर आंसुओं की झड़ी न बांध दे । ---- हमारे राष्ट्रीय जीवन की धारा पहले की अपेक्षा बहुत म्लान, क्षीण, संकीर्ण और मंद हो गया है । ----- पवित्र भारत माता की वेदी पर सब मत और मतांतर के लोग दत्तचित्त हो कर जिस चीज के लिये अड़ जायेंगे, उसे वे अवश्य प्राप्त करेंगे ।[47]

25 नवम्बर 1928 के अपने अंक में 'स्वदेश' ने लाला लाजपत राय की मृत्यु को मुखपृष्ठ पर प्रकाशित किया तथा देशवासियों से 29 नवम्बर को 'लाजपतराय दिवस' मनाने की अपील की ।[48]

जमानत और तमाम परेशानियों को झेलते हुये 1919 से 1938 तक 'स्वदेश' पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वदेश की बलिवेदी पर सेनानियों को प्राणोत्सर्ग करने की शिक्षा देता रहा ।[49]

विजयांक में प्रकाशित अनूप शर्मा की पंक्तियां राष्ट्रप्रेमियों के लिये प्रेरणा शक्ति बन गया था -

क्रान्ति की उषा से होगा रक्त भारतीय व्योम
ताव भरा देह का तरणि तमके ही गा ।
भारी राजनीति के उदधि से उभारने को,
चारु कालचक्र चन्द्रमा सा चमके ही गा ।
वैरियों का दमन शमन होगा शक्ति ही से
युद्ध घोषणा को कोई धर धमके ही गा ।
कायरों ! क्यों लेते हो कलंक को अकारथ ही,
भारत के भाग्य का सितारा चमके ही गा ।[50]

---

47. वही, पृ० 60; 62
48. वही, पृ० 65
49. वही, पृ० 66
50. पुलिस विभाग, फाइल नं० 411, बाक्स नं059, 1980 रामनगर, अभिलेखागार

इसके अतिरिक्त 'भावी क्रान्ति', 'विजय', 'विप्लव राग' और 'माँ' अत्यधिक आपत्तिजनक थे ।[51]

<u>विजय</u> (पं० रामचरित उपाध्याय)

विजय की फिर हो जय जयकार ।
अवधि निकट अवशेष खड़ी है, करिये विकट विचार ।।
अति अद्भुत अवतार लीजिये समयोचित इस बार ।
वे त्रेता के असुर रहे, ये कलि के कपटागार ।
अबकी जाना नहीं पड़ेगा, राम जलधि के पार ।
असुरों का भरमार यहीं है हरिये भू के भार ।।
बाकी कौन रहा भारत में भीषण अत्याचार ।
शीघ्र क्रोध - हुंकार सहित प्रभु करिये धनु टंकार ।
जो उदार बने असुरों से वे हैं देश कुठार
राम भरोसा रहा आपका करिये देशोद्धार ।
बातों से सुधार क्या होगा सुनो विजय का सार ।
फिर दुलार भारत का करिये कर के अरि संहार ।

<u>विप्लव राग</u>

<u>माँ</u> (श्री रामनाथ 'सुमन')

माँ ! अपनी आँखों से क्यों है गूँथ रही नन्हीं बूँदें ।
तू छींट दे, आग जला, धध धध लपटें अम्बर छू दें ।
वे नृशंस दर्शन से ही मर जायें बस आँखें मूँदे ।
अत्याचारी वधिक विदेशी छाती पर न अधिक कूदें ।
एक बार माँ ! एक बार तू नाच काम बन जायेगा ।
ताण्डव का बस एक कला में खल पात्र भर जायेगा ।

---

51. पुलिस विभाग, फाइल नं० 411, बाक्स नं० 59, उ०प्र० रा० अभि०, लखनऊ।

निश्चय ही नौकरशाही की क्रूर दृष्टि को झेलते हुए 'स्वदेश' ने जो सेवा युक्त प्रान्त की, की वह अविस्मरणीय है। 1919-1937 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की साहित्यिक व राजनीतिक गतिविधियों का 'स्वदेश' नियामक था।[52]

'स्वदेश' के अतिरिक्त 'आज' दैनिक पत्र ने पूर्वांचल में स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशानुसार स्वराज्य प्राप्ति, अधिकार बोध एवं धर्म बुद्धि से कर्तव्य पालन इन तीनों के लिये 'आज' सदैव जनता का आह्वान करता रहा।[53]

'आज' का सत्संकल्प निम्न पंक्तियों से स्पष्ट होता है -

> स्मरण रखिये, जलियां वाला बाग दिवस है।
> अपना कर्तव्य पालन कीजिये।
> कार बार बन्द रखिये, उपवास कीजिये,
> ईश्वराधन कीजिये, राष्ट्र कार्य को करने में
> दृढ़ प्रतिज्ञा सत्यसंकल्प होइये।[54]

इस तरह पत्रकारिता स्वतंत्रता आन्दोलन को बढ़ावा दे रही था। भाषण देने पर रोक लगाने के बावजूद कानून का उल्लंघन कर भाषण दिये जाते थे और कड़ी से कड़ी सजा सहर्ष स्वीकार की जाती रघुपति सहाय, ब्रम्हदेव शर्मा, हनुमान प्रसाद पोद्दार, अंगूर त्रिपाठी आदि ऐसे ही नेता थे।

52· तिवारी, डा0 अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ0 प्र0 के सन्दर्भ में) पृ0 89-90

53· वही, पृ0 297

54· 'आज' 13 अप्रैल, 1922

17 सितम्बर 1921 को नेहरू जी देवरिया आये । आते ही धारा 144 लगा दी गयी । यह स्थिति रामपुर (हाटा) शिकारपुर (गोरखपुर) में भी रही । गोरखपुर में 12,000 आदमियों की सभा में नेहरू जी ने एक घन्टे तक सभी विषयों पर प्रकाश डाला ।[55]

नेहरू जी के आने के बाद से जिले का वातावरण और गर्म हो गया । सभाओं में जनता की उपस्थिति बढ़ने लगी ।[56]

जिले में शासन का साथ जिले के प्रमुख जमींदार तथा अन्य सरकार परस्त लोग देते थे, इस कारण कार्यकर्ताओं तथा सामान्य लोगों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे ।[57]

चौरी चौरा काण्ड के पहले गोरखपुर के सत्याग्रहियों ने अच्छे संगठन व विश्वास का परिचय दिया था । यहाँ एक ऐसा जिला था जिसमें कांग्रेस नीचे से ऊपर तक पूर्ण व मजबूत था । तहसील व मण्डल स्तर तक कमेटियां बन गया था । विधिवत ताड़ी शराब, गांजा तथा विदेशी कपड़ों की दुकान पर सत्याग्रह शुरू किया गया था ।

इस सिलसिले में सहजनवां और चौरीचौरा दो प्रमुख बाजारों में सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया गया ।[58] फरवरी 1922 को चौरीचौरा से जुड़े मुन्देरा बाजार में शान्ति पूर्वक धरना दिया गया । चौरीचौरा पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर द्वारा स्वयं सेवकों को मारा पीटा गया । फलत: 4 फरवरी 1922 को जिला मुख्यालय से 15 मील पूर्व में डुमरी नामक

---

55. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर, पृ0 7-8
56. वही - पृ0 8
57. वही - पृ0 8
58. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर, पृ0 11

स्थान पर स्वयं सेवकों का विशाल सभा को स्थानीय नेताओं ने सम्बोधित किया । इसके बाद यह जुलूस चौरी चौरा की ओर बढ़ा । 5फरवरी को वहां पहुंचकर जुलूस थाने के आगे रूक गया । पुलिस अफसर के व्यवहार का स्पष्टीकरण मांगा गया । पुलिस ने उन पर गोली चलायी । जवाब में उन पर पत्थर फेंके गये । गोली काण्ड में 26 लोग मरे । पुलिस का गोली खत्म हो जाने पर स्वयं सेवकों के थाना घेर लिया । पुलिस वाले थाने के अन्दर छिप गये, उत्तेजित स्वयं सेवकों ने थाने में आग लगा दी । 21 पुलिस कर्मचारी तथा एक सब इंसपेक्टर अन्दर जलकर मर गये ।

225 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । पुर्दाबनी तथा पं० मदन मोहन मालवीय की कानूनी लड़ाई के बाद 19 लोगों को फांसी की सजा दी गया । इसके पहले 100 लोगों को फांसी की सजा सुनायी गया था ।[59]

आन्दोलन स्थगित हो गया । हिंसा का कलंक लेकर इस क्षेत्र के लोग महीनों वर्षों तक अनेक प्रकार के कष्ट व अत्याचार सहते रहे ।[60] चौरी चौरा काण्ड के विषय में कई मत हैं । सत्याग्रह आन्दोलन के नेता द्वारिका प्रसाद पाण्डे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी, के अनुसार संघर्ष की शुरूआत पुलिस ने की था । इसमें 26 स्वयंसेवक मरे तथा सैकड़ों घायल हुये । पुलिस ने 23 लाशें गायब करा दी तथा मुकदमें के दौरान केवल तीन स्वयं सेवकों की मृत्यु को स्वीकार किया गया । सरकारी विवरण इस कथन की पुष्टि नहीं करते ।[61]

---

59. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ गोरखपुर - 1985 - पृ० 40-41
60. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर, पृ०-12
61. उत्तर प्रदेश {मासिक पत्रिका} सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश - अक्टूबर 1972 - पृ० 25

इस काण्ड के एकमात्र बचे सिपाही साबिक अहमद का मत है मुंदेरा बाजार में मादक द्रव्यों की दुकान पर धरना दिया गया। थाना अध्यक्ष अहमद व एक अन्य सिपाही वहां गये तथा एक स्वयंसेवक को पीटा - 13 फरवरी को अफवाह थी कि 5 फरवरी को जन समूह थानाध्यक्ष से इस घटना के बारे में पूछेगा कि उन्होंने स्वयंसेवक को क्यों पीटा। थानाध्यक्ष ने मुख्यालय से मदद मांगी जो कि 4 फरवरी को ही आ गयी। 5 फरवरी को चौकीदार हरपाल ने सूचना दी कि डुमरी गांव से स्वयं सेवकों की भीड़ थाने की ओर आ रही है। थानाध्यक्ष ने चौकीदार को भेजकर सरदार हरचरन सिंह से मदद मांगी। दोपहर एक बजे तक भीड़ थाने पर आ गयी और वह गांधी जी की जय के नारे लगा रही थी। थानाध्यक्ष ने पुलिस से शान्ति से काम लेने को कहा। भीड़ को पांच मिनट का समय दिया गया कि वह हट जाये अन्यथा गोली चला दी जायेगी। भीड़ के न हटने पर हवाई फायर किया गया कोई घायल नहीं हुआ। भीड़ ने कंकड़ फेंकने शुरू किये। थानाध्यक्ष ने गोली चलाने का आदेश दिया। गोली चलने तक भीड़ दूरी पर खड़ी रही। पर कंकड़ फेंकती रही। गोली वर्षा रुकने पर भीड़ के नेता अन्य लोगों के साथ आगे बढ़े और 80 पुलिस को गिरा दिया। बयान कर्ता ने अपनी वर्दी उतार दी तथा निकटवर्ती थाना गौरी में क इसकी सूचना दी।

कांग्रेस सूत्र व सरकारी विवरण घटना की तिथि 4 फरवरी बताते हैं जबकि अहमद ने 5 फरवरी बताया है। सरकारी विवरण में स्वयं सेवकों को दोषी माना गया है तथा मरने वालों की संख्या 2 बताया है। देवदास गांधी का भी कहना है कि पहले पुलिस ने लाठी चार्ज किया तब भीड़ ने कंकड़ फेंके। सतर्कता बरतने पर यह घटना टाली जा सकती थी। हृदय नाथ कुंजरू, मोहम्मद सुभान उल्लाह तथा चन्द्रकान्त

मालवीय द्वारा की गयी जांच से पता चलता है कि स्वयं सेवक के साथ किये गये दुर्व्यवहार के विरोध में थाने के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। 3-4 हजार लोगों की भीड़ थी। भीड़ पर लाठी चार्ज हुआ। केवल 2 लोग मृत पाये गये। सम्भव है कि पुलिस के भय से भीड़ मृतकों को उठा ले गयी हो तथा बाद में कुछ घायल लोग भी मरे हों। पुलिस अत्याचार के प्रमाण मिलते हैं।[62]

यह घटना दुःखद अवश्य थी, पर पूर्व नियोजित नहीं थी। चौरी चौरा काण्ड स्वयंसेवकों की उत्तेजना का परिणाम था, पर उन्हें उत्तेजित करने का कार्य पुलिस ने ही किया। पुलिस के लाठी चार्ज और हवाई फायर के पहले स्वयं सेवकों का उद्देश्य थाने पर आक्रमण करना या पुलिस वालों को जान से मारने का नहीं था। यदि पुलिस ने बुद्धिमत्ता से काम लिया होता तो यह घटना टाली जा सकती थी। पुलिस ने अपनी कार्यवाहियों से स्वयं सेवकों को उत्तेजित किया, इसलिये इस घटना के लिये पुलिस अधिक उत्तरदायी है।

चौरी चौरा कान्ड में मृत स्वयं सेवकों की संख्या सरकारी विवरण में दी गयी संख्या से अधिक प्रतीत होती है। सरकारी विवरणों में मृत स्वयं सेवकों की संख्या 2 बतायी गयी जबकि द्वारिका प्रसाद पान्डे - जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे - के अनुसार 26 स्वयं सेवक शहीद हुये। हृदय नाथ कुंजरू, चंद्रकान्त मालवीय तथा सुभान उल्लाह द्वारा की गयी जांच में जांचकर्ताओं का मत है कि यद्यपि दो स्वयं सेवकों से अधिक की मृत्यु का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, पर यह भी असम्भव नहीं कि

---

62. गुप्तचर विभाग के अभिलेख।

लाशों को भाड़ पुलिस के भय से उठा ले गयी हो और बहुत से घायल व्यक्ति बाद में मरे हैं । इस काण्ड में सजा प्राप्त लोगों का कहना है कि पुलिस ने स्वयंसेवकों के अपराध को बढ़ा कर बताने के लिये मृत स्वयंसेवकों का संख्या घटा कर बताया तथा बाद में हुयी जाँचों में इस क्षेत्र के लोगों ने पुलिस के भय से अधिकांश लोगों ने पुलिस के सामने बयान नहीं दिये ।

इस घटना के बाद राजनीति नैराश्यपूर्ण हो गयी थी । कांग्रेस कार्यकारिणी ने 11 फरवरी को एक प्रस्ताव पास करके निषेधात्मक असहयोग आन्दोलन बन्द करने की घोषणा की । साथ ही स्वयं सेवकों के प्रदर्शन और भाषण पद्धति पर भी प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया । आन्दोलन के स्थगन के प्रस्ताव को जनता ने सहर्ष स्वीकार किया । इसी का परिणाम था कि जनता ने आगे हिंसा को नहीं अपनाया ।[63]

1923 में चौरी चौरा काण्ड के पीड़ित लोगों की मदद के लिये एक फन्ड स्थापित किया गया ।[64] जुलाई 1922 में मोती लाल नेहरू यहाँ आये । धारा 144 लगी होने के बावजूद उनका शानदार स्वागत किया गया ।

2 अक्टूबर 1922 को महात्मा गांधी का जन्मदिन पूरे जिले में सभाओं का और जुलूसों का आयोजन कर के उत्साह के साथ मनाया गया ।

---

63. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ - यू० पी० (1921-22) जनरल समरी - पृ० 7

64. होम पुलिस विभाग - फाइल नं० 347, बाक्स नं० 45, उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ

3 दिसम्बर 1922 को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने गोरखपुर में 8,000 लोगों की भीड़ को सम्बोधित किया ।

1923 तक जिले की सभी तहसीलों व कस्बों में कांग्रेस समितियाँ स्थापित हो गयी थी, सभी जगह राजनीतिक सभायें हो रही थीं ।

जिले के कुछ स्वयं सेवक नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिये नागपुर गये ।

26 अगस्त 1923 को मोती लाल नेहरू यहां पुन: आये और 2000 लोगों की सभा को सम्बोधित किया ।

मार्च 1924 में जवाहर लाल नेहरू पटना के डा० महमूद तथा कुछ अन्य नेताओं के साथ गोरखपुर आये और कांग्रेस फंड में योगदान देने की अपील की ।

31अक्टूबर 1924 को कुछ सम्पन्न होने वाले राजनीतिक समारोह के लिये गोरखपुर को चुना गया । इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की । उस समय वहां पर मोती लाल नेहरू और जवाहर लाल नेहरू भी उपस्थित थे ।[65]

7 फरवरी 1925 को गोरखपुर मंडल के आयुक्त की ओर से युक्त प्रान्त के सचिव को पत्र लिखा गया जिसमें 7 अक्टूबर 1924 के 'स्वदेश' के विशेषांक की सभी प्रतियों को जब्त करने की बात थी ।[66]

---

65. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ गोरखपुर (1985) पृ0 42
66. पुलिस विभाग - फाइल नं0 411, बाक्स नं0 59, उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ

30 अक्टूबर 1925 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोरखपुर से मुद्रित व प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका 'स्वदेश' के प्रकाशक व मुद्रक पं० दशरथ प्रसाद द्विवेदी की अपील रद्द कर दी। इसमें उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 ए के अन्तर्गत राजद्रोह का आरोप लगाया गया था तथा जिलाधीश द्वारा दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50/- जुर्माना लगाया गया था। यह आरोप विजया दशमी अंक में प्रकाशित चार लेखों के लिये था जिससे कि सरकार व शासितों के मध्य कटुता फैलने का अंदेशा था।[67]

1926 में कई राष्ट्रीय नेता फिर गोरखपुर आये। सरोजिनी नायडू, लाजपत राय, मोती लाल नेहरू इनमें मुख्य थे। 18 दिसम्बर 1927 को काकोरी केस के राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गया। उनके अंतिम शब्द थे, मैं ब्रिटिश राज्य का अन्त चाहता हूँ।[68]

1926 के अन्त में साम्प्रदायिक झगड़े तथा राजनीतिक पिछड़ापन धीरे-धीरे दूर हो रहा था।[69]

1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति का भारतीय प्रेस तथा राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया गया।[70]

---

67. पायनियर - 30 अक्टूबर 1925, पृ० 13
68. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ गोरखपुर - (1985) पृ० 42
69. पायनियर - 31 दिसम्बर 1926, सम्पादकीय लेख 'दि इंडियन पोलिटिक्स' इन 1926, पृ० - 2
70. पायनियर - 11 नवम्बर 1927, पृ० 1

1928 में साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया तथा देश के अन्य भागों की तरह यहां पर भी उसका बहिष्कार किया गया । सारे जिले में काले झंडे दिखायें गये तथा विरोध में सभायें भी आयोजित की गयी ।[71]

1928 में गोरखपुर में मजदूर आन्दोलनों की नींव पड़ चुकी थी । 23 जनवरी 1928 को सुरेन्द्र नाथ दत्त की अध्यक्षता में गोरखपुर कमिश्नरी में मजदूर किसान कांफ्रेंस हुयी । इसके पहले 19 दिसम्बर को बस्ती में विशाल किसान सम्मेलन हो चुका था ।[72]

इसी वर्ष युक्त प्रान्त में महामारियां फैली हुयी थीं । गोरखपुर में इन कारणों से मरने वालों की संख्या 143 हो गयी थी । यह (संख्या) अन्य सभी जिलों से ज्यादा थी ।[73]

10 मार्च 1929 को प्राय: संयुक्त प्रान्त के हर पूर्वी जिले में जुलूस निकाले गये, सभाओं का आयोजन हुआ । गोरखपुर में रमाकान्त, रामधारी, तथा शिवमंगल गांधी ने पडरौना तथा गोला में सभाओं को सम्बोधित किया तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की अपील की । बाबा राघवदास के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार बड़ा सफल रहा ।[74]

4 अक्टूबर 1929 की गांधी जी की गोरखपुर की दूसरी यात्रा ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930-34) को बड़ा प्रोत्साहन दिया । बृजमनगंज में 4500 लोगों ने उनका स्वागत किया । वहां से जे0बी0 कृपलानी के साथ

---

71. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ गोरखपुर (1985) पृ0 42,(कान्फीडेन्शियल रिकार्ड्स
72. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक संक्षिप्त परिचय गोरखपुर, पृ0 13
73. पायनियर - 4 अक्टूबर 1928, पृ0 17
74. (गुप्तचर विभाग के अभिलेख)

गोरखपुर के दक्षिण में 53 कि0 मी0 दूर गौला गये । 8,000 व्यक्तियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया । घुघली जाते समय वे मगहा, बड़हलगंज व कोड़ा राम से हो कर गये । वहाँ पर 10,000 की भीड़ ने स्वागत किया । गोरखपुर परेड ग्राउन्ड में उसी दिन 15,000 व्यक्तियों की सभा को सम्बोधित किया । 5-6 अक्टूबर 1929 को महाराज गंज व चौरी चौरा में सभा सम्बोधित की । उन्होंने भाषण में कहा कि हमें प्रत्येक स्थिति में अहिंसा का पालन करना चाहिये जिससे कहीं भी चौरी चौरा काण्ड की पुनरावृत्ति न हो सके । साथ ही उन्होंने जनता को आगामी जनवरी में आन्दोलन हेतु तैयार रहने के लिये सचेत किया ।

1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान गोरखपुर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । नमक कानून तोड़ने पर गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में आन्दोलन शुरू हो गया, सभायें की गयीं, जुलूसों व हड़ताल का आयोजन किया गया । अप्रैल 1930 में स्थान-स्थान पर नमक कानून सार्वजनिक रूप से तोड़ा गया । 17मई 1930 को गोरखपुर में पूर्ण हड़ताल मनायी गयी । 22 जुलाई 1930 को मदन मोहन मालवीय जी गोरखपुर आये और 8,000 की सभा में हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये अपील की ।[75]

जब आन्दोलन शुरू हुआ गोरखपुर व पडरौना में कपड़े की दुकानों पर धरना दिया गया । देवरिया व बरहज में कपड़े व शराब की दुकानों पर धरना दिया गया । दुकानदारों ने विदेशी कपड़ा बेचने से इंकार कर दिया । शराब विक्रेताओं ने शराब बेचने से इंकार कर दिया । फिर भी सत्याग्रही काफी सफल रहे हैं ।

---

75. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ गोरखपुर - 1985 पृ0 42-43

ऐसा कहा जा रहा है कि कपड़े के बड़े व्यापारी आन्दोलन का साथ इसलिये दे रहे हैं ताकि छोटे व्यवसायी समाप्त हो जायें और उनको लाभ हो ।

गोरखपुर में शराब के एक लाइसेंसी ने शिकायत की, पर वह गलत पाया गया । एक मुसलमान व्यापारी ने सहायता की अपील की और उसकी मदद के लिये पुलिस दे दी गयी ।[76]

विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के दौरान एक अफवाह यह फैली थी कि इनको बनाने में गाय की चर्बी इस्तेमाल की जाती है । इन अफवाहों का सामना करने के लिये तैयारी करने की सलाह दी गयी । क्योंकि यह खबर चर्बी वाले कारतूसों की तरह ही फैल रही थी ।[77] प्रेस आर्डिनेन्स के अन्तर्गत सिक्योरिटी मांगी जाने पर 'आज' 'प्रताप' व 'स्वाधीन प्रजा' ने प्रकाशन बन्द कर दिया ।

'स्वदेश' ने संपादकीय लिखना बन्द कर दिया । मनस्वी संपादकों ने देश प्रेमी पाठकों के लिये भूमिगत क्रांतिकारी पत्रों को अपना शुरू किया ।[78]

17 अप्रैल 1930 में 'सत्याग्रह समाचार' में श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने 'सत्याग्रह संग्राम' नामक लेख लिखा जिसमें स्पष्ट किया कि इस बार लड़ाई का स्वरूप 1921-22 की अपेक्षा अधिक बड़ा है ।

---

76. कान्फीडेन्शियल रिकार्ड्स

77. पुलिस विभाग - फाइल नं० 202, बाक्स नं० 66 उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।

78. पुलिस विभाग - फाइल नं० 1012, बाक्स नं० 66 उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।

18 अप्रैल 1930 के संपादकीय में जनता से आग्रह किया गया कि वह शान्तिपूर्वक बढ़े चले, सहिष्णुता दिखाये तथा शान्ति के लिये अपनी जान भी आगे दे दे।

31 मई 1930 के साइक्लोस्टाइल अंक द्वारा निःशस्त्र जनता पर गोली, लाठी वर्षा आदि का विरोध किया गया।

5 जून 1930 के अंक द्वारा सरकार के अनुचित कानूनों को तोड़ने के लिये कहा गया।[79]

'आज' का प्रकाशन 'आज के समाचार' साइक्लोस्टाइल पत्र के रूप में हुआ। ऐसे प्रकाशन से क्षुब्ध होकर सरकार ने अनआथोराइज्ड न्यूजशाट एण्ड न्यूज पेपर्स आर्डिनेन्स 1930 नं0 7/1930 आर्डिनेन्स 2 जुलाई 1930 को घोषित किया। इसके द्वारा अनियत कालिक पत्रों की जब्ती, छापाखानों व पत्रों को नष्ट करने का अधिकार दिया।[80]

नमक सत्याग्रह के दौरान जिले में प्रभात कुसुम बनर्जी, श्री गोविन्द राव, सूरजकला पाण्डे, रामधारी पाण्डे, अलिकरण मिश्र, सिया शरण मिश्र, रामचंद्र शर्मा, लक्ष्मी शंकर सिंह, मंगल सिंह और राजमंगल प्रसाद ने विशेष भाग लिया। जेल जाने वाले प्रथम सत्याग्रहियों में बाबा राघवदास भी थे। पूरे जिले में बहिष्कार आन्दोलन से सरकारी अधिकारियों के हाथ पैर ठण्डे होने लगे।[81]

---

79. पुलिस विभाग – फाइल नं0 106, बाक्स नं0 – 87,88, उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
80. तिवारी डा0 अर्जुन – स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ0 प्र0 के सम्बन्ध में) पृ0 300
81. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक संक्षिप्त परिचय गोरखपुर – पृ0 14

क्रान्तिकाल में गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की राजनीति को साहित्य, कला तथा संस्कृति को सर्वाधिक प्रभावित किया। लगातार 25 वर्षों तक गांधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया। भारतीय इतिहास को एक नया स्वरूप ही नहीं दिया वरन् भारत की विचार धारा पर एक अमिट छाप छोड़ा। इसी कारण 1920 के बाद का समय भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में गांधी युग कहलाता है।[82]

---

82. तिवारी, डा० अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वो उ० पृ० के सन्दर्भ में) पृ० 110

"सविनय अवज्ञा आन्दोलन और उसके बाद की स्थिति" (1931 - 1941)

"1931 और 1940 के बीच स्वतंत्रता का संघर्ष कई कदम आगे बढ़ा । इसका प्रारम्भ दूसरे असहयोग आन्दोलन से हुआ और अंत दूसरे विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तथा युद्ध में भारत को बिना उसकी अनुमति लिये घसीटने के विरोध में प्रान्तों के कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के त्यागपत्र के साथ"।[1]

"1930 और 40 के मध्य कांग्रेस साम्राज्यवाद के विरोध के अपने निर्णय में अधिक से अधिक दृढ़ होती गयी"।[2]

"1930 - 34 के मध्य जो व्यापक सिविल नाफरमानी का आन्दोलन हुआ, उसमें हजारों नौजवानों को त्याग व बलिदान का, अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने का, अपने उद्देश्यों को पूरा करने का सुनहरा मौका मिला"।[3]

"1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन लोकप्रिय होता जा रहा था । सरकार का दमन चक्र जारी था । अखबार व कार्यकर्ताओं के दमन और गिरफ्तारी का क्रम चलता रहा" ।[4]

"लोगों में इस बात का भय था कि कहीं किसी एक हिंसात्मक काण्ड के हो जाने से पूरा आन्दोलन फिर न स्थगित कर दिया जाय, जैसा कि 1921-22 के आन्दोलन के साथ हुआ था ।[5] "गांधी जी ने एक लेख लिख कर सत्याग्रहियों को आदेश दिया - "इस बार मेरी गिरफ्तारी पर मूक तथा निष्क्रिय अहिंसा का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिये । वरन् पूर्ण स्वराज्य

---

1. विपिन चंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ० सं० 151
2. वही ; पृ० 200
3. लिमये, मधु, स्वतंत्रता आन्दोलन की विचारधारा - पृ० 95
4. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ० 400
5. नेहरू, जवाहर लाल - मेरी कहानी, पृ० 286

की प्राप्ति के लिये अहिंसा में निष्ठापूर्वक विश्वास करने वाला एक-एक व्यक्ति अपने को इस संकल्प के साथ या तो गिरफ्तार करा दें या फिर मर जाय कि वह इस गुलामी में नहीं रहेगा । ----- मैं यही कह सकता हूँ कि यह आन्दोलन मुख्य रूप से स्वतः संचालित होगा हरेक व्यक्ति जो अहिंसा में निष्ठापूर्वक विश्वास करता है अथवा उसे नीति के रूप के स्वीकार करता है, इस सामूहिक आन्दोलन में मदद देगा ।"[6]

25 जनवरी 1931 को कांग्रेस कार्य समिति पर से हर तरह की रोक हटा ली गया ।[7] प्रथम गोल मेज सम्मेलन से लौटने के बाद सर तेज बहादुर शाह और जयकर ने मध्यस्थता के प्रयास शुरू किये । इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी व लार्ड इर्विन में विचार विमर्श शुरू हुआ । इस वार्ता के परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को गांधी-इर्विन समझौता हुआ । जिस संस्था को सरकार ने कल तक गैर कानूनी करार दिया था, उसी के साथ झुक कर समझौता करना पड़ा । यह सरकार व कांग्रेस की पहली सन्धि था ।[8]

इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द करने की घोषणा की तथा सरकार ने राजनीतिक बन्दियों को मुक्त करने का आश्वासन दिया । 5मार्च 1931 को गांधी जी ने प्रतिनिधि सम्मेलन में घोषणा की कि कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को पाने के लिये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा ।[9]

---

6. रामगोपाल - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, पृ0 356
7. गुप्त, मन्मथनाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ0 403
8. वहीं ; पृ0 404 - 405
9. आज - 7 मार्च 1931 पृ0 9

गांधी जी ने वायसराय के साथ बात चीत में कई मसले उठाये थे। इन सभी प्रश्नों को लेकर इरविन अपनी बात पर अड़े रहे। अनेक बहानों की आड़ में सरकार ने दमनकारी कदमों में किसी तरह की ढिलाई नहीं दी। गांधी जी ने जो रियायतें चाही थीं, उन्हें पाने में वे सफल नहीं रहे।[10]

1931 मार्च के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। मौलिक अधिकारों व आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पास हुआ जो भविष्य के जनतंत्र में कांग्रेस के राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रमों का रूप प्रस्तुत करता था।[11]

कराची अधिवेशन समझाने-बुझाने के तर्क के जरिये भीतरी और बाहरी मतभेदों को समाप्त कर देने में गांधीवादी दर्शन की राजनैतिक सफलता का द्योतन करता है तो दूसरी ओर वहीं से कांग्रेस के कार्यक्रम में, परिवर्तनकारी, समाजवादी प्रवृत्तियों के प्रभावशाली ढंग से आने का सूत्रपात होता है।[12]

सन् 1931 में अप्रैल से जून तक, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में अपने उस दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करती रही जो उसने प्रस्तुत किया था। कांग्रेस का प्रतिनिधि सिर्फ गांधी जी को स्वीकार किया गया। यदि डा० अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान भी लंदन गये होते तो संभव है कि ब्रितानी जनमत को इस बात का विश्वास दिलाया जा सकता था कि कांग्रेस प्रगतिशील मुसलमानों के मत का प्रतिनिधित्व करती है।[13]

---

10. त्रिपाठी, अमलेश, विपिनचंद्र व दे, बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ० 176-177
11. वहीं ; पृ० 178
12. विपिन चंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे, बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ० 178
13. वही ; पृ० 179

अगस्त में लार्ड विलिंगडन नये वायसराय हो कर आये, वे मूलत: कम उदारवादी थे। अगस्त में ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया गया।[14]

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में हर निर्णय सरकार पर छूटता रहा। गांधी जी निश्चित आश्वासन पाने में सफल नहीं रहे। अल्पसंख्यकों का प्रश्न सुलझाने पर ज्यादा आलोचना हुआ। निराश हो कर गांधी जी लौट आये।[15]

दिसम्बर 1931 में लंदन से लौटने के बाद गांधी जी ने वायसराय से मुलाकात का समय मांगा ताकि उत्तर प्रदेश तथा सीमा प्रान्त के किसानों में अशांति के बारे में सरकार से शान्तिपूर्ण समझौते का कोई रास्ता निकाला जा सके। गांधी जी को यह सूचित किया गया कि मुलाकात इस शर्त पर हो सकती है कि राजनीतिक स्थिति का सामना करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सरकार के इन्हीं कदमों के फलस्वरूप कांग्रेस करबन्दी आन्दोलन चलाने के लिये मजबूर हो गयी थी और यदि उन्हीं के बारे में वार्ता न हो तो मुलाकात का कोई अर्थ न था। अत: कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास कर के सत्याग्रह आन्दोलन फिर शुरू करने का निश्चय किया।[16]

---

14. वहीं ; पृ0 180
15. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ0 409
16. रामगोपाल - भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास - पृ0 388

कांग्रेस अभी भी बातचीत व समझौते के लिये तैयार था, पर सरकार किसी भी समझौते के लिये तैयार नहीं थी। एक साथ कई आर्डिनेन्स पास हुये। शुरू के चार महीनों में 80,000 गिरफ्तारियां हुयी। सैकड़ों बुलेटिन पर्चे, पुस्तिकायें गैर कानूनी रूप से निकाली गयीं। अक्सर टाइप या साइक्लोस्टाइल से काम लिया गया। सरकार को परेशान करने के नये-नये उपाय निकाले गये।[17]

17 अगस्त को प्रधान मंत्री रेम्जे मैकडोनल्ड ने अपना कुख्यात साम्प्रदायिक बंटवारा घोषित किया जिसमें अस्पृश्यों के लिये अलग निर्वाचन था। गांधी जी ने 18 अगस्त को वायसराय को पत्र लिखा कि यदि इसको बदला नहीं गया तो मैं 20 सितम्बर से आमरण अनशन करूंगा। 12 सितम्बर को यह बात सार्वजनिक रूप से घोषित कर दी गयी। बम्बई में मालवीय जी ने कांफ्रेन्स बुलायी। इसमें डा० अम्बेडकर व अन्य उच्च वर्ग के नेता थे। 24 तारीख को एक निर्णय लिया गया, 26 को ब्रिटिश सरकार ने भी इसे मान लिया। गांधी जी ने अनशन भंग कर दिया। इस पूना पैक्ट के अनुसार पहले कथित अछूत चार व्यक्तियों को नामजद करेंगे। इस नामजदगी में अछूत ही भाग ले सकेंगे। इसके बाद कथित उच्च जाति और अछूत इन चार में से एक को चुनेंगे।[18]

29 अक्टूबर 1932 को वाराणसी के दैनिक 'आज' के कार्यालय की पुलिस द्वारा तलाशी ली गयी। पुलिस को वहां कांग्रेस का साहित्य छपे जाने का संदेह था। पर वहां पर कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं प्राप्त हुयी।[19]

---

17. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ० 412
18. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ० 413-414
19. लीडर - 2 नवम्बर 1932, पृ० 6

4 नवम्बर 1932 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कैदा दिवस मनाया गया।[20]

1932 के तीसरे गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श हुआ उसके अनुसार कुछ अतिरिक्त सुधारों के साथ 1935 का भारतीय विधेयक पास करने का फैसला किया। पहली बार नये विधेयक में केन्द्र में संघीय शासन और प्रान्तों को पहले से अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव था।[21]

1935 का विधेयक कांग्रेस के लिये पूर्णतः निराशाजनक था। ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता पर राजनीतिक व आर्थिक अधिकार छोड़ नहीं दिये थे। जनमत से निर्वाचित मंत्रियों को ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया था, पर विदेशी हुकूमत कायम था।[22]

1932-33 का वर्ष शायद ब्रिटिश शासन का अंतिम वर्ष था जिसमें कट्टरपंथी आतंकवाद की लपटें ऊंचाई तक उठी और फिर जोर जुल्म से पूरी तरह दबा दी गयी।[23]

तीसरे गोल मेज सम्मेलन से जब गांधी जी वापस आये तो उस समय संयुक्त प्रान्त के किसानों की दशा खराब थी। कांग्रेस के समर्थन पर उन्होंने भरसक लगान अदा किया था, पर अब ऐसा बिन्दु आ गया था कि वे आगे लगान नहीं दे सकते थे। सरकार इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी।

---

20. पायनियर 10 दिसम्बर 1932, पृ0 5
21. विपिनचंद्र त्रिपाठी, अमलेश व दे, बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 186
22. वही; पृ0 187
23. वहीं; पृ0 185

अतः मजबूर हो कर किसानों को लगान न देने का सलाह कांग्रेस ने दी। 29 महीने तक चलने वाले आन्दोलन का उद्देश्य सम्भवतः सरकार को पंगु बना देने का था।[24]

धीरे-धीरे सत्याग्रह आन्दोलन कमजोर पड़ता गया; फिर भी वह चलता रहा। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, त्यों-त्यों वह जन-साधारण का आन्दोलन नहीं रहा। सरकारी दमन की सख्ती के अलावा इस आन्दोलन पर पहला जबरदस्त प्रहार उस समय हुआ जब सितम्बर 1932 में गांधी जी ने पहले पहल हरिजनों की समस्या पर अनशन किया। इसने जनता में जागृति जरूर पैदा की पर उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया। जब मई 1933 में सत्याग्रह की लड़ाई कुछ समय के लिये स्थगित की गयी तो यह व्यावहारिक रूप से उसका अन्त था। बाद में अप्रैल 1934 में आंदोलन को अंतिम रूप से तिलांजलि दे दी गयी।[25]

कांग्रेस ने 1935 के एक्ट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता से कम कोई चीज उसे स्वीकार नहीं था। पर संविधान भंग करने के लिये उसने चुनाव लड़ने का निश्चय किया तथा बहुसंख्यक सीटें जीत कर अपने इस दावे की पुष्टि की कि वह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस के पक्ष में पड़ा हर वोट अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध था।[26]

---

24. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ0 410
25. नेहरू, जवाहर लाल - मेरी कहानी - पृ0 460
26. राम गोपाल - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास - पृ0 404

1934 के 27-28 अक्टूबर को बम्बई अधिवेशन के संचालन के बाद गांधी जी कांग्रेस के चार आने की सदस्यता से अलग हो गये। उनका कहना था कि उनमें तथा बहुत से कांग्रेसियों में मतभेद हैं और यह मतभेद बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में कांग्रेस में रहना उनके लिये सम्भव नहीं है। पर यह तथ्य है कि इसके बाद भी वे कांग्रेस के सर्वेसर्वा बने रहे हैं।[27]

सितम्बर 1939 में युद्ध शुरू होने पर भारतीय नेता एक कठिन स्थिति में पड़ गये। वे फासिस्टवादी दर्शन के विरुद्ध थे।[28] कांग्रेस कार्यसमिति ने अगस्त 1939 में ही यह प्रस्ताव पास किया था कि कांग्रेस लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता के पक्ष में है।----- ब्रिटिश सरकार के भूतकाल के रवैये से तथा नीति से ज्ञात होता है कि यह सरकार लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की पक्षपाती नहीं है। किसी भी समय वह इन आदर्शों के साथ विश्वासघात कर सकती है। भारत ऐसी सरकार के साथ न तो सहयोग कर सकता है न वह उस लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिये जन धन दे सकता है।[29]

14 सितम्बर की बैठक में कांग्रेस में कहा गया कि कांग्रेस से जबरदस्ती सहयोग लेना गलत है। कांग्रेस बिना शर्त सहयोग नहीं देगी। नवम्बर में 8 प्रान्तों के कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने कार्य समिति की हिदायत के अनुसार त्याग पत्र दे दिया। 19-20 मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि कांग्रेस साम्राज्यवादी तथा फासिस्टवादी सरकारों के विरुद्ध है और उसे बड़ी खुशी होगी यदि वह आजाद हो कर फासिस्टवाद के विरुद्ध लड़ सके।[30]

---

27. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ0 420-421
28. विपिन चंद्र त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ206
29. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ0 440
30. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ0 441-442

1939 के बाद साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गये थे । इसका कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति थी ।[31] मुस्लिम लीग ने अपने राजनीतिक आग्रहों को प्रकट करने के लिये एक सुनियोजित आन्दोलन आरंभ किया । 1938 के अंत तक उसकी 170 नयी शाखायें स्थापित हो चुकी थीं । 90 उत्तर प्रदेश में तथा 40 पंजाब में । अकेले उत्तर प्रदेश में एक लाख सदस्य बनाये गये । 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गयी । ।[32]

गांधी जी 27 सितम्बर को वायसराय से मिले । वायसराय ने कांग्रेस की भाषण देने की स्वतंत्रता की मांग को नहीं माना । अस्वीकार करने का कारण यह कहा गया कि इससे युद्ध पर प्रभाव पड़ेगा । अब आन्दोलन शुरू करने के सिवाय कोई चारा नहीं था ।[33]

11 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर के गांधी जी के नेतृत्व में युद्ध के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया ।[34] इसमें सत्याग्रही नारा लगाता था कि 'युद्ध में किसी तरह का सहयोग देना पाप है' और वह गिरफ्तार हो जाता था । हजारों सत्याग्रही जेल गये । उत्तर प्रदेश ने इसमें जमकर हिस्सा लिया ।[35]

नवम्बर 1940 के अन्तिम दिनों में संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने गोरखपुर से बाबा राघवदास , प्रयाग ध्वजसिंह, रामधारी पान्डे, दशरथ प्रसाद द्विवेदी सिंहासन सिंह और सुलेमान अंसारी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की

---

31. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश, दे, बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 203
32. वही ; पृ0 205
33. मिश्रा, गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया, पृ0, 141
34. त्रिपाठी, आमोद नाथ - पूर्वी उ0 प्र0 के जनजीवन में बाबा राघवदास का योगदान, शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ0 123
35. मिश्र, कन्हैया लाल - उ0 प्र0 स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी - पृ0 127

अनुमति दी । 24 नवम्बर को उन्होंने जिले के अधिकारियों को सूचित किया कि वे 25 नवम्बर को सांयकाल चौरी चौरा स्टेशन से उत्तर की ओर युद्ध विरोधी नारे लगाते हुये सत्याग्रह करेंगे । पर उन्हें 24 की रात गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी से पहले उन्होंने जनता से व्यक्तिगत सत्याग्रह में पूर्ण सहयोग देने की अपील की ।[36]

प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे ने 21 अक्टूबर 1940 को युद्ध विरोधी भाषण देते हुये गिरफ्तारी दी ।[37]

नवम्बर 1940 में गांधी जी ने वायसराय को अपने नये कार्यक्रम की सूचना दी । इसके अनुसार सविनय अवज्ञा आन्दोलन व्यक्तिगत आन्दोलन में बदल गया । अधिकतर कांग्रेसियों ने आन्दोलन को समाप्त करने की अपील की, परन्तु गांधी जी न तो इसे वापस लेना चाहते थे और न ही इसे जन आन्दोलन में बदल कर सरकार को परेशान करना चाहते थे - जो कि युद्ध में व्यस्त थी ।

मि० ड्रेवर ने कहा - 1940-41 का सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1930 तथा 1942 के आन्दोलनों की तरह जनता में उत्साह नहीं ला सका ।[38]

3 दिसम्बर 1941 को सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी की गयी कि युद्ध समाप्त होने पर सभी सत्याग्रही बन्दी जो मुश्किल से 6-7 हजार हैं मुक्त कर दिये जायेंगे ।[39]

---

36. आज - 27 नवम्बर 1940 - पृ० 1-7
37. त्रिपाठी, आमोद नाथ - पूर्वी उ0 प्र0 के जन जीवन में बाबा राघवदास का योगदान, शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय - पृ० 124
38. मिश्रा, गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया {1919-47} पृ० 142
39. वहीं ; पृ० 142

कुछ भी न करने से यह प्रतीकवादी संग्राम अच्छा था जिससे संसार के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि भारत के वास्तविक प्रतिनिधि लड़ाई के साथ नहीं है। सरकार का दमन जारी रहा तथा संयुक्त प्रान्त में सबसे अधिक लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया।[40]

चूंकि गांधी जी किसी की दयनीय दशा से लाभ नहीं उठाना चाहते थे, अतः आन्दोलन समाप्त कर दिया गया। सरकार को युद्ध हेतु जनधन के रूप में दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती करने के उद्देश्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह काफी अंशों में सफल रहा।[41]

1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान गोरखपुर से 6 मील पूर्व की ओर सनहा गांव में सरकारी दमन तथा अत्याचार के विरुद्ध कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने एक प्रेरणा दायक आन्दोलन चलाया। यहां के कार्यकर्ताओं में चौरी चौरा काण्ड के लिये पश्चाताप की भावना बनी थी। इसी कारण गोरखपुर जिला कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष बाबा राघवदास के नेतृत्व में चलने वाले सनहा आन्दोलन का नारा था 'मर जायेंगे पर मारेंगे नहीं।' यह आन्दोलन सनहा गांव के कासिम अली द्वारा नौआकुमरी गांव के एक गरीब कांग्रेसी कार्यकर्ता की कुर्क की गयी भैंस एक रुपये के प्रतीक मूल्य पर लेने और फिर उसी दिन उसे गायब करा देने के विरुद्ध प्रारम्भ किया गया था। कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने सनहा में कासिम अली के घर के पास धरना दे कर हाय तौबा के नारे लगाना शुरू किया। 45 दिनों तक चलने वाले इस आन्दोलन में स्वयं सेवकों पर पुलिस ने कई बार लाठी चार्ज किया।

---

40. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास पृ0 446,
41. गहलौत, बी0 एस0 -'पूर्वी उ0 प्र0 में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास' शोध प्रबन्ध - इलाहाबाद विश्वविद्यालय - पृ0 107

15 स्वयं सेवकों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया । इनको छ:छ: महीने कारावास की सजा दी गयी । पुलिस की इन कार्यवाहियों का कोई उत्तर न दे कर कार्यकर्ता आन्दोलन में लगे रहे । 'हाय तौबा' के निरन्तर चल रहे नारे से पागल हो जाने की स्थिति में पहुँच गया कासिम अली बाबा राघवदास के पास आया । उसके द्वारा लिखित रूप से क्षमा याचना करने पर ही यह आन्दोलन समाप्त हुआ ।[42]

1931 में जिले में लोगों ने किसान आन्दोलन में भाग लिया यह जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन था । इसको दबाने के लिये सरकार ने भय का राज्य कायम किया । नागरिक स्वतंत्रता को दबाने के लिये प्रेस आर्डिनेन्स, प्रिवेंशन आफ इन्टीमीडेशन आर्डिनेन्स और अनलौफुल इन्स्टीगेशन आर्डिनेन्स पास किये गये । इन दमनकारी कानूनों द्वारा प्रेस एक्ट के अन्तर्गत 6, इंडियन पेनल कोड के अन्तर्गत 587, अन्य आर्डिनेन्सों द्वारा 219 तथा 22 केस इमरजेन्सी पावर्स एक्ट के अन्तर्गत हुये ।[43]

1 नवम्बर 1932 के संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस कमेटी के हिन्दी बुलेटिन नं० 21 से पता चलता है कि किसानों पर कितने अत्याचार किये गये थे । "गोरखपुर में पुलिस व जमींदारों का अत्याचार जारी है । स्वयं सेवक गिरफ्तार किये जाते हैं, बूते की ठोकरों से मारे जाते हैं और फिर मुक्त कर दिये जाते है ।[44] पर दमनकारी कार्य जिले के लोगों के उत्साह को कम न कर सके । 20 जुलाई 1934 को उन्होंने हृदय नाथ कुंजरू को

---

42. त्रिपाठी, आमोद नाथ - पूर्वी उ0 प्र0 के जन जीवन में बाबा राघवदास का योगदान शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय पृ0 101

43. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दी यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एन्ड अवध - सप्लीमेन्टरी नोट्स एन्ड स्टेटिसटिकल कवॉ, 1931-32, Vol. XXXI [1] गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट - पृ0 26

44. कान्फीडेन्शियल रिकार्ड्स

सभाओं को सम्बोधित करने के लिये बुलाया ।[45]

7/8 मई 1932 में गोरखपुर के जिलाधीश द्वारा संयुक्त प्रान्त के सरकार के उप सचिव को पत्र लिख कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन और लगान बन्दी आन्दोलन में भाग लेने वाले जिले के विद्यार्थियों की सूची भेजा गया ।[46]

गांधी-इर्विन समझौते के बाद गोरखपुर जिले के पडरौना, सदर, महाराजगंज और बांसगांव तहसील में कई डाके पड़े । पुलिस बजाय जांच करने के स्वयं सेवकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं या उनके सम्बन्धियों को फंसाने की चेष्टा करती ।[47]

1 जून 1932 को गोरखपुर में दरबार का आयोजन करके मंडल के आयुक्त ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जो जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने में सरकार की मदद कर रहे थे । 160 लोगों को मंडल व प्रमाण पत्र दिये गये ।[48]

1933 के प्रथम छः महीनों में संयुक्त प्रान्त में 7 केस आतंकवाद के हुये तथा बाद के छः महीनों में एक केस हुआ ।[49]

फरवरी 1934 में गोरखपुर में प्लेग फैल रहा था ।[50] मार्च 1934 में सारे प्रान्त में प्लेग महामारी के रूप में फैल रहा था ।[51] उ0प्र0 पब्लिक

---

45. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स - गोरखपुर - 1985 पृ0 44
46. जी0 ए0 डी0, - फाइल नं0 192, बाक्स नं0 119, उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।
47. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर - पृ0 16-17
48. पायनियर - 1 जून 1932 पृ0 5
49. पुलिस विभाग - फाइल नं0 1504, बाक्स नं0 77 उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।
50. पायनियर - 25 फरवरी 1934
51. पायनियर - 7 मार्च 1934 पृ0 - 1

हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार मार्च 1934 तक प्रान्त में प्लेग से 1,959 मौतें हो चुकी था।[52]

मई 1935 में रफी अहमद किदवई तथा जून 1935 में सम्पूर्णानन्द ने जिले की यात्रा की तथा ब्रिटिश अत्याचारों का विरोध किया।[53]

1935 के एक्ट के अनुसार पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुये तथा गोरखपुर से सभी कांग्रेसी उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत कर असेम्बली के सदस्य चुने गये। पं० गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रान्त में कुछ समय के लिये कांग्रेस शासन की स्थापना हुयी, पर द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने पर युद्ध में सहयोग न देने तथा ~~भाषण की स्वतंत्रता के प्रश्न पर सभी मंत्रिमण्डलों~~ भाषण की स्वतंत्रता के प्रश्न पर सभी मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया।[54]

1934 में गृह-पुलिस विभाग की ओर से गोरखपुर जिले के भैंसहा गांव के सभी व्यस्क पुरुष भारों (एक जाति) को अपराधी जाति घोषित किया गया।[55]

13 अगस्त 1936 को जवाहर लाल नेहरू ने गोरखपुर में 5,000 किसानों को सम्बोधित किया।[56] जून 1936 में ब्रिटेन के सम्राट के जन्म दिन के उपलक्ष में गोरखपुर में एक सैनिक परेड का समारोह किया गया।[57]

---

52. पायनियर - 21 मार्च 1934 - पृ० 1
53. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स - गोरखपुर (1985) पृ० 44
54. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय-गोरखपुर - पृ० 22
55. गृह पुलिस विभाग - फाइल नं० 1016/1936, बाक्स नं० 270 उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ
56. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स - गोरखपुर (1985) पृ० 44
57. पायनियर - 30 जून 1936, पृ० 6

जुलाई 1936 में गोरखपुर में बाढ़ आया और जिले में हैजा फैला था ।[58] जुलाई के अंतिम सप्ताह में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ । बाढ़ पीड़ितों के लिये राहत कार्य होता रहा ।[59] गीता प्रेस में 9,300 शरणार्थी थे। आयुक्त ने प्रान्तीय सरकार से पीड़ितों के लिये 10,000 रुपये देने के लिये कहा ।[60]

बाढ़ के बाद हैजे का आक्रमण जिले में हुआ । इसकी रोकथाम के उपाय किये गये ।[61]

1 अप्रैल 1937 को जिले में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया तथा 10,000 से अधिक लोगों का जुलूस निकाला गया । यह 1935 के इंडिया एक्ट का विरोध करने के लिये निकाला गया था । प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय भाग दोनों की आलोचना की गयी तथा खेद व्यक्त किया गया । मई 1937 में गोविन्द बल्लभ पन्त ने जिले में 12 सभायें आयोजित कीं ।[62]

जून 1937 में बाबा राघवदास पर धारा 108 और 112 के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में उनके द्वारा दिये गये राजद्रोहात्मक भाषणों के लिये मुकदमे चले । उन्हें दी गयी नोटिस में एक हजार रुपये का मुचलका तथा डेढ़-डेढ़ हजार रुपये की दो जमानतें एक वर्ष तक अच्छे चाल चलन के लिये मांगी गयी ।[63]

---

58. पायनियर - 23 जुलाई 1936 - पृ० ।
59. पायनियर - 26 जुलाई 1936 पृ० ।
60. पायनियर - 2 अगस्त 1936 पृ० ।
61. पायनियर - 4 अगस्त 1936 पृ० ।
62. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स - गोरखपुर - 1985 - पृ० 44
63. गुप्तचर विभाग के अभिलेख

18 अक्टूबर 1937 में संयुक्त प्रान्त सरकार द्वारा कांग्रेस के प्रति शिया सुन्नी दृष्टिकोण के ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी।[64] व 9नवम्बर 1937 को जवाहर लाल नेहरू ने आचार्य नरेन्द्र देव को संयुक्त प्रान्त की गम्भीर साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में पत्र लिखा।[65]

18 अप्रैल 1938 को पडरौना (गोरखपुर जिला) में जमींदारों व किसानों में संघर्ष हो गया जिसमे 23 लोग घायल हो गये।[66]

12 मई 1938 को 300 किसानों द्वारा महाराजगंज तहसील में एक ठाकुर जमींदार जंगा राय और उसके कारिन्दे को लाठियों से पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने 42 लोगोंको गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी।[67]

पिपराइच रेल डकैती के सिलसिले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्र, एक कांग्रेस नेता, गोरखपुर के मजदूर नेता को गिरफ्तार किया गया।[68]

जुलाई-अगस्त में पुन: यहां बाढ़ की स्थिति आयी। बड़हलगंज व बरहज बाजार की सड़कों पर पानी आ गया।[69]

12 मई की घटना के लिये कांग्रेस नेता प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना को जिम्मेदार ठहराया गया।[70] पायनियर में संपादकीय टिप्पणी लिखी गयी।[71]

---

64. टुवर्ड्स फ्रीडम (1937-47) Vol. I एक्स पेरीमेन्ट्स विद प्राविनशियल (आटोनामी) I Jan. - 31 दिसम्बर 1937 मुख्य प्रकाशक - डा०पी०एन० चौपड़ा - पृ० 1044
65. वहीं; पृ० 1128
66. पायनियर - 18 अप्रैल 1938 पृ० 1
67. पायनियर - 12 मई 1938 पृ० 1
68. पायनियर - 1 जून 1938 पृ० 1
69. पायनियर - 13 अगस्त 1938 पृ० 11
70. पायनियर - 2 अक्टूबर 1938 पृ० 1
71. पायनियर - 4 अक्टूबर 1938 पृ० 2 'दि ट्रुथ अबाउट गोरखपुर'

9 अक्टूबर 1938 के अंक में प्रो0 सक्सेना ने अपने ऊपर लगाये आरोपों का जवाब दिया । जमींदारों और जिले के अधिकारियों पर दोष लगाया गया ।[72] 11 नवम्बर के अंक में पायनियर के संपादक ने प्रो0 सक्सेना से सहमत होते हुये जिलाधिकारियों से पूछा कि वर्षों से किसानों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति वे खामोश क्यों थे । क्यों नहीं उन लोगों ने स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक कदम उठाये ।[73]

अक्टूबर 1938 में गोरखपुर में हैजा महामारी के रूप में फैला ।[74]

18 मार्च 1939 में गोरखपुर में प्रान्तीय मुस्लिम लीग का तीन दिन का सम्मेलन हुआ । इसी वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया । कांग्रेस में युद्ध में सरकार से सहयोग न करने का निश्चय किया । 26 अगस्त 1939 को आचार्य नरेन्द्र देव ने जिले के लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की ।[75]

जिला छात्र संघ के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर 10 सितम्बर 1939 को बरहज बाजार में 500 लोगों की सभा में परमानन्द ने भाषण दिया । इसमें उन्होंने छात्रों से संगठित हो कर संघर्ष करने की अपील की । यदि किसी भी भारतीय के साथ कोई गलत व्यवहार किया जाय तो सारे भारतीयों को उसका विरोध करना चाहिये ।[76]

30 सितम्बर 1939 को संयुक्त प्रान्त की सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को गोपनीय पत्र लिख कर आदेश दिया गया कि सार्वजनिक

---

72. पायनियर – 9 अक्टूबर 1938 – पृ0 3
73. पायनियर – 11 अक्टूबर – 1938 – पृ0 8 (संपादकीय) गवर्नमेन्ट एन्ड गोरखपुर ।
74. पायनियर – 12 अक्टूबर 1938 पृ0 6
75. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, गोरखपुर – 1985 पृ0 44
76. पुलिस विभाग – फाइल नं0 211 बाक्स नं0 80 (10.9.1938 को बरहज बाजार में परमानन्द द्वारा दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद ।

शान्ति बनाये रखने के लिये तथा हिंसा न फैलने पाये, इसके लिये आवश्यक कदम उठाये जायें। सभी वक्ताओं और प्रकाशकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, यदि वे कानून का उल्लंघन करते हैं और लोगों को हिंसा के लिये भड़काते हैं।[77]

1940 में गोविन्द बल्लभ पन्त जवाहर लाल नेहरू और रफी अहमद कीदवई जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने जिले का दौरा किया।[78] इसी वर्ष इस जिले में पं० जवाहर लाल नेहरू पर मुकदमा चलाया गया जिसमें उन्हें चार वर्ष की कड़ी सजा दी गयी। 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में अनेक लोगों को सजायें हुयी।[79]

21 अक्टूबर 1940 को बांसगांव में पं० रामचंद्र शर्मा ने (अखिल भारतीय हिन्दू आदर्श संघ के संस्थापक) क्षत्रियों द्वारा देवी दुर्गा को बैल का बलिदान करने पर विरोध में आमरण अनशन शुरू किया। कुछ स्थानीय लोगों ने क्षत्रियों को ऐसा न करने की सलाह दी।[80]

21 मई 1941 को गोरखपुर में पहली बार 9.15 पी०एम० 10.15 पी० एम० तक ब्लैक आउट रहा।[81]

1930 से 34-35 तक गोरखपुर में लगभग हर क्षेत्र में अच्छे कार्यकर्ता उभर कर आये। इनमें रामधारी पाण्डे, डा० शिवरत्न लाल, रामप्रसाद, शिब्बन लाल सक्सेना, राम जी सहाय, सूर्य बली पाण्डे, राम अवध सिंह, उमाशंकर ओझा, बाबू बसंत लाल, गप्पू लाल, महेश चंद्र, ब्रह्मदेव नारायण

---

77. पुलिस विभाग - फाइल नं० 211, बाक्स नं० 80 पुलिस विभाग द्वारा प्रान्त के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया गोपनीय पत्र।
78. वही - पृ० 44
79. वही - पृ० 44
80. पायनियर - 12 अक्टूबर 1940 पृ० 5
81. पायनियर - 23 मई 1941 पृ० 3

सिंह, पंचमन मिश्र, सत्य नारायण सिंह, दिलदार हुसैन, नियामत उल्लाह, इकाम इलियास प्रमुख थे ।[82]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये गोरखपुर बलिया, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़ में लोकगीतों की रचना हुयी । इसमें कांग्रेस के कार्यक्रमों और नीतियों की व्याख्या की गयी -

1. गंगा नहइली बड़े भोर त सौरोज मनाइली ।
2. हमरे चरखा क साथ लागे । चरखा हम चलाइ हो राम ।
3. गांव में हमरे कांग्रेस के कुमेटी उहवां झंडा गड़ल बारे ।
4. खादी के आइल जमाना बलम जेलखाना पकड़ि गये
5. गांधी बाबा सरकार के हैरान कइले बा ।
6. सोखजवा के कारन लोइवे फकोर, सारी विदेसी मोहे मन ही न भावे लउकेला ओमें मोरा सगरे सरीर ।[83]

---

82. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर - पृ० 21
83. कांग्रेस कार्यकर्ता अंगुर त्रिपाठी की डायरी । पहले ये कांग्रेस की सभाओं में गाये जाते थे । धीरे - धीरे ये घर - घर में गाये जाने लगे । इन गीतों के माध्यम से कांग्रेस की नीतियों व कार्यक्रमों का जनसाधारण में आसानी से प्रचार हो गया ।

पूर्वी क्षेत्र में क्रान्ति का बीज बोने में हिन्दी पत्रकारिता ने अहम् भूमिका अदा की। 'आज' दैनिक पत्र का व्यापक प्रभाव था। 'खादी अपनाओं' अभियान पर आज ने टिप्पणी की -

"खादी की बिक्री बढ़े तो,
विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सफल हो जाय,
बहिष्कार सफल हो तो स्वराज्य मिले,
इसलिये खादी की बिक्री बढ़ने से
स्वराज्य की दूरी घटती है।[84]

पहली जनवरी 1931 के सम्पादकीय स्तम्भ में लिखा गया-।

देश की दरिद्रता, विदेश जाने वाली लक्ष्मी, सर पर बरसने वाली लाठियां, देशभक्तों से भरने वाले कारागार, इन सबको देखकर प्रत्येक देशभक्त के हृदय में अहिंसा मूलक जो विचार उत्पन्न हों, वही सम्पादकीय विचार हैं।[85]

प्रेस एक्ट द्वारा विचार स्वतंत्र के अपहरण पर आज के पूरे पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में यही लिखा प्राप्त होता है -

समाचार पत्रों पर प्रहार, लेखन स्वातंत्र्य हरण करने वाला कानून बड़ी व्यवस्थापक सभा में बनाया जा रहा है, उसी के विरोध मे आज अग्रलेख टिप्पणियां नहीं लिखी गयीं।[86]

---

84. 'आज' दैनिक - 9 जनवरी 1931
85. 'आज' दैनिक - 1 जनवरी 1931
86. 'आज' दैनिक - 30 सितम्बर 1931

1931 के चुनाव में 'आज' ने कांग्रेस के समर्थन को स्वतंत्रता प्राप्ति का एक अंग माना तथा अपने पाठकों से अपील की -

> करेंगे जा के वह कौंसिल में गुफ्त गुए वतन
> न मिटने देंगे कभी दिल से आरजू-ए-वतन
> मिटा के अपने को रखेंगे आबरू-ए-वतन
> गुले उन्माद में उनके रहेगा बू-ए-वतन ।[87]

'स्वदेश' अपने समाचारों टिप्पणियों से पाठकों में स्वाधीनता का मंत्र फूंकने के लक्ष्य में लगा था । 8 मई 1921 के अंक में लिखा - स्वदेश तुम्हें संदेश दे रहा है कि तुम भी मनुष्य हो, तुम्हें भी ईश्वर के यहां से समान अधिकार प्राप्त है । उनमें भी उन्नति करने की, गौरवशाली बनने की शक्ति मौजूद है । उठो, उससे काम लो । हिम्मत मजबूत करो, परमात्मा तुम्हारे सहायक होंगे ।[88]

'स्वदेश' के अतिरिक्त 1932 में गोरखपुर से 'जीवन' साप्ताहिक पत्र निकलता था । 1939 में गोला (गोरखपुर) से 'वसुन्धरा' राष्ट्रीय मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ । पत्र के प्रकाशन का लक्ष्य भारतीय संस्कृति का उत्थान ही था । अपनी स्वतंत्रता व संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस पत्रिका का आविर्भाव हुआ है ।[89]

वसुन्धरा के प्रथम पृ० पर लिखा रहता था -

> वह व्यर्थ ही जनमा जगाया जिसने देश को नहीं,
> जातीय जीवन की झलक, आई कभी जिसमें नहीं ।[90]

---

87. तिवारी, डा० अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में) पृ० 298
88. तिवारी डा० अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन व हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में) पृ० 79
89. वही - पृ० 165, 166
90. वही - पृ० 166

प्रेस एक्ट द्वारा कड़ी पाबन्दी लगा देने के बाद स्वतंत्रता आन्दोलन का समाचार देने के लिये साइक्लोस्टाइल या हाथ से लिखे समाचार पत्र प्रकाशित करने की योजना बनायी गयी । काशी विद्यापीठ के अध्यापक राजा राम शास्त्री के निर्देशन में गोरखपुर से 'बवंडर' नामक साइक्लोस्टाइल पत्र का प्रकाशन 1932-33 में किया गया । बवंडर का मोटो था -

आंसू उमड़ रहे थे, हवा में बदल गये,
टिकता है कहां बांध, समंदर के सामने
जिस अग्नि आर्डिनेन्स ने पैदा किया गुबार
तिनका सा उड़ रहा है बवंडर के सामने ।

श्री सत्यनारायण सिंह की गिरफ्तारी के बाद इसका प्रकाशन स्थान बदल दिया गया । धर पकड़ में कृपाशंकर उपाध्याय पकड़ में आये । असह्य यंत्रणा देने के बाद भी पुलिस उनसे भेद पाने में असफल रही । सत्याग्रह आन्दोलन के बाद ही इसका प्रकाशन बन्द हुआ ।[91]

द्वितीय महायुद्ध के दौरान 'गोरखपुर अखबार' साप्ताहिक था, कुछ दिन तक दैनिक रूप में भी प्रकाशित हुआ । यह पूर्णतः सरकारी पत्र था ।

1939-44 तक 'अप्सरा' पत्र प्रकाशित हुआ । 'गोरख' नामक साप्ताहिक पत्र 5-6 अंकों तक ही अपना अस्तित्व रख सका । 'गोरखपुर गजट' त्रिशूल 'प्रदीप' (साप्ताहिक), किसान संदेश (साप्ता०) सरयूपारीण (मासिक) शंकर (साप्ता०) क्रान्तिकाल में कुछ पत्रों को वहाँ वहाँ के वासियों द्वारा सुना जाता है, पर इन पत्रों की प्रतियां नहीं मिलती ।[92]

---

91. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय-गोरखपुर पृ० 19-20
92. तिवारी, डा० अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन व हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ० प्र० के सन्दर्भ में) पृ० 177

समाचार पत्रों, पत्रिकाओं से जन साधारण में कुछ जागृति आयी। इसका प्रमाण है सनहा काण्ड, मैथौली काण्ड, भरोटिया गांव की लड़ाई गौरी बाजार का झण्डा सत्याग्रह।[93]

गांधी जी के हरिजन आन्दोलन से सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आन्दोलन को नयी दिशा मिली। स्थान-स्थान पर सभायें हुयीं तथा लोगों ने सत्यनारायण पूजा के बाद हरिजनों के हाथ से प्रसाद खाया। 25 सितम्बर को गोरखपुर में एक विशाल सहभोज हुआ, इसमें 2,000 से ऊपर हरिजन थे। गोविन्द पुर गांव में सभी भाइयों के लिये मन्दिर खोल दिये गये। गांधी जी की दीर्घायु के लिये प्रार्थना की।[94]

सरकार के दमन के बावजूद आन्दोलन चलते रहे। 1941 में सत्याग्रही कैदी बढ़ गये थे। यह अब जन-आन्दोलन होता जा रहा था।[95]

---

93. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय गोरखपुर - पृ० 20
94. वही, पृ० 21-22
95. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ० 446

स्वतंत्रता संग्राम का अन्तिम चरण:1942- 47 :

भारत वर्ष के इतिहास में अगस्त सन् 1942 की क्रान्ति एक महान चिरस्मरणीय घटना है। इस क्रान्ति ने ब्रिटिश भारत के इतिहास में ऐसी भंवर उथल पुथल कर दी कि ब्रिटिश सिंहासन भी डोलायमान हो उठा।[1]

मार्च 42 में रंगून जापानियों के हाथ में चले जाने से भारत के सीमांतों पर खतरा पैदा हो गया था।[2] ब्रिटिश सरकार यह समझने लगा था कि युद्धोद्योग में कांग्रेस का सहयोग पाना चाहिये। 11 मार्च को क्रिप्स मिशन का घोषणा हुआ। इसके प्रस्तावों का आशय था कि 'कांग्रेस युद्ध में मदद दे तभी जापानियों का सामना किया जा सकेगा। भारत वर्ष एक यूनियन बने, युद्ध समाप्त होने के बाद ही भारत को जिम्मेदार सरकार दी जायेगी। प्रान्तों व रियासतों को स्वतंत्रता दी गयी थी कि जब वे चाहें तभी यूनियन में शामिल हों।[3] सभी राजनीतिक दलों ने इसे अस्वीकृत किया।[4] केवल मुस्लिम लीग अपवाद था।[5]

क्रिप्स मिशन की असफलता से गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि जब तक तीसरा व्यक्ति मौजूद है, राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया कि वे या तो शान्ति से भारत छोड़ जायें या फिर जनता द्वारा शुरू किये जाने वाले सविनय अवज्ञा के परिणामों का सामना करें।

---

1. व्यास, दीनानाथ - अगस्त सन् '42 का महान विप्लव' - पृ० 1
2. विपिनचंद्र, त्रिपाठी- अमलेश व दे बरूण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ० 210
3. गुप्त, मन्मथनाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, पृ० 447-448
4. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे, बरूण स्वतंत्रता संग्राम- पृ० 211
5. वही, पृ० 212

शुरू में कार्य समिति के कई सदस्य नेहरू, आजाद, पन्त, सैयद मुहम्मद और आसफ अली ने ऐसे कदम का विरोध किया। पर जब गांधी जी ने धमकी दी कि वे कांग्रेस छोड़ देंगे और भारत की बालू से ऐसा आन्दोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तब उन लोगों को गांधी जी की बात माननी पड़ी।[6]

14 जुलाई को कांग्रेस कार्य समिति ने 1700 शब्दों का प्रस्ताव रखा। समिति ने मांग की कि ब्रिटेन फौरन सत्ता भारतीयों को सौंप कर भारत छोड़ दे। अगर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस न चाहते हुये भी 1920 से अर्जित अपनी सारी अहिंसक शक्ति का इस्तेमाल करके सीधी कार्यवाही का आन्दोलन शुरू करेगी।[7]

यद्यपि गांधी जी ने आन्दोलन की धमकी दी थी, पर उन्हें विश्वास था कि वायसराय से अच्छे व्यक्तिगत सम्बन्ध होने के कारण समझौते की बात हो सकती है। परन्तु अंग्रेज लोग राजनीति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। लार्ड लिनलिथगो तथा गांधी जी के सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण थे। पर 'भारत पर ब्रिटिश शासन' का प्रश्न आने पर वायसराय ने समझौते का मार्ग छोड़ कर धोखा और विश्वासघात का काम किया। हमें यह जान लेना चाहिये कि हमारा शत्रु केवल राजनीति की कला जानता है। उसने हजारों निहत्थे भारतीयों को मरवाया।[8]

जिस समय 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई में कार्य समिति के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, उस समय लंदन में युद्ध समिति ने भारत सरकार की कांग्रेस के विरुद्ध कार्यवाही की प्रस्तावित योजना

---

6. चौधरी, सन्ध्या, गांधी एण्ड दी पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ० 95
7. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ० 449-450
8. पुलिस विभाग - फाइल नं० 631. बाक्स नं० 83. "आरगेनाइजरिबेलियन" डा० राम मनोहर लोहिया

को मंजूरी दे दी । इस योजना के अनुसार - कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन होने पर गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, प्रान्तीय तथा सभी अखिल भारतीय समितियों को गैर कानूनी घोषित करना तथा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर के उसकी कार्यवाहियों से निपटने के लिये इमरजेन्सी पावर आर्डीनेन्स लागू करना था ।[9]

कुछ प्रमुख नेताओं ने गांधी जी को ऐसा कठोर कदम उठाने से रोकना चाहा, पर गांधी जी ने अपना निश्चय नहीं बदला ।[10]

बम्बई में कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में मशहूर 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास हुआ । काफी वाद-विवाद के बाद रात 10 बजे यह प्रस्ताव पास हुआ, इसमें तत्काल ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग की गयी । मुस्लिम लीग से वादा किया गया कि ऐसा संविधान बनेगा जिसमें संघ में शामिल होने वाली इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता मिलेगी तथा बचे हुये अधिकार उसी के पास रहेंगे ।[11]

यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो समिति अहिंसक ढंग से, जहां तक सम्भव हो सके, व्यापक धरातल पर जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है -------- यह संघर्ष अनिवार्यतः गांधी जी के नेतृत्व में होगा ।[12] इसमें 'करो या मरो' का नारा दिया गया, जो कि चिंगारी सिद्ध हुआ ।[13]

9 अगस्त की सुबह गांधी जी तथा अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गये । सारे ब्रिटिश भारत में कांग्रेस के संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया ।[14]

---

9. मिश्रा, गोविन्द - कांस्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919-47) पृ० 177
10. चौधरी, सन्ध्या - गांधी एन्ड दी पार्टीशन आफ इंडिया - पृ० 96
11. विपिनचंद्र, त्रिपाठी, अमलेश व दे, बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ० 215
12. मिश्रा, गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन्डिया (1919-47) पृ० 178
13. गुप्त, मन्मथ नाथ - राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास - पृ० 452
14. मिश्रा, गोविन्द- कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इनडीया (1919- 47) पृ० 179-180

कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से जो शून्य उत्पन्न हुआ, उससे लाभ उठा कर जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक मजबूत पार्टी बनाया। लीग ने मुसलमानों को आन्दोलन से दूर रहने की सलाह दी।[15] माइकेल ब्रेचर तथा मजूमदार ने तो यहां तक कहा कि भारत छोड़ो आन्दोलन ने पाकिस्तान निर्माण का रास्ता तैयार किया।[16]

स्वतंत्रता प्राप्ति के चौदह साल बाद नेहरू जी ने 1942 की घटनाओं को याद करते हुये कहा कि उस समय कांग्रेस के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। यदि उस समय शान्ति से काम लिया गया होता तो हमारी सारी शक्ति नष्ट हो गयी होती।[17]

जैसे ही नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार देश में फैला, जनता में रोष भड़क उठा। वे लोग आन्दोलन के लिये तैयार थे पर क्या करना है - इसका कुछ पता नहीं था। इसी समय बी०बी० सी० पर राज्य सचिव एमरी द्वारा एक भाषण दिया गया जिसमें उन कार्यों के बारे में बताया गया जो कि कांग्रेस भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान युद्ध के प्रयत्नों को नुकसान पहुंचाने के लिये कर सकती थी। इससे जनता को यह अहसास हो गया कि किन कार्यों से ब्रिटिश शासन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।[18]

अगस्त क्रान्ति के कार्यों को यदि सही शब्द दिया जाय तो वह अव्यवस्थित करना (dislocations) होगा, न कि जान बूझ कर तोड़-फोड़ द्वारा जनहानि करना (Sabotage)। हमारे कार्यक्रम का मुख्य सिद्धान्त है। "किसी को मारना नहीं है, किसी को घायल नहीं करना है।

---

15. चौधरी, सन्ध्या - गांधी एन्ड दी पार्टिशन आफ इण्डिया, पृ० 98-99
16. वही - पृ० 101
17. वही - पृ० 102
18. चटर्जी, जे०सी० - इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन कान्फ्रेंस - पृ० 32

जब तक निहत्थे लोगों का दल किसी को मारे या घायल किये बिना अव्यवस्थित करने के कार्य में लगा है, तब तक आन्दोलन निःसन्देह अहिंसा पर आधारित है। योरप के देशों की तरह यहाँ पर सैनिकों से भरी ट्रेनों या सैनिक छावनियों पर बम फेंकने जैसे कार्यों को नहीं अपनाया गया।[19]

लगभग हर बड़े शहर में प्रदर्शन हुये। छात्रों, श्रमिकों, दुकानदारों घर की महिलाओं सभी ने गलियों, सड़कों पर जुलूस निकाले। राष्ट्रीय गीत गाये जाते थे तथा गांधी जी व कार्य समिति के नेताओं को आजाद करने की मांग की जाती थी। शुरू में प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था, पर तनाव था और सरकार घबरा रही थी। संयुक्त प्रान्त में पुलिस ने 9-21 अगस्त के बीच 29 बार गोली चलायी, 76 लोग मारे गये तथा 114 गम्भीर रूप से घायल हुये।[20]

जल्दी ही परिस्थिति नियंत्रण के बाहर हो गयी। छात्र कालेजों व विश्वविद्यालयों से बाहर आ गये, उनके मन में हिंसा व अहिंसा को लेकर कोई नैतिक ऊहापोह नहीं था।[21] ब्रिटिश शासन का प्रतीक समझे जाने वाले पुलिस थानों, डाकखानों रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किये गये। आग लगायी गयी। टेलीफोन का तार काटने व रेल की पटरियां उखाड़ने की कोशिश हुयी। किसानों को कर न चुकाने के लिये कहा गया।[22]

1942 की जनक्रान्ति में उत्तर प्रदेश ने जो ऐतिहासिक चमत्कार किया वह यह था कि आन्दोलन गांधी वादी दृष्टिकोण से भी शत प्रतिशत पूर्ण था, और सशस्त्र दृष्टि से भी। उसके शहीदों की गाथा उसके गांधी वादी पक्ष पर और उसके विस्फोटक कार्य उसके सशस्त्र क्रान्ति के पक्ष पर पूरी रोशनी डालते हैं।[23]

---

19. पुलिस विभाग - फाइल नं0 631, पृ0 83 ‌‌(नाट सैबोटेज बट डिसलोकेशन') डा0 राम मनोहर लोहिया।
20. मिश्रा, गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919-47) पृ0 181
21. राम गोपाल - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास - पृ0 423
22. विपिनचंद्र, त्रिपाठी, अमलेश व दे, बरुण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 216
23. मिश्र, कन्हैया लाल - उ0प्र0 स्वाधीनता संग्राम की एक झाँकी - पृ0129

पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत खराब थी । मैक्स हार्ट कोर्ट ने अपने अध्ययन Congress And The Raj -316-21 में कहा है 'पूर्वी उत्तर प्रदेश के छ: जिले आन्दोलन से प्रभावित रहे । ये थे - बलिया, गाजीपुर, वाराणसी आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर ।[24]

10 सितम्बर 1942 तक आन्दोलन ने अपने अन्तिम चरण में प्रवेश किया । बिहार व पूर्वी उ0प्र0 मुख्य रूप से प्रभावित जिले थे ।[25]

आन्दोलन ने हिंसा का रूप ले लिया था । जनता ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ने में लग गया था । अप्रैल 1943 तक यह आन्दोलन चला ।[26]

सन् 1942 की क्रान्ति में गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का अगुआ रहा है ।[27] 11 अगस्त से ही गांव वालों को आन्दोलन की रिपोर्ट 'आज' और 'संसार' नामक हिन्दी के दैनिकों से मालूम होने लगी थी ।[28] जिले में यह लगभग हर जगह हड़तालों, विरोधी सभाओं, जुलूसों तथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 144 के आदेशों का विरोध करने से शुरू हुआ । 9 अगस्त को आन्दोलन शुरू होने के दो - तीन दिन के अन्दर ही जिले के महत्वपूर्ण नेता जेल में बन्द कर दिये गये ।[29]

16 अगस्त 1942 को शिब्बन लाल सक्सेना ने बचे-खुचे कार्य कर्ताओं के साथ आन्दोलन की योजना बना डाली । 21 अगस्त 42 की रात में पूरे जिले की पटरियां उखाड़ने व व्यर्थ करने का निश्चय कियागया, थानों, डाकखानों, सरकारी खजानों पर भी कब्जा करने का लक्ष्य था । 21 अगस्त को हवंस लीला

---

24. लिमये, मधु - स्वतंत्रता आन्दोलन की विचार धारा - पृ0 114
25. मिश्रा, गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919-47) पृ0 184-185
26. वही - पृ0 188
27. तिवारी, डा0 अर्जुन - स्वतंत्रता आन्दोलन व हिन्दी पत्रकारिता (पूर्वी उ0प्र0के सन्दर्भ में) पृ0 106
28. व्यास, दीनानाथ - सन् 42 का महान विप्लव- पृ0 126
29. सहाय, गोविन्द - सन् 42 का विद्रोह - 247.

के लिये भाटपार रानी, सलेमपुर, तुर्तीपार बरहज बाजार, नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, हाटा, हैसमपुर, पडरौना, सेवरही, पुदहा, खड्डा तथा सिसौना को चुना गया था ।[30]

21 अगस्त 42 को कसया रोड के खजुआं पुल को पांच घंटे के परिश्रम के बाद तोड़ दिया गया । सड़कों के पुल तो तोड़े गये, पर रेलवे लाइनों पर कम काम हुआ । इसका कारण था संगठन व जानकारी की कमी । दूसरा कारण था इन कार्यकर्ताओं का आकाश भेदी नारे लगाना । शासनतंत्र सजग हो जाता था तथा इसका परिणाम दुःखद होता था ।[31]

गोरखपुर के कलेक्टर व एस0पी0 को 22 अगस्त की शाम तक सारा कार्यक्रम पता चल गया था । छोटा गंडक व खनुआ के बीच के भू भागने संतोष-प्रद कार्य किया । अयोध्या प्रसाद व रामवृक्ष कुंअर के नेतृत्त्व में जत्थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे । नया शासन व नया पंचायत कायम करते थे । स्वतंत्रता का यह वातावरण मात्र 48 घन्टे रहा ।[32]

जनपद के कार्यकर्ताओं द्वारा अविचलितभाव से स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया । पडरौना, बरहज बाजार, भाटपार रानी, बेख्घाट, दोहरियां, अंसगांव, महाराजगंज के गोलाकाण्डों में शहीद व घायल स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी अन्तकाल तक प्रेरणा देती रहेगी ।[33]

बरहज बाजार, दोहरिया काण्ड, बनरही काण्ड, भाटपार रानी, खोपापार आदि जगहों पर हुये गोली काण्डों में कई लोग मारे गये तथा घायल हुये ।[34]

---

30. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक-संक्षिप्त परिचय-गोरखपुर - पृ0 23 - 24
31. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर - पृ0 24
32. वहीं ; पृ0 24 - 25
33. वहीं ; पृ0 25
34. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर - पृ0 25,26,27

वास्तविक दमन । सितम्बर से शुरू हुआ । ककरहा गांव के पंडित रामलखन का मकान लूटा गया ।[35]

गोपाल पुरा के लाल नारायण चंद्र का मकान लूटा गया, उनके 11 मास के पुत्र को जबरदस्ती थाने में रखा गया, जहां दूध के अभाव में बच्चा मर गया । यह राजा साहब का इकलौता पुत्र था ।[36]

गोकुल पुरा गांव में केशभान राय नामक कांग्रेसी को गिरफ्तार कर उनके मकान व जायदाद को जला कर राख कर दिया गया ।[37]

ओपापार में प्रसिद्ध कांग्रेसी रामबली मिश्र की पत्नी श्रीमती कैलाशवती मिश्र को बाल पकड़ कर घर से खींच कर निकाला गया, उनके कपड़े फाड़ दिये गये ।[38] रामलखन पान्डे व उसके दो बेटों को बेंत से पीटा गया तथा जब तक वे बेहोश नहीं हो गये, बन्दूक के कुंदे से मारा गया ।[39]

टांडा में पुलिस द्वारा भयंकर अत्याचार किये गये, मकान लूटे गये, जलाये गये, स्त्रियों की बेइज्जती की गयी, बलात्कार के भी काण्ड हुये । उरुवा बाजार में पुलिस ने लोगों को रस्सी से बांधकर खींचा ।[40]

मदरिया गांव में राम अलख सिंह व बलराम के घर जला दिये गये, उन पर जुर्माना किया गया तथा हर को 10-10 कोड़े की सजा दी गयी ।[41]

बांस गांव तहसील में प्राय: एक लाख रुपये की क्षति हुयी ।[42] 1942 में जिले के 145 से अधिक लोग बन्दी बनाये गये तथा 58 को सजा हुयी ।[43]

---

35. व्यास, दीना नाथ – अगस्त सन् 42 का महान विप्लव – पृ0 127
36. वही ; पृ0 127
37. वही ; पृ0 127-128
38. वही ; पृ0 128
39. सहाय, गोविन्द – सन् 42 का विद्रोह – पृ0 248
40. व्यास, दीना नाथ – अगस्त सन् 42 का महान विप्लव – पृ0 129
41. सहाय गोविन्द – सन् 42 का विद्रोह – पृ0 248
42. व्यास, दीनानाथ – अगस्त सन् 42 का महान विप्लव – पृ0 130
43. डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर आफ गोरखपुर – 1985– पृ0 45

यहां से 2•19,170 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गये ।[44]

गोरखपुर जिले ने इंडियन नेशनल आर्मी को सैनिक दिये । मगहर से केदार सिंह कुरविया, मनीपुर से जंगी सिंह तथा चौरी चौरा से करनाल सिंह ।[45]

शासन तंत्र ने अपनी गति तेज की तथा पूरे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मच गयी । शिब्बन लाल सक्सेना पकड़े गये । गोरखपुर षड्यंत्र केस उन पर चलाया गया । इस सम्बन्ध में रामपति सिंह, अकबर सिंह, डा० शिवरतन लाल, हरिशंकर गुप्ता तथा राम लुटावन सिंह को दंडित किया गया ।[46]

बाबा राघवदास ने स्वयं को गिरफ्तार न करा के फरारी हालत में देश के विभिन्न भागों का दौरा करके ऐतिहासिक सेवा की ।

अगस्त आन्दोलन की वर्षगांठ मनाने का साहसपूर्ण आयोजन बाबा जी का ही था । उन्हीं के प्रयत्न से 3 अप्रैल 1943 को लखनऊ में कौंसिल हाउस के सामने मर्यादा तिवारी के नेतृत्व में 14 स्वयंसेवकों ने तिरंगे सहित स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा दुहराया ।

जिले के प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता बाबा राघवदास मद्रास, अहमदाबाद, बंगाल हर जगह पार्टियों के साथ नजर आये । मेरठ में श्री राम शर्मा के नेतृत्व में उन्हीं से प्रेरित भाई ने वाइसराय के भवन के सामने नारे लगाये । 23 जुलाई 1944 को गांधी जी ने छिपे कार्यकर्ताओं से आत्म समर्पण करने को कहा । 7 अगस्त 44 को वे लखनऊ में चार बाग स्टेशन पर गिरफ्तार किये गये ।[47]

44• वही : पृ0 45
45• चोपड़ा, पी0 एन0 (सं0) हू इज हू ऑफ इन्डियन मार्टियर्स, भाग II पृ028, 131, 146,
46• स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक - संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर - पृ0 27•
47• वही : पृ0 28

दो वर्ष। तक जेल में रहे। अप्रैल 46 में रिहा किये गये।[48]

भारत छोड़ो आन्दोलन में बाबा राघवदास उत्तर प्रदेश के संचालक थे।[49]

वाराणसी के अतिरिक्त गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर मिर्जापुर का दौरा कर आन्दोलन को संगठित किया तथा तोड़ फोड़ के कार्यों का भी नेतृत्व किया।[50]

1942 के आन्दोलन में उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध तथा भारत की स्वतंत्रता से संबंधित कई पर्चे बंटवाये। गोरखपुर से बरामद हुये पर्चे में ब्रिटिश सरकार के पिट्ठुओं जमींदारों और पटवारियों को सरकार के दमन कार्य में सहयोग देने के विरुद्ध चेतावनी दी गयी थी। 1मार्च 1944 को उनकी ओर से प्रकाशित 'आजाद भारत' की प्रतियां लखनऊ, सुल्तानपुर व नैनीताल में पायी गयी। अलीगढ़ व देहरादून से भी पुलिस ने बाबा राघवदास द्वारा जारी किया गया एक पर्चा बरामद किया। इसमें राष्ट्रीय सप्ताह के आयोजन के लिये सात सूत्री कार्यक्रम था।[51]

गोरखपुर में धरमपुर गांव में पुलिस ने हिंसात्मक कार्यवाही के लिये एकत्र बम, विस्फोटक सामग्री तथा तोड़ फोड़ करने का सामान बरामद किया, 20 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।[52]

1857 के बाद 1942 का 'भारत छोड़ो आन्दोलन' ब्रिटिश शासन के लिये सबसे बड़ी चुनौती था। यद्यपि यह आन्दोलन सफल नहीं रहा, पर इसके

---

48. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, संक्षिप्त परिचय - गोरखपुर - पृ० 28
49. बाबा राघव दास स्मृति ग्रन्थ - पृ० 16,53,66
50. आज - 29 जनवरी 1958, पृ० 4 (42 में बाबा जी को पुलिस नहीं पकड़ सकी) ले० सच्चिदानन्द त्रिपाठी,
51. गुप्तचर विभाग के अभिलेख - 1944
52. गहलोत, बी० एस० - पूर्वी उ० प्र० में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय - पृ० 166

द्वारा ब्रिटिश शासन का अन्त आया । इसने विजेता ब्रिटिश सरकार को हतोत्साहित तथा पराजित विद्रोहियों को और अधिक दृढ़ निश्चय वा बनाया । यह विद्रोह विदेशी शासन के विरूद्ध एक खुला विद्रोह था ।[53]

1942 का विद्रोह सफल नहीं हुआ क्योंकि बिना नेतृत्व वाली असंगठित व निहत्था जनता साम्राज्यवादी सरकार की बड़ी शक्ति से नहीं जीत सकती थी । इस क्रान्ति ने साम्राज्यवाद के विरूद्ध भारत के आक्रोश तथा स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली तथा सुनिश्चित ढंग से व्यक्त किया । ब्रिटिश शासक अच्छी तरह समझ गये कि भारत में अब गिने चुने दिनों का साम्राज्यवादी शासन रह गया है ।[54]

वायसराय ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि उनके 8 अगस्त के 'करो या मरो' (Do or Die) के नारे के कारण ही आन्दोलन में हिंसा आयी । गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मंत्र केवल अहिंसा के सन्दर्भ में था । इसने हिंसा को नहीं भड़काया - जैसा कि सरकार समझती है ।[55]

आन्दोलन तीन मुख्य कारणों से असफल रहा -

1. संगठन व योजना बनाने में असावधानी
2. नौकरी के प्रति वफादारी (सरकार के प्रति प्रशासन तंत्र का वफादार रहना
3. सरकार के पास बेहतर सैन्य शक्ति थी ।

---

53. हटचिन्स, फ्रेंसिस जी० - स्पोन्टेनियस रिवोल्यूशन 'दि क्विट इंडिया मूवमेन्ट पृ० 341, 342,
54. विपिन चंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरूण - स्वतंत्रता संग्राम - पृ० 217
55. मिश्रा, गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवलेपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919-47) पृ० 194

इस आन्दोलन में धनी तथा उच्च वर्ग संघर्ष से अलग रहा । छात्रों व मध्यम वर्ग ने संघर्ष का नेतृत्व किया । डा० अम्बा प्रसाद के शब्दों में 'यह छात्र' किसान, मध्यम वर्ग का विद्रोह था । छात्रों ने नेतृत्व किया तथा किसानों ने लड़ने का काम किया ।[56]

यह जनसाधारण का विद्रोह था । जनसाधारण के विद्रोह से ही देश आजाद होता है ।[57]

यह विद्रोह एक तरह से भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की समाप्ति का परिचायक है । अब सिर्फ यह प्रश्न तय करना रह गया था कि सत्ता का हस्तांतरण किस तरीके से हो और स्वतंत्रता के बाद सरकार का स्वरूप क्या हो ? इसमें सन्देह नहीं कि 1942 के विद्रोह तथा 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बीच के समय में सांठ गांठ बैठाने और सौदेबाजी करने के कई प्रयास हुये तथा राजनैतिक परिवर्तन हुये । पर अबयह सन्देह नहीं रह गया था कि स्वतंत्रता संग्राम अपनी समाप्ति पर था और विजय मिलने वाली थी ।[58]

1942 के आन्दोलन को दबा देने के बाद से 1945 तक युद्ध के समाप्त होने तक देश मे मुश्किल से ही कोई राजनीतिक गतिविधि रही । सारे लोकप्रिय नेता जेल में थे और परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि नया नेतृत्व सामने आ सके । राष्ट्रीय आन्दोलन में ठहराव आ गया था ।[59]

मार्च 1942 में श्री हरिहर नाथ शास्त्री की अध्यक्षता में गोरखपुर में वाना के श्रमिकों का दूसरा सम्मेलन हुआ था । इसमें कांग्रेस के उस प्रस्ताव का समर्थन किया गया जिसके द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गयी थी और तब युद्ध में समर्थन करने की बात कही गया था ।[60]

---

56. मिश्रा, गोविन्द - कान्स्टीट्यूशनल डेवलेपमेन्ट एन्ड नेशनल मूवमेन्ट इन इंडिया (1919 -47) पृ0 195-196
57. दास, दीनानाथ - अगस्त सन् '42 का महान विप्लव' पृ0 29
58. त्रिपाठी, अमलेश, विपिन चंद्र तथा दे, बरुण - स्वतंत्रता संग्राम, पृ0 217
59. वही - पृ0 219
60. पायनियर - 21 1942 - पृ0 4

जुलाई 1942 को संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की सभा गोरखपुर में हुआ। इसमें लिये गये निर्णय गोपनीय रखे गये केवल एक प्रस्ताव प्रेस को दिया गया। समिति ने गांधी जी के कदम की (भारत छोड़ो आन्दोलन) तथा देश की स्थिति पर बहस की। अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर भी विचार किया गया।[61]

मई 1943 में जिले के सदर तहसील के प्रमुख जमींदारों की सभा हुयी। इसकी अध्यक्षता खान साहब, श्री एच० ए० सिद्दीकी ने की। इसमें जमींदारों को सलाह दी गयी कि वे अपनी आवश्यकता से अधिक की अनाज, खास तौर से गेहूँ, अधिकारियों को दे दें। ऐसा समझा गया कि जमींदार ऐसा करने को तैयार हो गये।[62]

संयुक्त प्रान्त सरकार की सस्ता अनाज योजना के अन्तर्गत सीमित आहार का वितरण सर्वप्रथम गोरखपुर जिले में लागू किया गया। जिलाधीश श्री जे० एल० सी० स्टूब्स और अन्य सरकारी अधिकारियों ने शहर के आटा मिलों और दुकानों का निरीक्षण किया। इस योजना से 25,000 निवासियों को मदद मिलने की सम्भावना थी। अधिकारियों ने दस सरकारी दुकाने खोलीं जिन्होंने आटा और चावल बेचा।[63]

अगस्त 1943 में श्री शिब्बन लाल सक्सेना और 21 अन्य लोगों पर डकैती, तोड़ फोड़ तथा अन्य क्रान्तिकारी कार्यों के लिये मुकदमा चलाया गया।[64]

---

61. पायनियर, 3 जुलाई 1942 - पृ० 3
62. पायनियर - 14 मई 1943 - पृ० 5
63. पायनियर - 11 जुलाई 1943 - पृ० 7
64. पायनियर - 6 अगस्त 1943 - पृ० 5

सितम्बर 1943 में निर्देश दिया कि
क्तरक अब लाइसेंस के अन्तर्गत इस
15 दिन के अन्दर वे सब अपना

का आमारी महामारी के रूप में फैली ।
की खबर मिली ।[66]

अक्टूबर 1943 में गा..जपुर में धारा 144 लागू कर दी गयी । इसके अनुसार लोगों पर लाठी, भाला, तलवार, चाकू ले कर चलने तथा आपत्तिजनक गीतों के गाने और झूठी अफवाह फैलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । यह आदेश 20 अक्टूबर तक लागू रहा ।[67]

इंडियन पीनल कोड की धारा 224 के अन्तर्गत एक क्रान्तिकारी कैलाश पति को ^दो^ वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गयी । उस पर आरोप लगाया गया कि 20 मार्च 1943 को वह एक अन्य कैदी बलरूप शर्मा के साथ रात को दो बजे गोरखपुर जेल से निकल कर भाग गया था । उन लोगों पर सहजनवां डकैती केस के लिये मुकदमा चल रहा था । कैलाश पति को सी० आई० डी० के ग्रुप आफीसर द्वारा 17 मई को बस्ती जिले में नेपाल की सीमा के पास गिरफ्तार कर लिया गया ।[68]

गोरखपुर क ी एक विशेष घटना गोरखपुर षड्यंत्र है । सहजनवां ट्रेन डकैती की जांच के सिलसिले में पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि शिब्बन लाल सक्सेना बहुत दिनों से जेल में बन्द पड़े हैं । फिर भी वह जेल के अन्दर से ही बाहर अपने मित्रों को पत्र भेजते रहे हैं तथा जेल से भागने की तैयारी

65· पायनियर – 9 सितम्बर 1943 पृ० 6
66· पायनियर – 15 सितम्बर 1943 पृ० 6
67· पायनियर – 6 अक्टूबर 1943 पृ० 6
68· पायनियर – 5 अगस्त 1944, पृ० 8

कर रहे हैं, पुलिस ने इस सूत्र के आधार पर राना प्रताप सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनके जरिये जेल जमादार को पत्र दिये जाते थे। राना प्रताप सिंह ने शहर गोरखपुर के बाहर धरमपुर गांव में एक मकान का पता दिया। इसमें एक कमरे के अन्दर 13 षड्यंत्रकारी गिरफ्तारी हुये। इस मकान तथा कुछ अन्य मकानों की तलाशी लेने पर तोड़ फोड़ के औजार 8 तैयार बम, बम बनाने का कुछ सामान, हजारों पर्चे तथा छापने के यंत्र बरामद किये गये। जिले भर में गिरफ्तारियां हुयीं।

षड्यंत्र का मुकदमा कुल 20 व्यक्ति अभियुक्त के रूप में पेश किये गये। सेशन जज श्री आर० पी० जेम्स ने 217 पृष्ठों के फैसले में इस बात पर तफसील के साथ लिखा कि अभियुक्तों के द्वारा अहिंसा की आड़ लिये जाने पर भी कांग्रेस के नेताओं ने जो खुला विद्रोह 'करो या मरो' का नारा दिया, उसी में हिंसा व तोड़ फोड़ अन्तर्निहित था। जज ने शिब्बन लाल सक्सेना को षड्यंत्रकारी विद्रोही करार दे कर दस वर्ष की सजा दी। सूर्य नाथ पान्डे तथा राम जी वर्मा को सात साल की सजा दी गयी। बाकी दस अभियुक्तों को तीन - तीन वर्ष की सजा हुयी।[69]

"अक्टूबर 1946 में गोरखपुर से निकलने वाली हिन्दी पत्रिका 'कल्याण' में 'बंगाल की बेटी की हृदय स्पर्शी अपील' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ। इस सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त के सी० आई० डी० के असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, ई० एम० रोजर्स को सरकार की ओर से एक गोपनीय पत्र भेजा गया। इसमें उनसे सूचना मांगी गयी कि 'कल्याण' के अक्टूबर अंक 1946 में आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के लिये उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी।"[70]

---

69. गुप्त, मन्मथ नाथ - भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास - पृ०
70. पुलिस विभाग - फाइल नं० 1116, बाक्स नं० 83, 7 जनवरी 1947 को संयुक्त प्रान्त की सरकार द्वारा सी० आई० डी० के असिस्टेन्ट इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस को लिखा गया पत्र। ~~पत्र सं०~~

जेल से बाहर आने के बाद गांधी जी ने 1942 के आन्दोलन की सार्वजनिक रूप से निन्दा की । उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का आन्दोलन नहीं था ।[71]

सरकार की पाशविक हिंसा का विरोध तथा आत्म शुद्धि के लिये महात्मा गांधी ने जेल में 10 फरवरी 1944 को 21 दिन का उपवास रखा । उनकी स्थिति चिन्ताजनक होने लगी । सरकार ने उन्हें रिहा करने या समझौते की कोई भी बात तब तक करने से इंकार कर दिया जब तक कि कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव की नीति न छोड़ दे । सरकार की नीति के विरोध में वाइसराय की कार्य कारिणी परिषद के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया । महात्मा का अनशन 21 दिन बाद समाप्त हो गया । ये 21 दिन राष्ट्र के लिये व्याकुलता के थे । पर इसका मुस्लिम लीग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उनका विचार था कि यह पूर्णतया हिन्दुओं की चिन्ता का विषय है ।[72]

अक्टूबर 1943 में लार्ड लिनलिथगो के स्थान पर लार्ड वैवेल वाइसराय बने । 17 फरवरी 1944 को केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद में अपने भाषण में लार्ड वैवेल ने भारत की प्राकृतिक एकता को स्वीकार किया । जनता में यह आशा उत्पन्न की कि किसी भी समय इंगलैण्ड भारत विभाजन का पक्ष न लेगा ।

उन्होंने कहा आप भूगोल नहीं बदल सकते । सुरक्षा तथा अनेक आन्तरिक व बाह्य समस्याओं की दृष्टि से भारत एक भौगोलिक इकाई है ।[73]

---

71. चटर्जी, जे० सी० - इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन कान्फ्रेंस - पृ० 32
72. आज - 19 फरवरी 1944 - पृ० 5
73. इंडियन एनुअल रजिस्टर - 1944 पृ० 1442

कांग्रेस छोड़ने के बाद राजगोपालचारी मुस्लिम लीग से समझौता करने के कार्य में व्यस्त हो गये थे। इसके लिये राजगोपालाचारी ने जो सूत्र तैयार किया था, उसे महात्मा गांधी की स्वीकृति मिल गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी बिना शर्त रिहा कर दिये गये। केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद में विधेयक का विरोध करने में तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के सहयोग से समझौते की नयी आशायें जागृत हो गयी थीं।

मई में महात्मा गांधी की रिहाई के पहले ही से राजगोपालाचारी जिन्ना से अपनी योजनाओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। उनके रिहा होते ही राजगोपालाचारी ने अपनी योजना उनके सामने प्रस्तुत की। सितम्बर 1944 में पूरे महीने जिन्ना व गांधी राजगोपालाचारी की समझौते की वार्ता चलती रहा। समझौते के मुख्य प्रस्ताव थे -

1. मुस्लिम लीग भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ले तथा अस्थायी अन्तरिम सरकार बनाने में वह कांग्रेस का सहयोग करें।

2. युद्ध के बाद एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त व पूर्व में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेशों की सीमा का निर्धारण करें। इन प्रदेशों के अलग होने के प्रश्न के निर्णय के लिये वयस्क मताधिकार के आधार पर जनमत लिया जाय।

3. इन प्रदेशों के अलग किये जाने की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य, यातायात की सुरक्षा के लिये पारस्परिक समझौता किया जाय।

4. यह शर्तें तभी लागू होंगी जब कि ब्रिटेन पूरी शक्ति हस्तांतरित कर दें।

यह समझौता वार्ता असफल रही । जिन्ना पूरे छः मुस्लिम प्रान्तों को अलग किये जाने तथा जनमत संग्रह को मुसलमानों तक ही शामिल रखना चाहते थे । रक्षा आदि समान हितों की बातों में उन्हें समान नियंत्रण स्वीकार नहीं था ।[74]

वस्तुतः इस समय जिन्ना व महात्मा की वार्ता से जिन्ना की हठधर्मी में वृद्धि हुयी । भारतीय राजनीति में उन्हें अधिक महत्व मिल गया । यह भविष्य में भारतीय हितों के लिये दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ ।[75]

19- 20 नवम्बर 1944 को इलाहाबाद में संयुक्त प्रान्त के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुयी । इसमें रचनात्मक कार्य अपनाने पर जोर दिया गया ।[76]

यद्यपि भारत छोड़ो प्रस्ताव पर अमल करना कांग्रेस का लक्ष्य अभी भी था । 3 दिसम्बर 1944 को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित निर्दलीय कमेटी का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ । इसमें 1935 के विधान की धारा 93 के अन्तर्गत हो रहे प्रान्तीय शासन की आलोचना की गयी ।[77]

---

74. डा० ईश्वरी प्रसाद – अर्वाचीन भारत का इतिहास – पृ० 546
75. गहलौत, बी०एस० – पूर्वी उ०प्र० में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास- शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ० – 144
76. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आफ यू०पी० – 1944, पृ० – 3
77. आज – 5 दिसम्बर 1944 – पृ० – 1

साथ ही कमेटी ने सम्मेलन में पाकिस्तान योजना का विरोध इस आधार पर किया कि इससे देश की शान्ति को आघात पहुँचेगा ।[78]

मार्च 1945 में लार्ड वैवेल परामर्श के लिये इंग्लैण्ड गये । जून 45 में भारत लौटने पर भारत तथा इंग्लैण्ड में एक साथ ही भारत की संवैधानिक समस्या पर वक्तव्य प्रकाशित हुये । वाइसराय ने प्रस्ताव रखा कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद को सवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों में समानता के आधार पर पूर्णतया भारतीय बना दिया जाय । केवल रक्षा मंत्री का पद भारतीयों के हाथ में नहीं रहेगा । वैवेल ने आशा व्यक्त की कि केन्द्र से सहयोग स्थापित होने पर प्रान्तीय व्यवस्थापिका की फिर स्थापना हो सकेगी तथा परामर्शदात्री स्थापना समितियाँ समाप्त की जा सकेंगी ।

वैवेल ने आगे कहा कि ये प्रस्ताव किसी भी प्रकार भावी भारतीय संविधान पर प्रभाव न डालेंगे । वैवेल ने अपनी योजना स्पष्ट करते हुये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को रिहा करने की घोषणा की और कांग्रेस कार्यकारिणी सभा पर लगा प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया । वैवेल ने शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया । 25 जून 1945 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक बैठक में शिमला सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया ।

---

78. लीडर - 9 अप्रैल 1945 - पृ० - 1

25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन शुरू हुआ । इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग, सिक्ख, केन्द्रीय विधान सभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया । नवीन परिषद में सभी सम्प्रदायों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर सभी दल एकमत थे पर साम्प्रदायिक मत भेद के कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर समझौता न हो सका । मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की ओर से कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की जो सूची प्रस्तुत की, उसमें तीन मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ दो राष्ट्रीय मुसलमानों को भी शामिल किया ।

जिन्ना ने इसे अस्वीकार करते हुये कहा कि मुस्लिम लीग ही एकमात्र मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है । वे चाहते थे कि कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद के पांचों सदस्य मुस्लिम लीग के हो । कांग्रेस ने जिन्ना की मांग अस्वीकार कर दी क्योंकि इसे स्वीकार करने का अर्थ होता कि कांग्रेस एक हिन्दू संस्था हैं । और यह उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती है । इस तरह जिन्ना की हठधर्मी से शिमला सम्मेलन असफल हो गया ।[79]

14 जुलाई 1945 को जब वाइसराय ने सम्मेलन की असफलता की घोषणा की तो इसकी प्रतिक्रिया के रूप में निराशा का नहीं वरन् जिन्ना के अनुचित व्यवहार के प्रति रोष का वातावरण अधिक था । प्रत्यक्ष रूप से लीग व उसके प्रतिनिधि ही सम्मेलन की असफलता के लिये दोषी थे ।[80]

---

79. पायनियर - 9 जुलाई 1945, पृ0 1

80. शर्मा, लीलाधर पर्वतीय - स्वतंत्रता की पूर्व सन्ध्या - पृ0 180

ब्रिटिश सरकार ऐसे किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था जिसमें मुस्लिम लीग एक पक्ष न हो। इस समय फूट डालो और राज करो की नीति अपने शिखर पर थी।[81]

शिमला सम्मेलन की असफलता से समझौते के प्रयासों का अन्त नहीं हुआ। जुलाई 1945 में इंग्लैण्ड में हुये आम चुनाव में मजदूर दल को आशातीत सफलता मिली। इस दल की सरकार ने लार्ड वेवेल को भारतीय समस्या पर विचार करने के लिये लंदन बुलाया। इस परामर्श के बाद लार्ड वेवेल ने भारत आने पर 19 सितम्बर 1945 को एक घोषणा की। इसी दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भी इंग्लैण्ड में इसी प्रकार की घोषणा की।

प्रधानमंत्री व वायसराय की घोषणाओं में कहा गया कि 1945 के शीतकाल में वे निर्वाचन होंगे जो विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिये गये थे, केन्द्र और प्रान्तों में व्यवस्थापिका सभाओं का पुनर्निर्माण होगा। सरकार ने आशा व्यक्त की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रांतीय मंत्रिमंडलों के संचालन का उत्तरदायित्व निभायेंगे। सरकार ने यह भी निश्चित कर दिया कि भारत के लिये भारतीयों द्वारा शीघ्र एक संविधान का निर्माण किया जायेगा तथा निर्वाचन के बाद ही भारतीय राजनीतिज्ञ क्रिप्स योजना अथवा उसके स्थान पर अन्य किसी संभावित योजना पर विचार करेंगे। 23 सितम्बर 1945 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वायसराय की घोषणा पर विचार किया तथा एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेस द्वारा आगामी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।[82]

---

81. विपिनचंद्र, त्रिपाठी अमलेश व दे बरुण- स्वतंत्रता संग्राम - पृ0 219
82. आज - 26 सितम्बर 1945, पृ0 4

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसार संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने 6 अक्टूबर 1945 को अपनी लखनऊ की बैठक में चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया ।[83] कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के लिये कांग्रेस को वोट देने की अपील की गयी ।[84] कांग्रेस के विशिष्ट नेताओं ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा किया तथा जन सभाओं को सम्बोधित करते हुये जनता से कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की ।

इस समय आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर सैनिक कानून के अन्तर्गत चलाये जा रहे राजद्रोह के मुकदमें ने राष्ट्र का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया । आजाद हिन्द फौज के जिन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था उनमें शाहनवाज, जी० के० सहगल, गुरुबक्श सिंह ढिल्लों मुख्य थे । कांग्रेस ने इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध किया । संयुक्त प्रान्त कांग्रेस कमेटी ने 6 अक्टूबर 1945 को इन अधिकारियों की रिहाई का प्रस्ताव पास किया । इन अधिकारियों के समर्थन में पूर्वी जिलों में जुलूस निकाले गये, शान्ति पूर्ण सभाओं का आयोजन हुआ तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे इस मुकदमें की कटु आलोचना करते हुये अधिकारियों को अविलम्ब रिहा करने की माँग की गयी ।[85]

83• पायनियर – 8 अक्टूबर 1945 – पृ० 3

84• लीडर – 12 दिसम्बर 1945 – पृ० 1

85• गुप्तचर विभाग के अभिलेख

वाराणसी में 1 नवम्बर 1945 को आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कोष में धन दिया गया ।[86]

सैनिक न्यायालय ने इन तीन अधिकारियों को आजन्म कारावास का दण्ड दिया पर ब्रिटिश सरकार जनमत के विरोध के भय से इस निर्णय को कार्यान्वित करने का साहस नहीं कर सकी । वाइसराय ने अपनी विशेष शक्तियों के अन्तर्गत इनको क्षमादान दे दिया । आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर चलाये इस मुकदमें ने कांग्रेस की प्रतिष्ठा को और बढाया ।[87]

1945-46 की शीत ऋतु में सैनिक सेनाओं में भी विद्रोह फैला । यह प्रवृत्ति कलकत्ता के निकट दमदम, भारत के दूसरे हवाई अड्डों तथा सिंगापुर में स्थित वायु सेना में उत्पन्न हुया । इसके बाद भारतीय वायु सेना के अनेक सैनिकों द्वारा भूख हड़ताल की गयी । इसी समय भारत की स्थल सेना में भी अनुशासनहीनता की घटनायें हुयीं । 18 फरवरी 1946 को जल सेना के भी स्पष्ट विरोध कर देने से स्थिति चिन्ताजनक हो गयी ।

इस भीषण विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिये सरकार को अँग्रेज सेना बुलानी पड़ी । कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, परन्तु बाद में कुछ कांग्रेसी नेताओं के हस्तक्षेप से ही स्थिति शान्त हुयी । इन उपद्रवों ने ब्रिटिश सम्मान को आघात पहुँचाया और यह स्पष्ट कर दिया कि

---

86. आज, 3 जनवरी 1946 - पृ0 4
87. दुर्गादास - भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात् - पृ0 235

कि वे अब भारत को अधिक समय तक पराधीन नहीं रख सकेंगी ।[88]

1946 में निश्चित समय पर व्यवस्थापिका सभा के चुनाव हुये । संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के कुल सदस्यों की संख्या 228 थी इसमें 66 मुस्लिम तथा 144 हिन्दू सीटें थीं ।[89] कांग्रेस सभी हिन्दू सीटों पर विजयी रही । लीग को 66 में से 54 स्थान ही मिले । पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली । यह स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों पर मुस्लिम लीग का प्रभाव अधिक है । मुस्लिम लीग के नेताओं का यह कथन सही सिद्ध हुआ कि कांग्रेस हिन्दुओं की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है । अबुल कलाम आजाद ने एक बार फिर प्रान्तीय राजनीति में हस्तक्षेप कर के मुस्लिम लीग व कांग्रेस का संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाने का प्रयास किया पर चौधरी खलीकुज्जमा की हठधर्मी ने उनका प्रयास विफल कर दिया ।[90]

1 अप्रैल 1946 को संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस मंत्रिमण्डल का गठन हुआ ।[91]

कांग्रेस सरकार ने पद ग्रहण करते ही संयुक्त प्रान्त में राष्ट्रीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया तथा राजनीतिक बन्दियों को रिहा करने का आदेश दिया । राजनीतिक बन्दियों की रिहाई के प्रश्न पर कांग्रेस सरकार व गवर्नर में मतभेद हो गया । ~~बाद में नैनीताल में~~

---

88. आज - 7 अप्रैल 1946 पृ0 4
89. पायनियर - 14 मार्च 1946 पृ0 1
90. पायनियर - 14 मार्च 1946 - पृ0 9
91. पायनियर - 2 अप्रैल 1946 - पृ0 1

बाद में नैनीताल में कांग्रेस नेता गोविन्द बल्लभ पन्त तथा संयुक्त प्रान्त गवर्नर के विचार विमर्श से दोनों में एक सफल समझौता हुआ इसके अनुसार राजनीतिक बन्दी रिहा कर दिये गये तथा फरार व्यक्तियों को बन्दी बनाने का आदेश रद्द कर दिया गया ।

19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री लार्ड पैथिक लारेंस ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में स्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन करने संविधान सभा की स्थापना तथा भारत के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारिणी परिषद के निर्माण में सहायता करने के लिये एक कैबिनेट मिशन भेजेगी । 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय समस्या के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की । इसमें भारतीयों के आत्म निर्णय के अधिकार और स्वयं संविधान बनाने के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया । यह कहा गया कि यद्यपि अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जायेगी, पर अल्प संख्यकों को बहुसंख्यक वर्ग के आगे निषेधाधिकार नहीं दिया जायेगा ।

24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया । इसके अध्यक्ष स्वयं भारत मंत्री लार्ड पैथिक लारेंस थे । इसके दो अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा ए0वी0 अलेक्जेंडर थे । कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया तथा इनके साथ कई सम्मेलन किये । कांग्रेस व मुस्लिम लीग के राजनीतिक उद्देश्यों की भिन्नता ने इनमें किसी प्रकार का भी समझौता असम्भव बना दिया । 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना निर्णय घोषित किया । इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं ।[92]

---

92. डा0 ईश्वरी प्रसाद - अर्वाचीन भारत का इतिहास, पृ0 549-550

1. भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतें शामिल होंगी जो वैदेशिक सम्बन्धों, रक्षा व यातायात का कार्य संभालेंगा। इसे आवश्यक कर वसूल करने का भी अधिकार होगा।

2. किसी प्रधान साम्प्रदायिक समस्या का प्रश्न यूनियन की व्यवस्थापिका में उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत तथा दोनों प्रधान सम्प्रदायों के मतों व सभी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से हल होगा।

3. संघ के विषयों के अतिरिक्त सभी विषय व शेषाधिकार प्रान्तों को प्राप्त होंगे।

4. प्रान्तों को स्वतंत्रता होगी कि वे कार्यकारिणी व व्यवस्थापिका सहित अपने वर्ग बना सके और इस प्रकार का प्रत्येक वर्ग सर्वसामान्य समझे जाने वाले विषयों का चुनाव कर सकेगा। निम्न तीन वर्ग बन सकेंगे -
(क) मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रान्त, उड़ीसा,
(ख) पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त व सिंध
(ग) बंगाल व आसाम।

5. संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य होंगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के निम्न सदन के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के ढंग पर करेंगे। रियासतों के सदस्यों का चुनाव परामर्श द्वारा निर्धारित होगा।

6. संविधान सभा तीन भागों में बांटी जायेगी।
(क) मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रान्त, उड़ीसा तथा मुख्य आयुक्तों के 3 प्रान्तों के 190 सदस्य,

(ख) पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त, सिन्ध व बिलोचिस्तान के 93 सदस्य,

(ग) बंगाल व आसाम के 70 सदस्य

7. एक अन्तरिम सरकार स्थापित की जायेगी इसमें प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य होंगे।

8. संविधान सभा इंगलैण्ड के साथ सन्धि करेगी,

9. संविधान के लागू हो जाने के बाद कोई भी प्रान्त अपनी व्यवस्थापिका सभा के मत से उस वर्ग से अलग होने के लिये स्वतंत्र होगा जिसमें उसे रखा गया है।

10. ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर ब्रिटिश क्राउन न तो रियासतों पर अपना प्रमुख रख सकेगा और नहीं भारत में अपनी उत्तराधिकारी सरकार को सौंप सकेगा।

इस मिशन के प्रस्तावों की तरह-तरह की आलोचना की गयी ~~किसी~~ फिर भी सभी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया।[93]

कांग्रेस ने मुसलमानों का पाकिस्तान बनाने का स्पष्ट अधिकार स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन की योजना द्विविध थी। एक तो दीर्घकालिक योजना जिसका सम्बन्ध संविधान सभा से था। दूसरी अल्पकालिक

---

93. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ, यू0 पी0 (1946) पृ0 - 1

योजना जिसमें वाइसराय की मंत्रि परिषद के पुर्नसंगठन पर विचार किया गया था ।

जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव हुये । इसमें कांग्रेस की लोकप्रियता व मान्यता सिद्ध हुयी । 293 सदस्यों में से कांग्रेस पक्ष के 211 सदस्य चुने गये । मुस्लिम लीग 73 स्थान पा सकी । इस चुनाव से लीग को निराशा हुयी । जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को बम्बई में कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिये 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' करने का प्रस्ताव पास किया । इसे प्रारम्भ करने के लिये 16 अगस्त का दिन निश्चित किया गया ।

कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मिशन की योजनायें स्वीकार करने तथा लीग द्वारा अस्वीकार करने पर वाइसराय ने अस्थायी सरकार के निर्माण में सहयोग करने के लिये कांग्रेस व मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया । जिन्ना ने यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और वे 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' की तैयारी में लग गये ।

12 अगस्त 1946 को वाइसराय ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को सरकार के निर्माण के लिये आमंत्रित किया । नेहरू जी ने इसको स्वीकार कर लिया । मुस्लिम लीग को वायसराय द्वारा कांग्रेस को सरकार निर्माण के लिये आमंत्रित करने से घोर निराशा हुयी ।[94]

---

94. आज - 14 अगस्त 1946 - पृ0 4

नेहरू ने अन्तरिम सरकार में लीग से सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की । पर जिन्ना की हठधर्मी के कारण वे सफल नहीं हुये । अन्त में 12 नामों की एक सूची उन्होंने प्रस्तुत की । इसमें उनके अतिरिक्त राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, आसफ अली, शरदचंद्र बोस, जान मथाई, बलदेव सिंह अली जहीर, बल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, सी० एच० भाभा व शफात अहमद खां थे ।[95]

वायसराय ने सूची को स्वीकृति दे दी । इस तरह अन्तरिम सरकार बन गयी ।[96]

संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के नेताओं ने व्यापक दौरा किया ताकि जनता में साम्प्रदायिक भावनायें उत्तेजित की जायें तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को सफल बनाया जाय । वाराणसी में लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गये जुलूस ने हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया । गाजीपुर में लीग के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, दुकाने बन्द करायी, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट की गयी ।[97]

बलिया में निकाले गये जुलूस ने टाउनहाल के फाटक को तोड़ दिया, सम्पत्ति नष्ट की । एक पुस्तकालय के भवन पर से तिरंगा झंडा उतारकर मुस्लिम लीग का झंडा फहरा दिया ।[98]

संयुक्त प्रान्त की सरकार ने जिलाधिकारियों को लीग द्वारा की जा रही उत्तेजनात्मक कार्यवाही को रोकने के लिये विशेष आदेश दिये ।

---

95. दुर्गादास - भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात् - पृ० 242
96. लीडर - 16 अगस्त 1946 - पृ० 1
97. आज, 23 अगस्त 1946, पृ० 4
98. वहीं ;

अन्तरिम सरकार के सदस्यों ने 2 सितम्बर को पद ग्रहण किया। सरकार काम करने लगी। अभी भी मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार में प्रवेश करवाने के प्रयत्न जारी थे। 9सितम्बर 1946 को जिन्ना ने प्रस्ताव रखा कि सारी योजना पर फिर से विचार किया जाय। वैवेल तैयार हो गये तथा जिन्ना के साथ कई बार वार्तालाप किया। परिणामतः मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में भाग लेने को तैयार हो गया।[99]

लीग के पाँच सदस्य लियाकत अली, आई० आई० चुन्दगर, अब्दुल रब्बनश्तर, जोगेन्द्र नाथ मण्डल तथा गजनफर अली अन्तरिम सरकार में शामिल हुये।[100]

शीघ्र ही अन्तरिम सरकार में, कांग्रेस व लीग में मतभेद हो गये। सरकार में लीग ने वाइसराय व कांग्रेस के साथ असहयोग की नीति अपनायी। संविधान सभा में भाग लेने के वाइसराय के निमंत्रण को लीग ने अस्वीकार कर दिया। इस असहयोग से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिये कांग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने लंदन बुलाया। पर यह प्रयास भी प्रयास भी असफल रहा।[101]

---

99. लीलाधर शर्मा, 'पर्वतीय' - स्वतंत्रता की पूर्व संध्या - पृ० 174
100. आज - 28 अक्टूबर 1946 - पृ० 4
101. आज - 8 दिसम्बर 1946 - पृ० 4

6 दिसम्बर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिये 'कार्य पद्धति' की मुस्लिम लीग के अनुसार व्याख्या कर दी, फिर भी लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय नहीं बदला।

इसी परिस्थिति में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि सम्राट की सरकार की हार्दिक इच्छा है कि वह उत्तरदायित्व का सम्पूर्ण भार उनके हाथों में सौंप दे जिनको भारत के सभी दलों द्वारा निर्मित संविधान स्वीकार हो। अतः सम्राट की सरकार स्पष्ट करती है कि जून 1948 तक वह समस्त उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथ में सौंप देगी तथा संसद से भारत में संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान लागू करने की सिफारिश करेगी।

यदि जून 1948 तक इस तरह का संविधान पूर्ण रूप से सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा द्वारा नहीं बनाया गया तो ब्रिटिश सरकार को यह विचार करना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय सरकार की सत्ता किसको दी जाय और क्या यह नई केन्द्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रों में प्रान्तीय सरकारों को या किसी और उचित तरीके से भारतीय जनता के सर्वोच्च हित के लिये दी जाय।[102]

यह भी घोषणा की गयी कि लार्ड वैवेल को भारत से बुला लिया जायेगा व उनके स्थान पर लार्ड माउन्टबैटन को नियुक्त किया जायेगा, वे भारत के अंतिम वायसराय होंगे।

---

102. आज - 22 फरवरी, 1947 - पृ0 1

भारतीय जनमत ने इस घोषणा का स्वागत किया । पर भारतीय नेता इतनी जल्दी सत्ता संभालने के लिये तैयार नहीं थे । साथ ही यह कैबिनेट मिशन की भारतीय एकता को बनाये रखने की घोषणा के विरुद्ध था । सर्वसम्मति से कोई संविधान तैयार न कर सकने की स्थिति में प्रान्तीय सरकारों को शासन सत्ता सौंपने के निर्णय से मुस्लिम लीग का उत्साह बढ़ा ।

23 मार्च 1947 को लार्ड माउन्टबेटेन भारत के वाइसराय बने । उन्होंने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया तथा यह फैसला किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत विभाजन ही भारत की समस्या का समाधान है ।

गृहयुद्ध के भय से भारतीय समस्या के इस दुर्भाग्यपूर्ण समाधान को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया । तत्कालीन परिस्थितियों का निरीक्षण करने के बाद लार्ड माउन्ट बेटेन 18 मई 1947 को ब्रिटिश सरकार से परामर्श करने के लिये लंदन गये । वापस आकर 3 जून 1947 को माउन्ट बेटेन योजना प्रस्तुत की ।[103]

इसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं – ब्रिटिश सरकार भारत का शासन शीघ्र ही ऐसी सरकार को सौंप देगी जिसका निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है । योजना के अन्तर्गत भारतीय समस्या के समाधान

---

103. आज, 11 जून 1947, पृ0 3

के रुप में पाकिस्तान की स्थापना स्वीकार की गयी पर मुस्लिम लीग की माँग के अनुसार सम्पूर्ण बंगाल, पंजाब, आसाम पाकिस्तान में शामिल नहीं लिये गये। पंजाब का कुछ भाग, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त, बंगाल का कुछ भाग, बिलोचिस्तान सिंध व आसाम में सिलहट का जिला जिसमें मुसलमानों का बहुमत था, पाकिस्तान में शामिल किया गया।

इन प्रान्तों में इस प्रश्न पर कि इनका संविधान वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाया जाय या नयी संविधान सभा द्वारा, जनता की इच्छा जानने के लिये यह निश्चित किया गया कि सिन्ध व बिलोचिस्तान की प्रान्तीय व्यवस्थापिकाएं यूरोपीय सदस्यों को अलग कर अपने अपने प्रान्त के लिये इस बात का निश्चय करेगी कि वह किस संविधान सभा में शामिल होगा। उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त व सिलहट के जिले में जनमत संग्रह किया जायेगा तथा पंजाब, बंगाल की प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं की दो भागों में अलग-अलग बैठक होगी जिसमें हिन्दू व मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रतिनिधि निश्चय करेंगे कि वे किस संविधान सभा में शामिल होंगे।

इस समझौते को सभी दलों ने स्वीकार कर लिया। पर इसमें प्रसन्नता किसी को नहीं हुयी। संयुक्त प्रान्त में देश विभाजन पर दुःख प्रकट किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि भारत विभाजन स्वीकार करने से अच्छा है कि हम कुछ दिन के लिये और ब्रिटिश शासन को स्वीकार कर लें। हिन्दू महासभा संयुक्त प्रान्तीय सिख प्रतिनिधि परिषद, समाजवादी दल व फारवर्ड ब्लाक ने भी देश विभाजन की आलोचना की।[104]

---

104. दुर्गादास, भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात, पृ० 260

माउन्टबेटन योजना के प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के रूप में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किये गये, इन्हें 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने अपनी स्वीकृति दे दी ।[105]

15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ तथा भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य अस्तित्व में आये । यद्यपि विभाजन की अपार वेदना से राष्ट्र दुःखी था, लाखों निवासियों के विस्थापित होने तथा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का दुख भी सर्वव्यापी था । फिर भी भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की इस अभिनव घटना ने भारतीयों में अपार प्रसन्नता का संचार किया ।[106]

15 अगस्त 1947 को सारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष में खुशियां मनायी गयी । 15 अगस्त 1947 को ही संयुक्त प्रान्त श्रीमती सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रान्त के प्रथम राज्यपाल के पद की शपथ ली । गोविन्द बल्लभ पंत ने आन्दोलन के दौरान जनता के योगदान का उल्लेख किया तथा इस बात का आश्वासन दिया कि सभी सम्प्रदायों को सुरक्षा, समान अधिकार तथा न्याय दिया जायेगा ।[107]

---

105. पायनियर – 20 जुलाई 1947, पृ0 ।
106. विपिनचंद्र, त्रिपाठी, अमलेश व दे, बरुण – स्वतंत्रता संग्राम – पृ0 222 – 223
107. आज – 19 अगस्त 1947 – पृ0 ।

इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के सत्रह वर्ष पूर्व 31 दिसम्बर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेहरू जी ने तिरंगा फहराते हुये जो घोषणा की थी कि "स्वतंत्रता आन्दोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य संपूर्ण स्वाधीनता होगा", वह पूरा हुआ । 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा तथा राष्ट्र को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की हैसियत से जवाहर लाल नेहरू ने सम्बोधित किया । इस भाषण में उन्होंने कहा -

"वर्षों पहले हमने भाग्यवधू से एक प्रतिज्ञा की थी । अब वह समय आ रहा है जब हम उस प्रतिज्ञा को समग्र रूप में या पूरी तौर पर न सही, काफी दूर तक पूरा करेंगे । रात के बारह बजे जबकि दुनिया नींद की गोद में होती है, भारत नये जीवन और स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा ।"

देश के स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पूरे देश ने भाग लिया था । परन्तु इसमें उत्तर प्रदेश की देन महत्वपूर्ण थी । 1857 से ही पूरा प्रान्त विदेशी शासन के विरुद्ध खड़ा हो गया था ।

1944 से 1947 के काल में इस प्रान्त में महत्वपूर्ण घटनायें नहीं हुयीं । इसका कारण यह था कि यह अवधि संवैधानिक प्रगति की थी । इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र उल्लेखनीय घटना थी - 1946 में हुये निर्वाचन में कांग्रेस की शानदार जीत । यहां की अधिकांश जनता ने देश के बंटवारे का विरोध किया ।

सिंहावलोकन

विदेशी शासन से मुक्त होने के लिये सारे देश ने संघर्ष किया था। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के परिणामस्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का स्वप्न साकार हुआ। यदि नेताओं के नेतृत्व ने आत्मत्याग, बलिदान देश प्रेम का सन्देश प्रसारित किया था तो स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं का बलिदान भी उत्कृष्ट देश प्रेम को प्रदर्शित करता था। इस समय देश का कोई भी ऐसा भाग नहीं था, जहाँ पर जनसाधारण कांग्रेस के कार्यक्रमों को पूरे जोश के साथ पालन नहीं किया जा रहा था।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐसा ही एक जिला गोरखपुर था। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में बड़े से बड़ा बलिदान करने में वह पीछे नहीं रहा। जिले के पूर्व में सारन और चम्पारन जिले, पश्चिम में बस्ती जिला, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में घाघरा नदी है।

जिले के नामकरण के सम्बन्ध में अनेक मत प्रचलित हैं। अधिकांश लोगों का मत है कि पंजाब से आये प्रसिद्ध सन्यासी गोरखपुर के नाम पर जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। उन्होंने यहाँ पर 'गोरक्ष' देवी का मन्दिर बनवाया था।

अनेक सामाजिक, आर्थिक व प्राकृतिक कारणों से यहाँ पर राजनीतिक सक्रियता अपेक्षाकृत कुछ देर से आयी। महाकाव्यों के काल में कारूपथ के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र आर्य सभ्यता व संस्कृति

का केन्द्र था । बौद्ध धर्म को यहां पर संरक्षण मिला । मौर्यों, लिच्छवियों व गुप्तों ने यहां पर शासन किया था ।

12वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के अन्त तक यहां का इतिहास मुख्य से क्षत्रिय जातियों का इतिहास है । मुगल वंश के शासन काल के दौरान इस क्षेत्र ने अकबर के समय में अधिकतम विकास किया । शाहजहां के समय में यह जिला सैनिक शासन के सुपुर्द किया गया था । बक्सर के युद्ध के बाद कर्नल हैना को सैनिक दलों का कमान दी गयी । उसे गोरखपुर व बहराइच में राजस्व कर इकट्ठा करने का काम भी सौंपा गया । उसकी निष्ठुरता से यह प्रान्त उजड़ गया था । नवम्बर 1801 में गोरखपुर व बुटवल ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया गया ।

कम्पनी ने आर्थिक प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान दिया । कई अंग्रेज भी जमींदार बनाये गये । ये सभी लोग अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते थे तथा जनता और मजदूरों के साथ इनका व्यवहार अमानुषिक होता था ।

1857 के पहले अंग्रेजी राज ने देश के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया था । इसने अनेक राजवंशों का अन्त किया । जमींदार लोग, जिनका शासन में पहले महत्वपूर्ण भाग होता था, अब मालगुजारी वसूल करने वाले ठेकेदार मात्र रह गये थे । कम्पनी ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार के लिये सहायता व प्रोत्साहन देती थी । देश की राजनैतिक व सैनिक प्रतिभा तो नष्ट हो ही गयी थी, अब धर्म व संस्कृति भी खतरे में थी ।

इन विभिन्न कारणों से जो अशांति थी, वह 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आयी । इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में गोरखपुर पीछे नहीं रहा । पैना गांव, नरहपुर के राजा, महुआडाबर के निवासियों ने खुला विद्रोह किया ।

गोरखपुर जेल से कुछ विचाराधीन कैदियों ने भागने का असफल प्रयास किया । इस समय ब्रिटिश शासन की लाचारी का पता इसी से चलता है कि जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला जज विनयार्ड ने सतासी, गोपालपुर, बांसी, सलेमपुर, तमकुही के राजाओं की परिषद नियुक्त की थी ।

अवध का चौकीदार मुहम्मद हसन कुछ समय के लिये यहां का वास्तविक शासक बन गया था । सर्वत्र हिंसा व अराजकता का वातावरण था । विद्रोहियों ने यूरोपीय अधिकारियों के अधिकांश निवास स्थानों पर लूट पाट कर के आग लगा दी । नेपाल के राजा जंग बहादुर के नेतृत्व में 500 गुरखा सैनिकों की मदद से अंग्रेजों ने विद्रोहियों को मझौली में छोटी गंडक नदी के किनारे 28 दिसम्बर 1857 को हराया तथा 6 जनवरी 1858 को नेपाल राजा का गोरखपुर पर अधिकार हो गया ।

देश के अन्य भागों की तरह गोरखपुर में भी 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम असफल रहा । पर इस का एक लाभ यह हुआ कि इसने जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत की । अधिकांश स्थानों पर जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया था ।

1893 में गोरखपुर में गो-रक्षिणी आन्दोलन चला था । इस आन्दोलन का उद्देश्य गो-हत्या रोकना था । 1887 में इस क्षेत्र के कट्टर हिन्दुओं द्वारा गो-रक्षिणी सभा नामक गुप्त समितियों की स्थापना की थी । यह सभा हिन्दुओं में लोकप्रिय होती जा रही थी । मुसलमानों ने इस पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया तथा इसका विरोध करने का निश्चय किया । इस आन्दोलन ने साम्प्रदायिक झगड़े का रूप धारण किया । मझौली का राजा ने इस आन्दोलन को संरक्षण दिया था । अंग्रेज सरकार द्वारा कड़े कदम उठाने पर यह आन्दोलन रोका जा सका ।

यद्यपि इस आन्दोलन का उद्देश्य अच्छा था, परन्तु इसका परिणाम साम्प्रदायिकता की वृद्धि के रूप में सामने आया । अंग्रेजों की नीति भी यही थी कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ न आ पायें । समय के साथ-साथ यह समस्या गम्भीर ही हुयी ।

गांधी जी द्वारा 1921 में खिलाफत, पंजाब के अन्याय तथा स्वराज्य की मांग को ले कर असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया गया । 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो भीषण हत्याकाण्ड हुआ था, उसके विरोध में प्रबल आन्दोलन चला था । गोरखपुर में भी हड़तालें हुयीं, सभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गये । रघुपति सहाय फिराक ने डिप्टी कलेक्टरी का पद छोड़ दिया । असहयोग आन्दोलन के दौरान अदालतों, स्कूलों और कालेजों के बहिष्कार पर जोर दिया गया । विदेशी वस्त्र जलाये जाते थे ।

इन सब से यह स्पष्ट है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम द्वारा उत्पन्न हुयी राजनीतिक चेतना इस समय कितनी सक्रिय हो गयी थी । समाज का हर वर्ग विदेशी शासन से मुक्त होने के लिये संघर्षरत था ।

सम्पूर्ण स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण घटना चौरीचौरा काण्ड था । 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरीचौरा नामक स्थान पर हिंसा की जो घटना हुयी, उसने आन्दोलन का स्वरूप ही बदल दिया । इस समय असहयोग आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था । चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के प्रबल पक्षधर थे अतः इस घटना से वे बड़े क्षुब्ध हुये तथा 6 फरवरी 1922 को यह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया ।

यद्यपि कई नेताओं द्वारा गांधी जी के इस कदम की आलोचना की गयी परन्तु एक तरह से यह ठीक ही हुआ कि यह आन्दोलन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया । सम्भव था कि हिंसा की कुछ और घटनायें घटित होती तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी कानून पास किये जाते । परिणाम स्वरूप आन्दोलनकर्ताओं का सख्ती से दमन किया जाता । यह सारी स्थिति आन्दोलनकारियों के मनोबल को कम करती तथा आन्दोलन की गति में कमी हो जाती ।

1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति का देश भर में व्यापक विरोध हुआ । गोरखपुर में विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया गया । सारे जिले में काले झण्डे दिखायें गये तथा प्रदर्शन किये गये । 31 दिसम्बर 1929 को रात बारह बजे रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित किया गया । 26 जनवरी 1930 को सारे देश में यह प्रतिज्ञा दोहरायी गयी । 5 अप्रैल को समुद्र के जल से नमक बना कर कानून तोड़ा गया ।

इन सब घटनाओं से गोरखपुर अप्रभावित नहीं रहा । यहां जुलूस निकाले गये, शराब की दुकानों पर धरना दिया जाता था । ताड़ के पेड़ काट कर ब्रिटिश सरकार के राजस्व को हानि पहुंचायी जाती थी । विदेशी सामान का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली सार्वजनिक रूप से जलायी जाती थी । हाथ के बने खादी के वस्त्र उपयोग में लाये जाते थे ।

यह सब घटनायें इस ओर संकेत करती हैं कि इस समय (1931-41) यहां का आम आदमी विदेशी शासन की समाप्ति के लिये कटिबद्ध था । स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलनों से सरकारी अधिकारी परेशान हो गये थे । चौरी चौरा काण्ड से गोरखपुर के कार्यकर्ताओं को अपार

कष्ट हुआ था । इसीलिये अब वे पूर्णतया अहिंसाव्रत का पालन कर रहे थे । इसका प्रमाण सनहा गांव के आन्दोलन से मिलता है । इस पूरे आन्दोलन में सत्याग्रहियों ने असह्य अत्याचार सहे परन्तु वे सभी अन्त तक अहिंसक बने रहे ।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन लोकप्रिय हो रहा था । सरकार का दमन चक्र भी जारी था । इस बीच दो गोल मेज सम्मेलन हुये, दूसरे गोल मेज सम्मेलन की असफलता के बाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः शुरू किया गया । पर धीरे-धीरे आन्दोलन कमजोर पड़ता गया तथा 1934 में समस्त समाप्त हो गया । तीसरा गोल मेज सम्मेलन भी निराशाजनक रहा ।

1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू किया गया । इसमें 'करो या मरो' का नारा दिया गया । कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि यदि सरकार तत्काल ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग स्वीकार नहीं करती है तो समिति अहिंसक ढंग से जहां तक सम्भव हो सके, व्यापक धरातल पर जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है । जो अनिवार्यतः गांधी जी के नेतृत्व में होगा । 9 अगस्त की सुबह गांधी जी व अन्य महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिये गये ।

नेताओं की गिरफ्तारी से जनता में रोष भड़क उठा । लगभग हर बड़े शहर में प्रदर्शन हुये । 1942 के आन्दोलन में मुख्य रूप से छात्रों, श्रमिकों दुकानदारों व घर की महिलाओं ने भाग लिया था । पूर्वी उत्तर प्रदेश में सन् 42 की क्रान्ति का नेतृत्व गोरखपुर ने किया ।

जिले में हर जगह हड़तालों, विरोधी सभाओं, जुलूसों का आयोजन किया गया। कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 144 का हर जगह उल्लंघन किया गया। 16 अगस्त 1942 को शिब्बन लाल सक्सेना ने बचे-खुचे कार्यकर्ताओं की मदद से आन्दोलन की योजना बनायी। पूरे जिले में रेल की पटरियां उखाड़ने व व्यर्थ करने का निश्चय किया गया। थानों, डाकखानों, सरकारी खजानों पर भी कब्जा करने का लक्ष्य था।

यद्यपि पुलिस द्वारा इनका बड़ी कठोरता से दमन किया गया, पर इस आन्दोलन के दौरान यहाँ की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में अब ब्रिटिश शासन नहीं चल सकता है। जनता द्वारा जिस साहस व शान्ति का प्रदर्शन किया गया, वह सराहनीय है।

1943-47 तक का समय संवैधानिक प्रगति का था। यही कारण है कि इस काल में न केवल गोरखपुर वरन् देश के अन्य स्थानों पर भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुयी।

स्थानीय पत्रकारिता के जन साधारण को स्वतंत्रता आन्दोलन के लिये प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। सर्वाधिक स्तुत्य कार्य पं० दशरथ प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने 'स्वदेश' नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से 1919 से ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। इसके संपादकों पर मुकदमा भी चलाया गया, परन्तु देशभक्ति की भावना से प्रेरित इन वीरों ने अपना कार्य जारी रखा। इसके अतिरिक्त 'क्षत्रिय' 'जीवन', 'वसुन्धरा', 'कल्याण' नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होता था। इन सभी का एकमात्र उद्देश्य था जनता में राजनीतिक जागृति लाना तथा उसे विदेशी शासन के विरुद्ध खड़ा करना।

अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी से ग्रस्त होते हुये भी यहां की जनता ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया । स्वतंत्रता आन्दोलन ने इस क्षेत्र को न केवल राजनीतिक स्तर पर जागृत किया वरन् यहां के आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक पहलुओं पर भी प्रभाव डाला । कांग्रेस के आन्दोलनों को यहां पर व्यापक समर्थन मिला । सभी का सम्मिलित प्रयास था कि भारत लम्बे समय से चले आ रहे विदेशी शासन से स्वयं को मुक्त कर सका ।

"चौरी चौरा काण्ड के सिलसिले में जिन्हें फांसी दी गयी"

1- अब्दुल्ला उर्फ सुकई : आत्मज श्री गोबर जुलाहा ।
: ग्राम राजधानी, झंगहा, गोरखपुर ।

2- भगवान : आत्मज श्री रामनाथ अहीर ।
: चौरीचौरा, गोरखपुर

3- बिक्रम : आत्मज श्री शिवचरन ।
: ग्राम डुमरी खुर्द, डाक० चौरा, गोरखपुर ।

4- दुधई : आत्मज श्री समशावनभर ।
: ग्राम चौरा, गोरखपुर

5- काशीचरन : आत्मज श्री भगुन ।
: ग्राम चौरा, गोरखपुर ।

6- लाल अहमद : आत्मज श्री हकीम ।
: ग्राम कोटा, चौरा, गोरखपुर

7- लौटू : आत्मज श्री शिवचरन ।
: ग्राम बाले, चौरा, गोरखपुर ।

8- महादेव : आत्मज श्री कुंज बिहारी ।
: मझपुर, चौरा, गोरखपुर

9- लाल बिहारी उर्फ गेन्दू : आत्मज श्री जानकी तिवारी ।
: मोहिया, झंगहा, चौरा, गोरखपुर ।

10- नजर अली : आत्मज श्री हुसैन ।
: ग्राम डुमरी, वौरा, गोरखपुर ।

11- रघुवीर : आत्मज श्री रुद्र सोनार ।
: ग्राम मुण्डेरा बाजार, वौरा, गोरखपुर ।

12- रामलगन : आत्मज श्री शिवटहल ।
: ग्राम पोखर भिंडा, वौरा, गोरखपुर ।

13- सरूप : आत्मज श्री राम टहल ।
: ग्राम मुण्डेरा, बाजार, वौरा, गोरखपुर ।

14- रुदन्ती : आत्मज श्री रामदाहल ।
: ग्राम लक्ष्मन पुर, वौरा, गोरखपुर ।

15- सहदेव : आत्मज श्री जादू कोहार ।
: ग्राम महदेवा, वौरा, गोरखपुर ।

16- रामपति : आत्मज श्री जिउत्त चमार ।
: ग्राम वौरा, गोरखपुर ।

17- रामपति : आत्मज श्री मोहर अहीर ।
:ग्राम रामपुर रकबा, गोरखपुर ।

18- श्याम सुन्दर : आत्मज श्री नारायण मिश्र ।
: ग्राम नदुआ, झंगहा, गोरखपुर ।

19- सीताराम : आत्मज श्री रामफल अहीर ।
: ग्राम बाले, चौरा, गोरखपुर ।

20- इन्द्रजीत : आत्मज श्री भरोसा ।
: ग्राम रामपुर, लकुवां,
: चौरा, गोरखपुर ।

:=:=:=:=:

चौरी चौरा काण्ड के मुकदमें के दौरान जेल में हो दिवंगत

1- नारायण : आत्मज श्री कोदई ।
: डुमरी, चौरा, गोरखपुर ।

2- रघुवीर : आत्मज श्री मथुरा भर ।
: मुण्डेरा बाजार, गोरखपुर ।

3- पुरन्दर : आत्मज श्री भवानी ।
: पकिया, चौरा, गोरखपुर ।

4- सहदेव : आत्मज श्री छोटू पासी ।
: चकिया, चौरा, गोरखपुर ।

5- पाँचू : आत्मज श्री छोटे कहार ।
: डुमरी, चौरा, गोरखपुर ।

:=:=:=:=:

10 फरवरी 1932 के गोपनीय जी0 ओ0 नम्बर 109/111 - 192 के अन्तर्गत सविनय अवज्ञा आन्दोलन या लगानबन्दी आन्दोलन से सम्बन्धित चौथी छात्रों की सूची -

1- कृष्णानन्द	: आत्मज श्री भगवान - उम्र - 19 वर्ष, सेन्ट एन्ड्रूज : कालेज, गोरखपुर का छात्र । गोरखपुर शहर में : बक्शीपुर मुहल्ले का निवासी । {कायस्थ}
2- कुलदीपत	: आत्मज श्री जैसिरी पति - उम्र 18 वर्ष, गवर्नमेन्ट : जुबली हाई स्कूल, गोरखपुर का छात्र । ग्राम कतौरा, : जिला बस्ती का निवासी । {कायस्थ}
3- शिव रतन	: आत्मज श्री श्याम सुन्दर - उम्र 22 वर्ष, सेन्ट एन्ड्रूज : कालेज, गोरखपुर का छात्र । मोहल्ला बसन्तपुर, : गोरखपुर का निवासी । {कायस्थ}
4- रामअछत्तर	: आत्मज श्री रामजनम - उम्र 19 वर्ष । सेन्ट्रल हिन्दू- : कालेज बनारस का छात्र । ग्राम नारायणपुर, : गोरखपुर का निवासी । {शुक्ल}

:=:=:=:=:

"दोहरिया गोलाकाण्ड में शहीद हुये"

1- जेठू प्रसाद	: ग्राम जरपार उर्फ घसरा, गोरखपुर ।
	: दोहरिया गोली काण्ड के सिलसिले में
	: 23 अगस्त 1942 को शहीद हुये ।
2- मुनेश्वर सिंह	: बरईपार सेतरिया, डाक0पाली, गोरखपुर ।
	: दोहरिया गोली काण्ड में 23 अगस्त 1942
	: को शहीद हुये ।
3- जगतबली सोनार	: आत्मज श्री गोपाल सोनार ।
	: पाली, गोरखपुर ।
	: दोहरिया गोली काण्ड के सिलसिले में
	: 23 अगस्त 1942 को शहीद हुये ।
4- घिराऊ बरई	: त्रिबिढुरहा, डाक0 पाली, गोरखपुर ।
	: दोहरिया गोलाकाण्ड में 23 अगस्त
	: 1942 को शहीद हुये ।
5- बद्री गड़ेरिया	: ग्राम जोगिया, गोरखपुर । दोहरिया
	: गोलाकाण्ड के सिलसिले में 1942 में शहीद
	: हुये ।

6- रामदास गड़ेरिया : जिला गोरखपुर । दोहरिया गोलीकाण्ड के
: सिलसिले में सन् 1942 में शहीद हुये ।

7- भरौसे केवार : पाली, गोरखपुर । दोहरिया गोली काण्ड
: के सिलसिले में सन् 1942 में शहीद हुये ।

:=:=:=:=:

"जिले के समर्पित स्वतंत्रता सेनानी"

1- श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी-

गोरखपुर के डोहरिया (मझगांवा) के साधारण परिवार में दशरथ प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन् 1891 में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा गोरखपुर तथा इलाहाबाद में सम्पन्न हुयी। वे थानेदारी के प्रशिक्षण हेतु मुरादाबाद जा रहे थे कि लखनऊ में इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी का भाषण सुना। विद्यार्थी जी की वक्तृता से प्रभावित हो कर वे कानपुर चले गये जहाँ 'प्रताप' के संपादकीय विभाग में काम किया। पत्रकारिता का प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी जी के आदेशानुसार 'स्वदेश' का प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने पूर्वी जनपदों के जनसाधारण में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की।

स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें लगभग 10 वर्षों तक जेल की यातना भुगतना पड़ा। सन् 1952 - 57 तक लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। गोरखपुर जिला विकास संघ, बाढ़ सहायता समिति तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के पदाधिकारी के रूप में पूर्वांचल की अविस्मरणीय सेवायें की।

2- बाबा राघवदास -

12 दिसम्बर 1896 में महाराष्ट्र में जन्म लेकर इन्होंने पूर्वांचल की सेवा की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विविध साप्ताहिक और दैनिक पत्रों के प्रकाशन एवं संपादन में इनका अमूल्य योगदान था। गोरखपुर के

ऐतिहासिक पत्र 'कल्याण' के पल्लवित व पुष्पित बनाने में उनका अविस्मरणीय योगदान था । इनकी प्रेरणा से पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिन्दी पत्रों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना प्राप्त होती थी ।

3- रघुपति सहाय फिराक -

श्री गोरखप्रसाद जी वकील के सुपुत्र श्री रघुपति सहाय अपने विद्यार्थी जीवन में एक मेधावी छात्र थे । अपनी प्रतिभा के बल पर डिप्टी कलेक्टरी का पद प्राप्त किया । घर की हालत अच्छी न होते हुये भी उन्होंने श्रम व प्रतिभा से अर्जित पद छोड़ कर युवकों के लिये एक अद्भुत आदर्श उपस्थित किया । 1921 के असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया । 18 मास की कड़ी कैद तथा 500 रुपये जुर्माने की सजा पायी ।

4- बाबू विन्ध्यवासिनी प्रसाद -

ये गोरखपुर में कांग्रेस के संस्थापकों में प्रमुख थे । जिले के मुख्य नेता थे । असहयोग आन्दोलन में अत्यधिक उत्साहपूर्वक भाग लेने के कारण 1921 में 18 मास की कड़ी कैद तथा 500 रुपये जुर्माने की सजा पायी । सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान भी आन्दोलन में 1932 में पहले जत्थे का नेतृत्व किया ।

5- अक्षयवर सिंह -

स्कूल छोड़ कर असहयोग आन्दोलन में भाग लिया । 1930 में नमक सत्याग्रह का संचालन किया । व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन का संचालन करने के कारण भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत सजा मिली । 1942 में 18 मास नजरबन्द रहे । सन् 1946 से 1967 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे ।

6- सिंहासन सिंह -

नमक सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान 1930 में सत्याग्रह किये। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान आन्दोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आन्दोलन में 15 मास नजर बन्द रहे।

7- डा0 शिव रतन लाल -

सक्रिय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान सन् 1932 में 6 मास की सजा पाया। युद्ध विरोधी भाषण देने के आरोप में 1941 में एक वर्ष की सजा पाया। ये जिले के कर्म0 कार्यकर्ता थे तथा कविता व होम्योपैथी में इनकी विशिष्टता सर्वविदित थी।

8- भृगुनाथ चतुर्वेदी -

व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान सन् 1941 में 1 वर्ष कैद तथा 250 रुपये जुर्माना हुआ। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान नजरबन्द रहे।

9- केशभान राय -

इन्होंने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान सक्रिय भाग लिया तथा कारावास व जुर्माने की सजा पायी। 15 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

10- श्यामाचरण शास्त्री -

जिले के सक्रिय कार्यकर्ता थे 1930 से प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया । अनेक बार जेल गये । 1931 से 1938 तक जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री रहे । प्रान्तीय भूदान यज्ञ समिति के मंत्री और अखिल भारत सर्व सेवा संघ के कार्यालय मंत्री, व खादी ग्रामोद्योग के कार्य में संलग्न रहे ।

11- डा० विश्वनाथ मुकर्जी -

गोरखपुर के लोकप्रिय नेता थे । कांग्रेस का गोरखपुर में स्थापना करने वालों में प्रमुख थे । असहयोग आन्दोलन में 1920-21 में दो वर्ष कैद की सजा पायी । 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के सिलसिले में पकड़े गये, 4वर्ष जेल में रहे । जेल से मुक्त होने के बाद किसान व मजदूर सभा तथा रेलवे यूनियन का संगठन किया । प्रथम आम-चुनाव में विधान सभा के सदस्य थे ।

12- महावीर प्रसाद पोद्दार -

1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया । 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में 1वर्ष की कड़ी कैद तथा 100रूपये का जुर्माना हुआ । 1942 में 18 मास के लिये नजरबन्द रहे । 150बीघे का फार्म जब्त कर के कुड़ा घाट हवाई अड्डा बनवाया गया था ।

13- द्वारिका प्रसाद पाण्डे -

1920 में असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। 1922 में चौरा चौरा काण्ड में नेतृत्व के आरोप में फांसी की सजा पायी। बाद में फांसी की सजा कालेपानी में बदल गयी। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान ढाई वर्ष नैनी सेन्ट्रल जेल में नजरबन्द रहे। सन् 1945 के जिला बोर्ड के प्रथम चुनाव में निर्विरोध सदस्य चुने गये। 1952-67 तक विधान सभा के सदस्य रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वर्षों तक सदस्य रहे। बी०एन०डब्लू०, रेलवे मेन्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी तथा किसान मजदूर सभा के संस्थापक सदस्य भी थे। सन् 1972 में भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त को रजत जयंती के उपलक्ष्य में ताम्र पत्र भेंट किया गया।

14- जामिन अली -

ये साम्यवादी विचारधारा के कार्यकर्ता थे। शुरू से उग्र विचारों के थे। 1934 में सर्वप्रथम आइजट ब्रिज पर रिवाल्वर सहित पकड़े गये, साढ़े तीन वर्ष की सजा मिली। पिपराडाह ट्रेन डकैती में 1938 को पकड़े गये तथा 27 जनवरी 1939 को 10 वर्ष की कड़ी कैद तथा 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गयी। 23 जनवरी 1947 को छोड़ दिये गये।

15- जितेन्द्र नाथ सन्याल -

15 वर्ष की अल्पायु से ही बंगाल की क्रान्तिकारी पार्टी से सम्बद्ध रहे। बनारस षड्यंत्र केस में 2 वर्ष की सजा मिली। छूटने के कुछ समय बाद आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण पुनः 2 वर्ष की सजा पायी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान सी० आई० डी० की निगरानी में रहे।

:=:=:=:=:=:

सरकारी रिपोर्ट्स

- ﴾1﴿ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट ।
- ﴾2﴿ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ।
- ﴾3﴿ गृह - पुलिस विभाग ।
- ﴾4﴿ एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यूनाइटेड प्राविन्सेज ﴾1946﴿
- ﴾5﴿ पुलिस विभाग ।
- ﴾6﴿ गुप्तचर विभाग के अभिलेख, ﴾1944﴿
- ﴾7﴿ कान्फीडेन्शियल रिकार्ड्स ।

:=:=:=:=:=:=:=:

'सहायक ग्रन्थ'- "हिन्दी पुस्तकें"

1- [illegible] कुमार - : बाबा राघवदास स्मृति ग्रन्थ ।
: वाराणसी, 1963 ।

2- आचार्य चतुरसेन - : हमारे लाल दिन, दिल्ली,1949 ।

3- गुप्त ., मन्मथनाथ - : राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास ।
: आगरा, 1962 ।

4- गुप्त, मन्मथनाथ - : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन
: का इतिहास । दिल्ली,1960 ।

5- गुप्त, मन्मथनाथ - : भारत में सशस्त्र क्रान्ति चेष्टा का
: रोमांचकारी इतिहास । प्रयाग,1948 ।

6- ब्रजकृष्ण चांदीवाला- : गांधी जी की दिल्ली डायरी (तथा दिल्ली का
: स्वतंत्रता संग्राम) खण्ड 1, खण्ड 2,
: दिल्ली 1969, 1970 ।

7- गांधी,संस्मरण व विचार-: प्रकाशक-सस्ता साहित्य मंडल ।
: नई दिल्ली, 1968 ।

8- सम्पूर्ण गांधी वांङ्मय-: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार ।

9- चतुर्वेदी, बनारसी दास-: महापुरुषों की खोज में ।
: नई दिल्ली, 1983 ।

10- चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद-: हमारे देश के राज्य, उत्तर प्रदेश ।
: प्रकाशन विभाग, 1971 ।

11- डा० सम्पूर्णानन्द - : कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार ।
: वाराणसी, 1962 ।

12- डा० ईश्वरी प्रसाद - : अर्वाचीन भारत का इतिहास ।

13- डा० ताराचंद - : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का
: इतिहास, खण्ड 1 व खण्ड 2

14- ठाकुर, केशव कुमार - : भारत में अंग्रेजी राज्य के दो सौ वर्ष ।
: इलाहाबाद, 1952 ।

15- तिवारी, डा० अर्जुन - : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन व हिन्दी
: पत्रकारिता (पू० उ०प्र० के सन्दर्भ में)
: वाराणसी, 1982 ।

16- तिवारी, उमाशंकर लाल-: भारत सन् 57 के बाद । वाराणसी ।

17- दुर्गादास - : भारत कर्जन से नेहरू व उसके बाद ।

18- नेहरू, जवाहर लाल - : मेरी कहानी । नई दिल्ली, 1946 ।

19- नेहरू, जवाहर लाल - : विश्व इतिहास की एक झलक ।

20- पाण्डेय, रा० राजबली- : गोरखपुर जनपद व उसकी क्षत्रिय जातियों
: का इतिहास । गोरखपुर, सम्वत् 2003वि० ।

21- मिश्र, कन्हैया लाल प्रभाकर- : उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झाँकी ।
: सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, 1972 ।

22- राठौर, डा०भगवानदास: 1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिन्दी
: साहित्य पर प्रभाव ।
: अजमेर ।

23- यशपाल - : सिंहावलोकन ।

24- राम गोपाल - : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास,
: वाराणसी, 1974 ।

25- राबर्टस, पी०ई० - : ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास,
: दिल्ली, 1955 ।

26- लिमये, मधु - : स्वतंत्रता आन्दोलन की विचारधारा,
: दिल्ली, 1983 ।

विद्यार्थी, रामशरण व गुप्त
27- मन्मथनाथ - : भूले बिसरे क्रान्तिकारी-क्रान्तिकारी,
: का संक्षिप्त इतिहास । नई दिल्ली, 1976

28- विपिन चंद्र, त्रिपाठी
अमलेश व दे, बरुण - : स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली 1972 ।

29- व्यास, दीनानाथ - : अगस्त सन् 42 का महान विप्लव ।
: आगरा, सम्वत् 2003 ।

30- शर्मा, लीलाधर पर्वतीय: स्वतंत्रता की पूर्व संध्या ।

31- सिंह, अयोध्या - : भारत का मुक्ति संग्राम ।
: दिल्ली, 1977 ।

32- सान्याल, शचीन्द्रनाथ- : बन्दी जीवन । दिल्ली, 1963

33- सहाय, गोविन्द - : सन् 42 का विद्रोह ।

34- सुन्दर लाल - : भारत में अंग्रेजी राज्य (तीसरी जिल्द)
: इलाहाबाद, 1938 ।

35- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक- : गोरखपुर, (संक्षिप्त परिचय)

36- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक- : बस्ती, (संक्षिप्त परिचय)

37- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक- : देवरिया । (संक्षिप्त परिचय)

38- संघर्षकालीन नेताओं की जीवनियां:भाग - ।

39- स्वतंत्रता संग्राम : ('आज' कार्यालय वाराणसी द्वारा प्रस्तुत)
: 1971

40- सुमन, रामनाथ - : उत्तर प्रदेश में गांधी जी, सूचना विभाग, उ०प्र०

41- 1921 के असहयोग आन्दोलन की झाँकियाँ ।

अंग्रेजी पुस्तकें

1- आजाद, मौलाना अबुल कलाम-: इंडिया विन्स फ्रीडम । 1959

2- बमफोर्ड, पी० सी० - : हिस्ट्रीज आफ दी नॉन को
: आपरेशन एन्ड खिलाफत मूवमेन्ट्स,
: नई दिल्ली, 1974 ।

3- बेसेन्ट, ऐनी - : हाउ इंडिया रॉट फार फ्रीडम ।
: फ्रीडम । 1915

4- बक्शी, डा० एस० आर० : गांधी एन्ड नॉन को- आपरेशन
: मूवमेन्टस 1920-22 ।
: नई दिल्ली, 1983 ।

5- चट्टोपाध्याय, एच०पी० : दी सिपाय म्यूटिनी 1857-
: ए सोशल स्टडी एन्ड एनालिसिस ।
: कलकत्ता, 1957 ।

6- बत्रा, एस० एन० - : सम अनटोल्ड स्टोरीज ।
: नई दिल्ली, 1979

7- घोष, पी० सी० - : इंडियन नेशनल कांग्रेस,
: 1892- 1909 ।
: कलकत्ता 1960

8- चटर्जी, जे0 सी0- : इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन कान्फ्रेन्स।
: कलकत्ता।

9- चौधरी, सन्ध्या - : गांधी एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया।
: नई दिल्ली, 1984

10- चोपड़ा, डा0पी0एन0- : ट्वर्ड्स फ्रीडम (1937 - 47) खण्ड-1
: एक्सपेरीमेन्ट्स विद प्राविन्शियल ऑटोनामी,
: (1 जनवरी - 31 दिसम्बर 1937)
: नई दिल्ली, 1985।

11- चोपड़ा, डा0 पी0एन0 : हूज, हू ऑफ इंडियन मार्टीयर्स, खण्ड - 2।

12- हचिन्स, फ्रैंसिस जी0- : स्पोन्टेनियस रिवोल्यूशन -
: "दि क्विट इंडिया मूवमेन्ट"।
: हरियाणा, 1971।

13- कम्पाइल्ड इन दी - इनटेलीजेन्स ब्यूरो - होम डिपार्टमेन्ट आफ इंडिया। : टैरेरिज्म इन इंडिया (1917 - 36)
: रिप्रिन्टेड इन 1974।

14- कायस्थ, एस0 एल0 व सिंह, एम0 बी0 - : दी नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ
: इंडिया अंक 24 (वाराणसी-सितम्बर-
: दिसम्बर - 1978)

15- कौर, मनमोहन : रोल ऑफ वीमेन इन दी फ्रीडम मूवमेन्ट
: (1857- 1947) नई दिल्ली, 1968 ।

16- मिश्रा, डा० गोविन्द- : कान्स्टीट्यूशनल डेवलेपमेन्ट एन्ड नेशनल
: मूवमेन्ट इन इंडिया । पटना, 1978 ।

17- रिजवी, ए० ए०- : फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश, ७
: खन्ड - 1 कानपुर, 1957

18- रिजवी, एस०ए०ए०- : फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश ।
: खन्ड - 4 इलाहाबाद ।

19- सेन, सुनील - : पाजेन्ट मूवमेन्ट्स इन इंडिया मिड
: नाइनटीन्थ एन्ड ट्वेन्टियेथ सेंचुरी ।
: नई दिल्ली । 1982 ।

20- त्रिपाठी, आर०एस० : हिस्ट्री ऑफ एन्शायेन्ट इंडिया ।

21- डा० ताराचंद - : हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इंडिया ।
: खन्ड 3- 4, प्रकाशन विभाग
: भारत सरकार, दिल्ली, 1972

22- दासगुप्ता, कल्पना - : वीमेन आन दा इंडियन सीन ।
: नई दिल्ली, 1976

23- बशीर, एम0 व गुप्त- : दा आर्गेनाइजेशन आफ दा गवर्नमेन्ट
ओदित : आफ यू0 पी0 ।
: नई दिल्ली 1970

:=:=:=:=:

गजेटियर

1- नेविल, एच0 आर0 : डिस्ट्रिक्ट गजेटियर - गोरखपुर
: (इलाहाबाद 1909) खन्ड XXXI

2- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दी यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एन्ड अवध - सप्लीमेन्टरी नोट्स एन्ड स्टैटिस्टिक्स अप टू 1931 - 32 खन्ड XXXI ( ) गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1935 ।

3- गोरखपुर सप्लीमेन्टरी नोट्स एन्ड स्टैटिसटिक्स टू वाल्यूम XXXII डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दी यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ एन्ड अवध 1921 ।

4- उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स - गोरखपुर 1985 - इलाहाबाद ।

5- इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया - यूनाइटेड प्राविन्सेज - खन्ड 2 कलकत्ता 1908 ।

6- इंडियन एनुअल रजिस्टर - 1922 - 22 ।

7- इंडियन एनुअल रजिस्टर - 1944 ।

:=:=:=:=:=:

शोध - प्रबन्ध

1- गहलौत, डी० एस० - : पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आन्दोलन : का इतिहास (1920 - 47) : शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।

2- त्रिपाठी, आमोद नाथ- : पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन जीवन में बाबा : राघवदास का योगदान । शोध प्रबन्ध : इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।

3- पाण्डे, राम आधार - : हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ : गोरखपुर - 1813 - 1914 : शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।

:=:=:=:=:

समाचार पत्र

1- पायनियर - : 1880 - 1947 ।

2- लीडर - : 1920 - 1947

3- आज - : 1920 - 1947 ।

:=:=:=:=: